राष्ट्रीय संस्करण

मशहूर डायलॉग के साथ बिग बी ने सराही भारत की जीत >>14

वर्ष 3 अंक 180

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 8 दिसंबर 2019

पृष्ठ 16

BYJU'S The Learning App IAS 2020
COURSES AVAILABLE
IAS/SSC
HINDI & ENGLISH MEDIUM
BATCH STARTS : 9th DECEMBER
JAI BHIM MUKHYAMANTRI PRATIBHA VIKAS YOJANA
FREE COACHING
FOR DELHI STUDENTS
FOR SC/ST/OBC AND GENERAL CATEGORY (EWS)
OFFICE 1 : 1B, Third Floor, Near Karol Bagh Metro Station Gate #8, Pusa Road, New Delhi
OFFICE 2 : Shop No. 19, Vardhaman Central Mall, Nehru Vihar, Delhi
For More Details Call, SMS or Whatsapp to 9873643487

जागरण पड़ताल

टेनरियों पर ताला, फिर भी गंगा में गिर रही गंदगी

कानपुर : उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में टेनरियों के गेट पर ताला है, फिर भी कर्मचारी ड्यूटी पर आ रहे हैं। वाहन में लदकर फिनिश लेदर फैक्ट्रियों से बाहर जा रहा है। सारा काम रोज की तरह हो रहा है। इसी का नतीजा है कि गंगा नदी में गंदगी गिरने का क्रम जारी है। (पेज-11)

रविवार विशेष

कह रहे खुलकर कि नहीं करना विवाह, क्योंकि...

नई दिल्ली : दिल्ली की डॉ. प्रगति सिंह चर्चा में हैं। उनका फेसबुक पेज 'इंडियन एसेस' जेंडर व सेक्सुएलिटी के बेहद जटिल मसलों पर नई बहस छेड़ चुका है। बीबीसी ने प्रगति सिंह को टॉप-100 वुमन लिस्ट में शामिल किया है। (पेज-11)

आनन-फानन नहीं हो सकता न्याय : बोबडे

देश के प्रधान न्यायाधीश बोले, बदले की भावना से किया गया तो मूल चरित्र खो देगा न्याय

जोधपुर, एजेंसियां : हैदराबाद में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपितों के पुलिस मुठभेड़ में मारे की घटना को लेकर उठ रहे सवालों के बीच देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) एसए बोबडे ने बड़ा बयान दिया है। जस्टिस बोबडे ने शनिवार को यहां कहा कि आनन-फानन में कभी भी न्याय नहीं हो सकता और बदले की भावना से न्याय किया जाता है तो वह अपना मूल चरित्र खो देता है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने राजस्थान हाई कोर्ट के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने माना कि देश में हाल की घटनाओं से नई ताकत के साथ पुरानी बहस छिड़ गई है। इसमें कोई संदेह नहींहै कि आपराधिक न्याय प्रणाली को एक मामले के निपटारे में लगने वाले समय को देखते हुए अपनी स्थिति और दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए।

सीजेआइ ने आगे कहा, 'मैं नहीं समझता हूं कि न्याय तत्काल हो सकता है या होना चाहिए। न्याय कभी भी बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि बदले की भावना से न्याय किया जाता है तो वह अपना चरित्र खो देता है।' उन्होंने कहा कि आखिरी समय तक अपराध का निपटारा कानून के तहत ही होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही हैदराबाद पुलिस ने दावा किया था कि महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपित पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस की जवाबी फायरिंग में चारों मारे गए। पुलिस उन्हें जांच के सिलसिले में घटनास्थल पर लेकर गई थी।

न्यायपालिका में स्वयं सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत : सीजेआइ

जस्टिस बोबडे ने कहा कि न्यायपालिका में स्वयं सुधारात्मक कदम उठाए जाने की जरूरत है, लेकिन उसे प्रचारित किया जाए या नहीं, यह बहस का विषय है। उन्होंने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम जजों द्वारा किए गए प्रेस कांफ्रेंस को भी सुधारात्मक कदम बताया। उल्लेखनीय है कि एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में 12 जनवरी, 2018 को जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एमबी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने एक प्रेस कांफ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट में कामकाजी स्थितियों को लेकर सवाल उठाए थे।

जोधपुर हाई कोर्ट के नए भवन के उद्घाटन पर (बाएं से) कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सीजेआइ एसए बोबडे, राज्यपाल कलराज मिश्रा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम अशोक गहलोत। एएनआइ

दुष्कर्म के मामलों के जल्द निपटारे का तंत्र बनाए न्यायपालिका : प्रसाद

जोधपुर, एजेंसियां : केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने हाई कोर्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआइ तथा अन्य वरिष्ठ जजों से दुष्कर्म के मामलों की निगरानी और जल्द निपटारे के लिए तंत्र बनाने का आग्रह किया।

कानून मंत्री ने कहा, देश की महिलाएं पीड़ा और संकट में हैं। वे न्याय मांग रही हैं। सरकार ने इस मामले में मौत की सजा का प्रावधान पहले ही कर दिया है। प्रसाद ने कहा, देश में जघन्य अपराधों की सुनवाई के लिए 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं। महिलाओं व बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा, देश में महिलाओं-बच्चियों संग होने वाली घटनाओं को लेकर गुस्सा है। न्यायपालिका को भी इस गुस्से को समझना चाहिए और जल्द सुनवाई के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। वहीं, पटना में पत्रकारों से बातचीत में प्रसाद ने कहा,बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलों का दो माह के भीतर निपटारा होना चाहिए। इसके लिए वो सभी मुख्यमंत्रियों व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा, मुख्य न्यायाधीशों से वह दुष्कर्म के मामलों को त्वरित निपटारे की अपील करेंगे।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर बल : कानून मंत्री ने कहा, प्रतिभाशाली जजों की भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा कराई जानी चाहिए। कोलेजियम को वकील कोटे से हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करते समय ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके परिवार से पहले कोई वकील नहीं रहा हो।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

सेनाओं पर साइबर हमला अफसर-जवान हुए सतर्क

नई दिल्ली : देश की सेनाओं पर शुक्रवार की देर रात हैकर्स ने साइबर हमला किया। तीनों सेनाओं के साइबर विंग ने आपात चेतावनी देते हुए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को आगाह किया कि अटैचमेंट के साथ 'नोटिस' शीर्षक वाले ईमेल को न खोलें।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने की राह मुश्किल

नई दिल्ली : पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक दर्जन से ज्यादा बार पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने की मांग कर चुके हैं। जीएसटी संग्रह की मौजूदा स्थिति व राज्यों कों क्षतिपूर्ति में हो रही देरी को देखते हुए इस उम्मीद के पूरा होने की संभावना बहुत कम है।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 14

एनबीए ड्राफ्ट में शामिल हो चुके सतनाम डोप टेस्ट में फेल

नई दिल्ली : अमेरिका की बास्केटबॉल लीग एनबीए के ड्राफ्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय सतनाम सिंह भामरा गत माह डोपिंग परीक्षण में विफल रहे जिसके बाद नाडा ने उन्हें अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया।

पहला टी-20
भारत vs वेस्टइंडीज
शाम 7:00 बजे से
स्थान : तिरुवनंतपुरम
प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

संकेत ▶ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं, कई प्रस्ताव विचाराधीन

आयकर में राहत की तैयारी

कहा, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार कई कदमों पर कर रही विचार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आगामी बजट में आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। सितंबर, 2019 में कॉरपोरेट सेक्टर को बड़ी टैक्स राहत देने के बाद सरकार अब आम जनता के लिए आयकर की दर में कटौती पर गंभीरता से विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक बार फिर इस बात के संकेत दिए। एक कार्यक्रम में आर्थिक विकास दर के घटने की बात को स्वीकारते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे पास विकास दर की रफ्तार तेज करने के कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं, इनमें आयकर की दर में कटौती भी एक है। जब यह पूछा गया कि ऐसा कब तक हो सकता है तो उन्होंने जवाब दिया कि बजट तक सभी को इंतजार करना चाहिए। सोमवार को संसद में भी एक मुद्दे पर चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण ने ऐसा संकेत दिया था।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने टैक्स रेट को घटाने के साथ ही कर ढांचे को आम करदाताओं के लिए सुगम बनाने का भी वादा किया। सीतारमण ने कहा, 'टैक्सेशन के बारे में पूछताछ के मौजूदा तरीके को हमने काफी हद तक बदल दिया है। अब यह 'फेसलेस' होता है। हम धीरे-धीरे पूरी व्यवस्था को उत्पीड़न मुक्त बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे प्रक्रिया समझने में आसान होगी और अलग-अलग तरह की छूट के प्रावधानों से मुक्त होगी।'

वित्त मंत्री के इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसकी जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही है। यह मौजूदा आयकर ढांचे में बड़े बदलाव की जमीन तैयार करेगा। पर्सनल टैक्स व्यवस्था में बदलाव के लिए सरकार की ओर से गठित समिति की तरफ से डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) नाम से एक रिपोर्ट दी गई है। इसमें आयकर की दर को नीचे लाने के साथ ही मौजूदा ढांचे को पूरी तरह से बदलने की सिफारिश की गई है। इसमें आय कर में मिलने वाली तमाम तरह की छूट को समाप्त कर उनकी जगह कर की दर को नीचे लाने की मुख्य तौर पर सिफारिश की गई है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों राज्यसभा में डायरेक्ट टैक्स कोड पर भी विचार करने की बात कही थी।

निर्मला सीतारमण फाइल फोटो

इसलिए जरूरी

- आयकर की दर में कमी लाने से घरेलू मांग बढ़ाने में मिलेगी मदद
- आयकर व्यवस्था आसान बनने से कर अनुपालन भी बढ़ने की उम्मीद

यह है खतरा

- राजस्व संग्रह की स्थिति को देखते हुए राजकोषीय घाटा बढ़ने की आशंका

बहुत आसान नहीं है कटौती की राह

वैसे सरकार की इस मंशा की राह में मौजूदा राजकोषीय स्थिति एक बड़ी अड़चन है। केंद्र के खजाने की स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है। कॉरपोरेट टैक्स में कमी से सरकारी खजाने में 1.45 लाख करोड़ रुपये की आमदनी कम होगी। पिछले बजट में पांच लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर भी टैक्स से छूट दे दी गई थी और उसका बोझ पड़ा था। वहीं जीएसटी संग्रह भी उम्मीद से काफी कम है। नवंबर, 2019 तक डायरेक्ट टैक्स संग्रह में पांच फीसद का इजाफा हुआ है। ऐसे में यह देखना होगा कि इनकम टैक्स रेट घटाकर सरकार इसके संग्रह में कमी का कितना खतरा उठाती है। यह कदम राजकोषीय संतुलन को और चुनौतीपूर्ण बना सकता है।

सितंबर में कॉरपोरेट सेक्टर को सरकार ने दी थी छूट

केंद्र ने आर्थिक मंदी के आसार को भांपते हुए सितंबर, 2019 में कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30 से घटाकर 22 फीसद कर दिया था। मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग को बढ़ावा देने वाले इस कदम से भारत अभी दुनिया के सबसे आकर्षक निवेश स्थल के तौर पर उभरा है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक, मंदी के पीछे घरेलू मांग में भारी कमी काफी हद तक जिम्मेदार है। इससे निपटने को इनकम टैक्स रेट घटाना प्रभावी कदम हो सकता है।

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मौत से उप्र में उबाल

- पीड़ित परिवार से मिलीं प्रियंका, प्रदर्शन करते कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज
- विधानसभा के सामने धरने पर बैठे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव
- मायावती पहुंचीं राजभवन, राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा

दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव स्थित गांव में पीड़िता के पिता से मुलाकात करतीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा (लाल रंग के पहनावे में) और पूर्व सांसद अन्नू टंडन (सामने, बाएं)। जागरण

जागरण टीम, लखनऊ

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मौत ने उत्तर प्रदेश में सियासी हंगामा मचा दिया है। शनिवार को सरकार पर हमलावर विपक्षी दल सड़क पर उतर आए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा के सामने धरने पर बैठ गए तो पहली बार बसपा प्रमुख मायावती राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने राजभवन पहुंच गईं। कांग्रेस ने भी सक्रियता दिखाई। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जहां पीड़ित परिवार से मिलने उन्नाव पहुंचीं, वहीं कार्यकर्ताओं ने भाजपा दफ्तर पर धावा बोला और लखनऊ स्थित जीपीओ पर चार घंटे प्रदर्शन किया। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस बीच पीड़िता का शव गांव पहुंच गया। शव देख पिता ने कहा कि हैदराबाद जैसा इंसाफ दो, वरना घर पर बम गिरवा दो।

दुष्कर्म पीड़िता की मौत पर विपक्षी खेमे में खलबली प्रियंका के कदम से शुरू हुई। सुबह वह वरिष्ठ नेताओं संग उन्नाव के लिए रवाना हो गईं। दोपहर 12 बजे गांव पहुंचीं प्रियंका को पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने पीड़ित परिवार से मिलवाया। प्रियंका पीड़िता के पिता और मां को लेकर घर के एक कमरे में चली गईं और पूरे घटनाक्रम की 55 मिनट तक सिलसिलेवार जानकारी ली। बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का कौन सा सुरक्षित ठिकाना है। योगी के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा, उन्नाव की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली तक आवाज उठाएंगे। प्रियंका के इस कदम के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा के गेट नंबर एक के सामने धरने पर बैठ गए।

इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला प्रकोष्ठ के साथ भाजपा मुख्यालय पर धावा बोल दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। इसके बाद कार्यकर्ता जीपीओ पहुंचे और धरना देने लगे। यहां भी लाठीचार्ज हुआ। सभी को हिरासत में ले लिया गया। इसी दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती सवा दो बजे राजभवन पहुंची। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भेंट कर कानून व्यवस्था पर चर्चा की और ज्ञापन सौंपा। सुबह उन्होंने घटना पर ट्वीट भी किया था।

मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर दिलाएंगे सजा : योगी पेज>>5

निर्भया के दोषी विनय की दया याचिका पर खड़ा हुआ विवाद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका पर विवाद खड़ा हो गया है। विनय ने अपने वकील के माध्यम से राष्ट्रपति को एक अर्जी भेजी है, उसमें लिखा है कि उसने कोई दया याचिका नहीं लगाई है। लिहाजा गृह मंत्रालय की ओर से भेजी गई दया याचिका को वापस कर दिया जाए। उधर, जेल प्रशासन ने दावा किया कि विनय की ओर से दी गई दया याचिका ही राष्ट्रपति के पास भेजी गई है।

विनय शर्मा के वकील एपी सिंह ने बताया कि शुक्रवार को वह विनय से मिलने तिहाड़ गए थे। वहां बात की तो पता चला कि उसने कोई याचिका नहीं लगाई है। इसके बाद जेल में ही उसने एक आवेदन लिखा, जिसमें उसने दया याचिका नहीं लगाने और उसके पास सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डालने का विकल्प मौजूद होने की बात लिखी है। अर्जी में दया याचिका पर अपना हस्ताक्षर नहीं होने का भी दावा किया है। एपी सिंह ने कहा कि विनय की सहमति के बाद एक याचिका राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को शनिवार को भेज दी है। सिंह ने कहा, दोषियों विनय और पवन की सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगानी है, साथ ही अक्षय की रिव्यू पिटीशन देनी है। अभी इनके पास विकल्प मौजूद हैं।

जेल के एआइजी राजकुमार ने बताया कि चारों दोषियों को दया याचिका भेजे जाने के बारे में नोटिस दिया गया था। इसके बाद विनय शर्मा ने दया याचिका लगाई थी, जबकि अन्य दोषियों ने कहा था कि अभी उनके पास अन्य विकल्प मौजूद हैं।

कसेगी लगाम

केंद्रीय बैंक ने वित्त मंत्रालय से मांगे हैं प्रबंधन के मामलों में पूरे अधिकार, अभी सहकारी बैंकों पर आरबीआइ के साथ राज्यों का भी रहता है नियंत्रण

सहकारी बैंकों की कमान चाहता है आरबीआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था के कारण संभव नहीं हो पाती है पर्याप्त निगरानी

पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक में सामने आए भारी घोटाले के बाद से सहकारी क्षेत्र के बैंकों पर नियंत्रण को लेकर आवाजें उठ रही हैं। इस सेक्टर पर लगाम कसने और बेहतर निगरानी के लिए उच्च स्तर पर विमर्श भी चल रहा है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए रिजर्व बैंक ने अब इस सेक्टर की लगाम अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय बैंक ने वित्त मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखकर सहकारी बैंकों का पूरा नियंत्रण देने को कहा है। वित्त मंत्रालय के रुख से भी ऐसा लग रहा है कि वह आरबीआइ के इस प्रस्ताव के पक्ष में है। उम्मीद है कि संसद के आगामी बजट सत्र में मौजूदा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बड़े संशोधन कर शहरी सहकारी बैंकों के नियमन की पूरी जिम्मेदारी आरबीआइ को सौंप दी जाए।

वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते संसद को बताया था कि पीएमसी बैंक की घटना के बाद शहरी सरकारी बैंकों के निगरानी तंत्र में बदलाव करने के लिए आरबीआइ से बातचीत की जा रही है। अब यह सूचना आ रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि दोहरे रेगुलेशन की मौजूदा व्यवस्था के चलते शहरी सहकारी बैंकों की निगरानी में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। इन्हें दूर करने का एक ही तरीका है कि देश के दूसरे बैंकिंग सेक्टर की तरह ही इसकी बागडोर भी आरबीआइ को सौंप दी जाए। अभी शहरी सहकारी बैंकों पर आरबीआइ के साथ-साथ राज्यों का भी नियंत्रण है। ऐसा होने से रिजर्व बैंक इनकी पूरी निगरानी करने में सक्षम नहीं हो पाता है। इस दोहरी व्यवस्था को सहकारी बैंकों में होने वाली गड़बड़ियों की एक बड़ी वजह माना जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से केंद्र सरकार को भेजे गए नोट में कहा गया है कि उसे शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंधन की सारी गतिविधियों पर नजर रखने का अधिकार मिले। केंद्रीय बैंक ने जरूरत पड़ने पर प्रबंधन में बदलाव या प्रबंधन को निरस्त कर उसकी जगह अपने अधिकारियों को नियुक्त करने से लेकर इनकी अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों को भी अपने अधिकार में देने की बात कही है। अभी जब शहरी सहकारी बैंक पूरी तरह से विफल हो जाते हैं, तभी आरबीआइ उनके प्रबंधन में हस्तक्षेप करता है, जैसा पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक बैंक के मामले में हुआ है।

प्रतीकात्मक

झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव में छिटपुट हिंसा, एक की मौत

रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण की 20 विधानसभा सीटों पर शनिवार को हुए मतदान के दौरान नक्सलियों ने अपनी धमक दिखाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। छिटपुट हिंसा के बीच दूसरे चरण में 64.39 फीसद मतदान हुआ। बहरागोड़ा सीट पर जहां सर्वाधिक 74.44 फीसद मतदान हुआ, वहीं जमशेदपुर पूर्वी व जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर सबसे कम वोट पड़े हैं। (पेज-4)

पाकिस्तान जैसे पड़ोसी से निपटने को तैयार रहना होगा : राजनाथ

देहरादून : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को राष्ट्र नीति बना लिया है। वहां चरमंपथी तत्व इतने मजबूत हैं कि सियासत के केंद्र में बैठे लोग उनके हाथों की कठपुतलियों से ज्यादा कुछ नहीं लगते। हमें पाक जैसे पड़ोसी से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। चीन पर टिप्पणी करते हुए राजनाथ बोले, भारत व चीन की क्षेत्रीय अवधारणाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन चीन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बाकी दुनिया के साथ खड़ा है। (पेज-6)

टाइगर रिजर्व के पर्यटन स्थलों पर अब रात में नहीं रुक सकेंगे सैलानी

देवेंद्र देवा, पीलीभीत

- एनटीसीए ने जंगल के कोर एरिया में पर्यटकों के ठहरने पर लगाया प्रतिबंध
- जंगल में रोशनी करने या मानवीय गतिविधियों से असहज होते हैं वन्यजीव

देशभर के टाइगर रिजर्व में स्थित पर्यटन स्थलों पर सैलानी अब रात्रि विश्राम नहीं कर सकेंगे। इससे देश-विदेश से जंगल में प्रवास के लिए आने वाले लोगों को निराश होना पड़ेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने जंगल के कोर एरिया में पर्यटकों के रात में ठहरने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर किया है। वजह, रात में जंगल में रोशनी करने या मानवीय गतिविधियों से वन्यजीव असहज होते हैं।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का मानना है कि कोर एरिया में बाघों का वास होता है। ऐसे में वहां पर्यटकों को ठहराया जाना अनुचित है। इसलिए, एनटीसीए ने देशभर के सभी टाइगर रिजर्व को यह आदेश जारी कर दिया है कि कोर एरिया में पर्यटकों की ठहराने की व्यवस्था खत्म की जाए। इस बाबत अक्टूबर में ही पत्र जारी किया जा चुका है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) प्रशासन ने आदेश मिलने के बाद तैयारी शुरू कर दी है। पीटीआर के फील्ड डायरेक्टर डॉ. एच राजामोहन ने कहा, एनपीसीए ने देशभर के सभी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पर्यटकों को ठहराने पर पाबंदी का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि,समय सीमा तय नहीं है।

उन्होंने कहा, एनटीसीए के आदेश का पालन करने के लिए चूका स्पॉट पर पर्यटकों के ठहरने के लिए हट की व्यवस्था खत्म करा दी जाएगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए गेस्ट हाउस बनाने के लिए कई स्थानों पर जमीन देखी गई है। उल्लेखनीय है कि वन्यजीव प्रेमियों और इस संबंध में काम करने वाले विभिन्न संगठन मांग करते रहे हैं कि वन क्षेत्र में मानवीय दखल कम किया जाए, ताकि वन्यजीवों को दिक्कत न हो।

394 एयर इंडेक्स शनिवार को दर्ज किया गया गाजियाबाद में। गुरुग्राम में 362, नोएडा में 388 और ग्रेटर नोएडा में 366 रहा एयर इंडेक्स।

न्यूज गैलरी

एनआरसी को लेकर आप का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन आज

नई दिल्ली : एनआरसी को लेकर दिल्ली में सियासत गरमा गई है। इस मुद्दे पर भाजपा और आप के बीच चल रही खींचतान के बीच आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने रविवार को जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करने की घोषणा की है। आप नेता सिंह ने दावा किया कि पूरे देश में एनआरसी लागू करने की सरकार की योजना उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को निशाना बनाने की साजिश है। इसके विरोध में आप रविवार को जंतर-मंतर पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन का नेतृत्व आप की पूर्वांचल इकाई के प्रमुख गोपाल राय करेंगे। सिंह ने कहा कि अगर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पूरे भारत में लागू होता है तो देश के विभिन्न हिस्सों में दशकों से रह रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग कहां जाएंगे? क्योंकि वह 1971 से पहले अपने स्थानीय निवासी होने को साबित नहीं कर पाएंगे। (जासं)

दिल्ली विवि के शिक्षकों की हड़ताल जारी रहेगी

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) की तरफ से बुधवार को शुरू की गई हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। शिक्षकों ने दिसंबर में हो रही सेमेस्टर परीक्षा के मूल्यांकन का बहिष्कार किया है। शिक्षकों की मांग है कि लंबे समय से काम कर रहे तदर्थ शिक्षकों का समायोजन किया जाए। इन शिक्षकों को स्थायी तौर पर नौकरी दी जाए। डीयू प्रशासन की तरफ से जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। डूटा के उपाध्यक्ष आलोक रंजन पांडेय ने बताया कि कुलपति कार्यालय के पास शिक्षकों ने आमसभा का आयोजन किया। इसमें फैसला हुआ है कि तदर्थ शिक्षकों के समायोजन जब तक नहीं होता है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कई शिक्षक कुलपति कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। शिक्षकों की तरफ से कुलपति कार्यालय के बाहर चादर व दरी बिछाकर और कंबल के साथ धरना देने का प्रयास किया गया। डीयू प्रशासन की तरफ से शिक्षकों से हड़ताल खत्म करने की अपील की जा रही है। (जासं)

सरकारी स्कूलों में लगी दाखिले की होड़ : टोकस

नई दिल्ली : आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र स्थित सर्वोदय विद्यालय में शनिवार को वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक प्रमिला टोकस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचीं। विधायक ने नई दिल्ली जिले में बेस्ट टीचर चुनी गईं मीनाक्षी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विधायक प्रमिला टोकस ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन किया है। पहले लोग बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते थे और बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कराते थे। अब लोगों में सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने को लेकर होड़ मची है। लोग निजी स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करा रहे हैं। (जासं)

सियासत ▸ विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बनाई रणनीति

नेताओं को एकजुटता और जनसंवाद का मिला मंत्र

मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में लोगों को जानकारी देने पर जोर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक, संयोजक व प्रभारियों की तैनाती करने के बाद उन्हें चुनाव प्रबंधन के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक हुई जिसमें अनधिकृत कॉलोनियों में मकान का मालिकाना हक देने, झुग्गीवासियों को पक्का मकान देने, व्यापारियों को सीलिंग से मुक्ति सहित नरेंद्र मोदी सरकार के अन्य कदमों को जोरशोर से उठाने का फैसला किया गया।

पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दिल्ली के नेताओं को एकजुट होने और विधानसभा स्तर पर रणनीति बनाकर चुनाव प्रचार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता विपरीत परिस्थितियों में अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कला में माहिर हैं। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने इस कौशल का प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2015 विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को एक भी चुनाव जीतने नहीं दिया है। विधानसभा चुनाव में भी यह प्रदर्शन जारी रखना है।

चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि मोदी सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। आप सरकार पांच सालों में इन कॉलोनियों का नक्शा भी नहीं बना सकी। मजबूरन केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी पड़ी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अब तक एक हजार कॉलोनियों के नक्शे तैयार कर लिए हैं। लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी न हो इसके लिए डीडीए ने 25 सेंटर खोले हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता को इसकी जानकारी देने के साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान देने की घोषणा की है। झुग्गी झोपड़ी (जेजे) क्लस्टर में सर्वे किया जा रहा है। व्यापारियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने लीज पर चल रही दस लाख दुकानों को फ्री होल्ड करने व 105 बाजारों में 50 हजार से अधिक दुकानदारों का कंवर्जन शुल्क माफ करने का फैसला किया है। पांच लाख घरेलू उद्योगों को भी बड़ी राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को बताया जाना चाहिए कि केंद्र की मोदी सरकार ने क्या किया और दिल्ली की आप सरकार ने किस तरह से धोखा दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि जनता को बताना होगा कि किस तरह से आप सरकार की गलत नीतियों व लापरवाही से दिल्ली में प्रदूषण व दूषित जल की समस्या विकराल हो गई है। स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं। बैठक में राज्यसभा सदस्य विजय गोयल, सांसद रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश साहिब सिंह व गौतम गंभीर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, मिजोरम प्रभारी पवन शर्मा आदि मौजूद रहे।

कहां मिल रहा सस्ता प्याज, हेल्प लाइन नंबर पर करें बात

जासं, नोएडा : प्रशासन ने जनपद निवासियों को सस्ती प्याज खरीदने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। प्रशासन से जारी मंडी समिति सचिव के मोबाइल नंबर 9839593646 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कहां पर सस्ता प्याज मिल रहा है। प्याज मिलने में हो रही परेशानी की शिकायत भी कर सकते हैं। दरअसल, मार्केट में प्याज की कीमत कम होने की अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है। दुकानदार 80 से 100 रुपये किलो प्याज बेच रहे हैं। जनपद निवासियों को राहत देने के लिए प्रशासन तीन पोर्टेबल वैन व तीन सरकारी दुकानों पर 35 से 38 रुपये किलो प्याज बिकवा रहा है। वैन से डोर टू डोर घूम कर प्याज बेचा जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि प्रशासन प्याज की कीमतों पर नजर रखे हुए है। लोगों को पोर्टेबल वैन या सरकारी दुकान पर प्याज खरीदने में परेशानी हो रही है, तो वे जारी हेल्प लाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कहां पर वैन है। प्याज की कीमतों को लेकर दिल्ली-एनसीआर हीं नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों में हंगामा हो रहा है।

जितनी दूरी का सफर उतना ही देना होगा टोल

सौरभ पांडेय, गाजियाबाद

▸ दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस के लिए एनएचएआइ ने तैयार की नई योजना

▸ हापुड़ टोल प्लाजा पर 125 रुपये टोल दे रहे लोगों को मिलेगी राहत

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के बीच हापुड़ टोल प्लाजा पर 125 रुपये टोल दे रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। एक्सप्रेस-वे के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) ने नई योजना तैयार की है। इसके तहत वाहन चालकों को दूरी के हिसाब से टोल देना होगा। एनएचएआइ एक्सप्रेस-वे पर तीन और स्थानों पर टोल प्लाजा बनाने जा रहा है। ऐसे में दिल्ली से मेरठ तक लोगों को 80-100 रुपये का टोल चुकाना होगा।

दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक बन रहे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर अभी सिर्फ हापुड़ के छिजारसी पर टोल चुकाना पड़ता है। गाजियाबाद, पिलखुवा, नोएडा अथवा दिल्ली से जाने वाले सभी वाहन चालकों को एक तरफ से 125 रुपये का टोल देना पड़ता है। ऐसे में उन लोगों को अधिक नुकसान होता है जो कम दूरी की यात्रा करते हैं। इससे राहत दिलाने के लिए एनएचएआइ ने नई योजना तैयार की है। तीन स्थानों पर टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। पहला टोल प्लाजा गाजियाबाद के लाल कुआं, दूसरा ईस्टर्न पेरीफेरल-वे के पास और तीसरा प्लाजा मेरठ के परतापुर के पास बनाया जाएगा।

ईस्टर्न पेरीफेरल-वे की तर्ज पर चुकाना होगा टोल : एक्सप्रेस-वे पर चढ़ने के बाद पहले टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को एंट्री टिकट मिलेगा। वहीं जिस टोल प्लाजा से बाहर निकलेंगे, वहां टोल चुकाना होगा। फास्टैग लागू होने के चलते राशि खुद ब खुद कट जाएगी। अगर कोई व्यक्ति गाजियाबाद से पिलखुवा तक जाता है तो उसे महज लाल कुआं से ईस्टर्न पेरीफेरल-वे तक का टोल चुकाना होगा। एनएचएआइ ने अभी टोल की दरें निर्धारित नहीं की हैं। हालांकि माना जा रहा है कि टोल को वर्तमान दरों से कम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली से मेरठ तक वाहन चालकों को 80 से 100 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं। वर्तमान में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर इसी तरह टोल लिया जाता है।

काम पूरा होने के साथ बनेंगे टोल प्लाजा : एनएचएआइ के उप महाप्रबंधक मुदित गर्ग ने बताया कि एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही टोल प्लाजा बनाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। टोल प्लाजा बनने के बाद कम दूरी के लिए कम टोल देना होगा। दरें जल्द ही निर्धारित की जाएंगी।

अमरनाथ यात्रा पर शोध कर रहे डॉ. अदफर राशिद शाह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज में कार्यरत रिसर्च असिस्टेंट डॉ. अदफर राशिद शाह 2011 से अमरनाथ यात्रा पर शोध कर रहे हैं। 2013 में अमरनाथ यात्रा शांति निर्माण क्षमता पर लिखा गया शोधपत्र तिब्बत पत्रिका में छपा था। उन्होंने वर्ष 2010 से अमरनाथ यात्रा पर शोध की शुरुआत की थी। अब तक उनके द्वारा अमरनाथ यात्रा पर लिखे गए पांच शोधपत्र छप चुके हैं। मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले के रहने वाले डॉ. अदफर राशिद शाह ने 2010 में पीएचडी पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था। उन्होंने पीएचडी के दौरान मुसलमान तीर्थस्थलों, वक्फ बोर्ड के अधीन आ रहे औकाफ पर अध्ययन किया। इसी दौरान ही उन्हें ख्याल आया कि उनके घर के नजदीक इतना बड़ा तीर्थस्थल है जिसकी मान्यता पूरे विश्व में है, अमरनाथ गुफा व अमरनाथ यात्रा। इसके बाद इस पर सामाजिक महत्व व दृष्टिकोण से अध्ययन शुरू किया। अमरनाथ यात्रा पर अब तक के किए गए शोध कार्यों के लिए इसी वर्ष अमेरिका के दूसरे सबसे पुराने विश्वविद्यालय, विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ पिलग्रेमेज स्टडीज की तरफ से जॉर्ज ग्रीनिया रिसर्च फेलोशिप प्राप्त हुई है। इसी फेलोशिप के तहत डॉ. अदफर को एक हजार डॉलर की नगद राशि भी मिली है। इस फेलोशिप के बाद उन्होंने 'हितधारकों के विचारों और अनुभवों से एक संघर्ष क्षेत्र में तीर्थयात्रा को समझना : कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा का गुणात्मक अध्ययन' विषय को अमेरिकी विश्वविद्यालय के सामने शोध प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया है। अब वह इसी में ही आगे अध्ययन करेंगे।

डॉ राशिद अदफर शाह

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रिसर्च असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं डॉ. शाह, अमेरिका के विश्वविद्यालय से मिली जॉर्ज ग्रीनिया रिसर्च फेलोशिप

डॉ. अदफर राशिद शाह बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा में तीर्थस्थल के साथ ही हमें काफी कुछ सिखाता है। यहां पर एक तरह से मिनी इंडिया बसता है। इसके हर पहलुओं व आयाम को बारीकी से समझकर इस पर अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि अब तक के अपने इस अध्ययन पर एक किताब भी लिखने का निर्णय लिया है।

सिसोदिया बोले शिक्षक ही समाज के वास्तविक पायलट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पांच साल मेहनत करके हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली है। शिक्षा के स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार किया है। आप सभी को दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की बदली हुई तस्वीर को निखारने का काम करना है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को त्यागराज स्टेडियम में यह बातें शिक्षा विभाग में नियुक्त किए गए नए शिक्षकों के साथ संवाद करते हुए कहीं।

नवनियुक्त 7600 शिक्षकों के साथ त्यागराज स्टेडियम में संवाद का आयोजन किया गया था। इसमें मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षक समाज में पायलट होता है। शिक्षा मंत्री से लेकर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका आपको सुविधा देने की है। देश की नई पीढ़ी आपके हाथों में है। शिक्षक होना सिर्फ नौकरी नहीं है, यह बड़ी जिम्मेदारी है। वर्तमान पीढ़ी को जानकारी देकर गतिशील पीढ़ी में बदलने की यात्रा में आप सभी शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सिसोदिया ने शिक्षकों से सवाल-जवाब भी किए। उन्होंने कहा कि समाज व देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। स्कूल की हर एक गतिविधि को अनुशासित तरीके से पूरा कराना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना सब शिक्षकों की ड्यूटी का हिस्सा है।

स्वच्छता अभियान को मिली है कामयाबी : राजनाथ

दिल्ली छावनी में स्वच्छता ही सुरक्षा पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान सड़क से प्लास्टिक की बोतल व कूड़ा उठाकर डस्टबीन में डालते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हरि प्रकाश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से चलाया जा रहा पखवाड़ा

▸ राजनाथ और श्रीपाद ने सड़क किनारे से प्लास्टिक कचरे का उठाया और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया

स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से प्लास्टिक से सुरक्षा, स्वच्छता ही सुरक्षा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को दिल्ली छावनी परिषद कार्यालय से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान इन्होंने भी सड़क किनारे से प्लास्टिक कचरे को उठाया और लोगों को स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

राजनाथ सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आजाद भारत में स्वच्छता ही एकमात्र ऐसा सामाजिक मुद्दा है, जो कुछ समय में जनांदोलन बन गया। देश में स्वच्छता अभियान कामयाब हुआ है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों को अब सड़क पर कूड़ा फेंकने से पूर्व मन में संशय होता है। शिक्षा संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों की मदद से देश को बच्चों के रूप में स्वच्छता दूत की फौज मिली है। यह इस जागरूकता अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है।

2014 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता कार्यक्रम की बात कही थी। स्वच्छता अभियान के तहत देश में करीब 10 करोड़ 60 लाख घरों में शौचालय बनाए गए। इसकी बदौलत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर देश के करीब 100 जिलों को खुले में शौच मुक्त किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गांव में भी लोग इस अभियान को लेकर जागरूक हुए हैं।

उन्होंने अपील की कि देश के प्रत्येक हिस्से में प्रतिवर्ष करीब सात दिन स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि लोग इससे निरंतर जुड़े रहें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति लोगों में जो जागरूकता पैदा हुई है, वह सतत बनी रहे। वहीं श्रीपाद येसो नाइक ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सरकार चिंतित है। यदि हर व्यक्ति अपने-अपने स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं का प्रयोग करने पर जोर दे, तो वर्ष 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य पूरा होना तय है। उन्होंने कार्यक्रम के अंत में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने यह शपथ ली।

रोगी कल्याण समितियां हो गई हैं निष्क्रिय : विजेंद्र गुप्ता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ आरटीआइ के तहत मिली जानकारी को आधार बनाकर लगाया आरोप

भाजपा ने सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मिली जानकारी को आधार बनाकर दिल्ली सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि मरीजों को दवाइयां और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति बनाई गई थी। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को समिति का चेयरमैन बनाया गया और मुख्यमंत्री खुद इसके सदस्य हैं। बावजूद इसके समितियां मरीजों को मदद करने में विफल रही हैं।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने रोगी कल्याण समिति को 75 लाख रुपये देने की बात कही थी, लेकिन अधिकांश समितियों को पैसे नहीं मिले। कुछ अस्पतालों में पैसे आए तो उसे मरीजों के हित में खर्च नहीं किया गया। विधायकों ने अपने स्वार्थ के लिए धन का दुरुपयोग किया। रोगी कल्याण समिति पूरी तरह से निष्क्रिय रही है।

उन्होंने कहा कि आरटीआइ से मिली जानकारी के अनुसार पांच वर्षों में संजय गांधी अस्पताल, बाबू जगजीवन राम अस्पताल, गुरु नानक नेत्र केंद्र, गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिलशाद गार्डन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल, लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में 3.25 लाख में से 25 हजार रुपये बोर्ड बनवाने में खर्च किए गए। एमसी जोशी अस्पताल में 3,61,962 रुपये में से 80 हजार रुपये बैठक और कंप्यूटर की मरम्मत कराने पर खर्च किए गए। डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान में पांच लाख रुपये में से 24 हजार रुपये ऑडिट पर और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पांच लाख रुपये में से 96297 रुपये का टेलीविजन खरीदा गया।

दो एलआइजी फ्लैट को जोड़कर आवासीय योजना शुरू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ऑनलाइन आवासीय योजना-2019 में काफी संख्या में आवंटियों ने एलआइजी फ्लैट लौटा दिए थे। अब दो एलआइजी फ्लैट को जोड़कर नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत नरेला के जी-7 और जी-8 स्थित एक हजार फ्लैट हैं। अब इनको जोड़कर 500 फ्लैटों की योजना लाई गई है। फ्लैटों को डीडीए के प्लान के अनुसार जोड़ा जाएगा, लेकिन खर्च आवंटी को उठाना पड़ेगा।

इसमें पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से फ्लैट का आवंटन होगा। योजना में आवेदक को दो फ्लैट खरीदने होंगे। ये नरेला के जी-7 और जी-8 में 500 जोड़े एलआइजी फ्लैट हैं। दोनों फ्लैट का साइज 99.80 वर्ग मीटर और कीमत 44.78 लाख रुपये होगी। इस योजना को हाल ही में डीडीए अथॉरिटी की बैठक में स्वीकृति दी गई थी। फ्लैट के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। बशर्ते उसके पास दिल्ली में 67 वर्ग मीटर का कोई दूसरा मकान या प्लाट न हो।

बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है प्रदूषण स्तर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रदूषण मॉनीटरिंग स्टेशन में दिल्ली का एयर इंडेक्स शनिवार को 33 अंक गिरकर 371 दर्ज हुआ, जो बहुत खराब श्रेणी है। शुक्रवार को एयर इंडेक्स 404 दर्ज हुआ था। इसके साथ ही गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा व ग्रेटर नोएडा में भी एयर इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में बीते दो दिनों से हवा की रफ्तार में कमी आई है। इससे पहले 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी। अब कई जगहों पर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। इसकी वजह से प्रदूषक तत्व एक ही जगह पर ठहर रहे हैं। इन्हीं वजहों से प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रोजेक्ट सफर के मुताबिक रविवार को प्रदूषण का स्तर और अधिक बढ़ सकता है।

दूसरी ओर दिल्ली में ठिठुरन बढ़ रही है। इस वजह से शनिवार को दिन में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस ज्यादा के साथ 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान सामान्य के साथ 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों तक इसी तरह से न्यूनतम तापमान की स्थिति रह सकती है।

आप प्रदूषण पर राजनीति करती रही तो यहां रहना मुश्किल हो जाएगा : गोयल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राज्यसभा सदस्य विजय गोयल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से कनॉट प्लेस तक मशाल जुलूस निकाला। गोयल ने कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराती रही है। सरकार का कहना था कि पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। अब पराली नहीं जल रही है, फिर भी राजधानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। सरकार को इसका कारण बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के मूल कारणों को दूर करने पर दिल्ली सरकार ध्यान नहीं दे रही है इसलिए यहां की हवा जहरीली होती जा रही है। समस्या हल करने के लिए केंद्रीय समिति बननी चाहिए। इस समिति में पर्यावरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली सरकार और नगर निगमों के प्रतिनिधि के साथ ही अन्य संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए। केजरीवाल सरकार प्रदूषण पर राजनीति करती रही तो दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। आज भी दिल्ली में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। सरकार खुद ही पानी के नमूने लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। कहा कि केंद्र ने अनाधिकृत कॉलोनियों में लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला किया है। इसे लेकर भी मुख्यमंत्री केजरीवाल लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। उत्तर दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के चैयरमेन जय प्रकाश ने कहा कि दिल्ली सरकार हर जगह टकराव की राजनीति कर रही है।

जेवर में डेढ़ वर्ष में तैयार होगा राजकीय कन्या महाविद्यालय

संवाद सहयोगी, जेवर : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने शनिवार को जेवर में बनने वाले राजकीय कन्या महाविद्यालय की आधारशिला रखी। जेवर-गोविंदगढ़ मार्ग पर बनने वाले कन्या महाविद्यालय के निर्माण पर करीब दस करोड़ रुपये की लागत आएगी। डेढ़ वर्ष में यह बनकर तैयार हो जाएगा। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह के प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार ने इसका निर्माण कराया है।

डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कटिबद्ध है। सरकार लड़कियों की उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए हर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक कन्या महाविद्यालय का निर्माण कराया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को इंटर की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए दूर न भटकना पड़े। जेवर में कन्या महाविद्यालय के निर्माण के बाद आसपास के क्षेत्र की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दूरदराज नहीं जाना होगा।

आमने-सामने

एनडीएमसी की ओर से पार्किंग निजी कंपनी को सौंपने और शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ दुकानदारों ने खोला मोर्चा

बंगाली मार्केट में दुकानदारों ने कराई नि :शुल्क पार्किंग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

लुटियन दिल्ली के प्रसिद्ध बंगाली मार्केट में पार्किंग शुल्क विवाद के बीच दुकानदारों ने मुफ्त पार्किंग का बैनर लगाकर बाजार में आ रहे वाहनों को खड़ा कराना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) की अधिकृत कंपनी के पार्किंग कर्मचारी भी मौजूद रहे। एक बार पार्किंग कर्मचारियों ने पर्ची काटने की कोशिश की, लेकिन दुकानदारों द्वारा विरोध जताने पर पर्ची काटना बंद कर दिया। दुकानदारों के मुताबिक शनिवार को 500 से अधिक गाड़ियों की निःशुल्क पार्किंग हुई है।

दुकानदारों ने कहा कि जब तक पार्किंग शुल्क को लेकर विवाद का निपटारा नहीं हो जाता है, तब तक वह मुफ्त पार्किंग की सुविधा जारी रखेंगे। उनको पार्किंग शुल्क ढाई गुना बढ़ाने पर आपत्ति है, जिसे जुलाई से 20 रुपये प्रति घंटा से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। सोमवार को एनडीएमसी ने विवाद को लेकर दुकानदारों को बातचीत के लिए बुलाया है।

बंगाली मार्केट में पार्किंग शुल्क बढ़ने के विरोध में दुकानदारों ने लगाया फ्री पार्किंग का बैनर। जागरण

दुकानदारों का आरोप है कि पार्किंग शुल्क बढ़ाने से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में इसके विरोध में कई दिनों से दुकानदार आंदोलनरत हैं। दो दिनों तक बाजार बंद रखकर भी विरोध जताया था। शनिवार को बाजार सामान्य तरीके से खुले रहे लेकिन दुकानदारों का विरोध जारी रहा। उन्होंने एनडीएमसी के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया है। बाजार में जगह-जगह मुफ्त पार्किंग के बैनर और पोस्टर लगाए हैं और अपने कर्मचारियों से वाहनों की निःशुल्क पार्किंग करा रहे हैं।

बंगाली मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव प्रमोद गुप्ता ने कहा कि जब तक पार्किंग शुल्क विवाद और इसके संचालन का विवाद खत्म नहीं होता है, तब तक विरोध जारी रहेगा। क्योंकि ई-कॉमर्स और आर्थिक सुस्ती के बीच इस नए विवाद ने उनके कारोबार पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। 50 फीसद तक कारोबार कम हो गया है।

लुटियन दिल्ली के पॉश बाजारों में से एक बंगाली मार्केट में पार्किंग को लेकर एनडीएमसी और दुकानदारों में तकरार पिछले छह माह से चल रही है। दुकानदारों की एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 15 सालों से पार्किंग संचालन का जिम्मा उनके हाथों में था, जिसे एनडीएमसी ने निजी कंपनी को दे दिया है। साथ ही पार्किंग शुल्क भी बढ़ा दिया गया है।

जल्द दूर होगा आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का टोटा

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार की आयुर्वेदिक व यूनानी डिस्पेंसरियों से दवाओं का टोटा जल्द दूर होगा। इसके लिए सरकारी स्तर पर प्रयास तेज हो गए हैं। लोगों की परेशानी देखते हुए दिल्ली कैबिनेट ने केंद्र सरकार की कंपनी आइएमपीसीएल (इंडियन मेडिसिंस फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड) से दवाइयां खरीदने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार की 44 आयुर्वेदिक व 22 यूनानी डिस्पेंसरियां हैं। दोनों में करीब एक सौ दवाइयां हैं। इन डिस्पेंसरियों के लिए दवाई खरीद की प्रक्रिया ऐसी उलझी की कि 31 मार्च 2018 के बाद दवाइयां नहीं खरीदी जा सकीं।

31 मार्च 2018 के बाद से दवाइयां नहीं खरीदी जा सकी हैं। दो बार टेंडर फेल हो चुके हैं। पहली बार टेंडर जारी हुए तो टेंडर में भाग नहीं ले पाने वाली एक कंपनी हाई कोर्ट चली गई। उसने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग के सर्वर में समस्या थी इसलिए वह टेंडर के लिए अपने दस्तावेज नहीं अपलोड कर पाई। इस पर हाई कोर्ट ने कंपनी को राहत दी। मगर विभाग सुप्रीम कोर्ट चला गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस निरस्त कर दिया। इसके बाद विभाग ने फिर से टेंडर जारी किए। इसमें 65 कंपनियां आईं। इनमें से 11 कंपनियों के दस्तावेज सही पाए गए थे। मगर इसी दौरान विभाग को पता चला कि जिन कंपनियों ने सरकार को जो रेट दिए हैं, उनके उन्हीं दवाइयां के लिए नगर निगमों व नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के लिए रेट अलग हैं। इस बार भी टेंडर निरस्त हो गए। अब तीसरी बार टेंडर जारी किए गए हैं जो गत 22 नवंबर को खोल दिए गए। इसमें करीब 25 कंपनियों ने भाग लिया है। मगर इस कार्य में कुछ समय लग सकता है। इसके चलते सरकार ने सीजीएचएस के रेट पर भारत सरकार की कंपनी से अगले छह माह के लिए दवाइयां लेने के लिए स्वीकृति दे दी है।

5500 स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान कर रहा है रेलवे। जनवरी 2016 में मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर सबसे पहले यह सुविधा शुरू की गई थी। 46 महीनों में रेलटेल ने देशभर के 5500 स्टेशनों पर इस सेवा का विस्तार कर दिया है।

सेनाओं पर साइबर हमला अधिकारी-जवान अलर्ट

हिमाकत ▶ देश विरोधी तत्वों ने शुक्रवार देर रात बनाया निशाना

पाकिस्तान या चीन का हाथ होने की आशंका

नई दिल्ली, आइएएनएस : देश की सेनाओं पर शुक्रवार की देर रात हैकर्स ने साइबर हमला किया। हमले के बाद तीनों सेनाओं के साइबर विंग ने आपात चेतावनी देते हुए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को आगाह किया कि अटैचमेंट के साथ 'नोटिस' शीर्षक वाले ईमेल को न खोलें। शनिवार को सूत्रों ने यह जानकारी दी।

आपात चेतावनी : इमरजेंसी अलर्ट में कहा गया है कि एचएनक्यू नोटिस फाइल. एक्सएलएस डाउनलोड नाम के हाइपरलिंक के साथ फिशिंग मेल सैन्य कर्मियों को भेजे जा रहे हैं। यह मेल खासतौर से 'पीआरवीआइएनएवाइएके.598के एट जीओवी.आइएन' ईमेल आइडी से भेजे जा रहे हैं। अलर्ट में कहा गया है कि इस तरह का सब्जेक्ट, ईमेल आइडी और लिंक के साथ भेजा जाता है तो सावधान रहना चाहिए। इनबॉक्स में ऐसे मेल मिलते हैं तो उन्हें कतई खोला न जाए, बल्कि उन्हें रिपोर्ट किया जाए या फिर डिलीट कर दिया जाए।

प्रतीकात्मक

पाकिस्तान ने 2016 में हजारों फाइलें चुराई थीं

पाकिस्तानी जासूसी का मुख्य उद्देश्य भारतीय जासूसों, सैन्य इकाइयों की तैनाती, पूर्व सैन्य कर्मियों की जानकारी जुटाना होता है। 2016 में पता चला था कि साइबर हमलावर भारत की स्कॉरपीन पनडुब्बी बेड़े की क्षमता की जानकारी वाली हजारों फाइलें चुराने में सफल हो गए। हालांकि भारतीय नेवी ने तब कहा था कि इन फाइलों में कोई गोपनीय जानकारी नहीं थी।

चीन या पाक से हो रहे साइबर हमले : सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमला पाकिस्तान या चीन से हो रहा है। हाल में जैसे ही ये हमले तेज हुए, हमारी साइबर यूनिट अलर्ट हो गई है। सरकार ने भी सशस्त्र बलों के लिए डिफेंस साइबर एजेंसी स्थापित करने की योजना बनाई है। सिर्फ सैन्य साइबर मसलों पर फोकस के लिए स्थापित की जाने वाली इस एजेंसी का काम चीन और पाकिस्तान जैसे विदेशी ठिकानों से उत्पन्न खतरों से निपटना है।

पाकिस्तानी जासूस दूसरे देशों की आड़ में कर रहे हैं हमले : सूत्रों ने बताया कि साइबर हमलों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी जासूस भारतीय सैन्य कर्मियों को अपने जाल में लेने के लिए कई दूसरे देशों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई मामलों में जासूस दूसरे देशों के सुरक्षा अधिकारी के तौर पर भारतीय सेना के संचार तंत्र में सेंध लगाने में सफल हो गए।

ईडी ने गुजराती कंपनी की 34 करोड़ की संपत्तियां अटैच की

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है। ईडी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। ईडी ने एक बयान जारी कर कहा कि बायोटोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक राजेश एम कपाड़िया तथा अन्य के खिलाफ जांच की जा रही है। इनके खिलाफ गुजरात पुलिस और सीबीआइ की भी जांच जारी है। जांच में आरोपितों के द्वारा 2007 से 2009 के दौरान फर्जी बिलों और रसीदों के जरिये करीब 250 करोड़ रुपये का हेरफेर करने का पता चला है।

ईडी ने कहा कि केजीएन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक आरिफ इस्माइल भाई मेमन ने राजेश कपाड़िया एवं अन्य के साथ साठगांठ कर हेराफेरी में बड़ी भूमिका निभाई। मेमन ने फर्जीवाड़े के जरिये करीब 62 करोड़ रुपये केजीएन ग्रुप ऑफ कंपनीज के खातों में जमा किया। ईडी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत केजीएन एंटरप्राइजेज लिमिटेड और सैलानी एग्रोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित जमीन, संयंत्र व मशीनें तथा अहमदाबाद में स्थित मेमन की आवासीय संपत्ति को अटैच किया। अटैच संपत्तियों का कुल मूल्य 34.47 करोड़ रुपये है। ईडी इस मामले में पहले भी 149 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर आरोपपत्र दाखिल कर चुका है।

डीजीपी-आइजीपी सम्मेलन में शामिल हुए पीएम

पुणे, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यहां पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) और महानिरीक्षकों (आइजीपी) के सम्मेलन में शामिल हुए। तीन दिनों का यह सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ था।

प्रधानमंत्री के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। यह सम्मेलन भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं शोध संस्थान में आयोजित किया गया है। पीएमओ ने एक ट्वीट में कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के शीर्ष पुलिस अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। यहां आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजभवन में आयोजित सशस्त्र बल झंडा दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत की। वहां उन्होंने 2016 में नागरोटा आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर कुणाल गोस्वामी की पत्नी और बेटी से मुलाकात की। ट्विटर पर झंडा दिवस समारोह के संबंधित 57 मिनट का वीडियो जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौके पर हम सशस्त्र बलों के जवानों और उनके परिजनों के अदम्य साहस को सलाम करते हैं। उन्होंने लोगों से भी सैन्य बलों के कल्याण के लिए योगदान देने की अपील की। इससे पहले, शुक्रवार को मुंबई पहुंचने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हवाईअड्डे पर उनका स्वागत किया था। भाजपा-शिवसेना गठबंधन के टूटने और ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी।

महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार को अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में हिस्सा लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (सामने, मध्य में) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (सामने, दाएं)। प्रेट्र

भाजपा में उपेक्षा जारी रही तो दूसरे विकल्प देखूंगा : खड़से

जलगांव, प्रेट्र : महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्य के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने शनिवार को खुलकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर भाजपा में उनकी उपेक्षा जारी रही तो वह दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे।

खड़से ने यह भी कहा कि उन्होंने भाजपा नेतृत्व को पार्टी विरोधी गतिविधियों का साक्ष्य सौंपा है, जिसके कारण 21 अक्टूबर को हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी रोहिणी और कई अन्य प्रत्याशियों को हार मिली। खड़से ने यहां भाजपा की उत्तर महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई साल हो गए उन्हें पार्टी की कोर कमेटियों और निर्णायक समिति की बैठकों से बाहर रखा जा रहा है।

उन्होंने कहा, 'मैं भगवान नहीं हूं। भावुक आदमी हूं। मैं उस पार्टी को नहीं छोड़ना चाहता जिसे आगे बढ़ाने में चार दशक मेहनत की है। मैं अब भी पार्टी के लिए काम करने को तैयार हूं, लेकिन निर्णय लेने वाली समिति से दूर रखा जाता रहा तो मुझे दूसरे विकल्पों पर विचार करना होगा।' अन्य पिछड़ा वर्ग

- महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता ने खुलकर जाहिर की नाराजगी
- कहा, पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रख कदम उठाए

(ओबीसी) नेताओं को पार्टी में हाशिये पर लाए जाने संबंधी बयान पर खड़से ने कहा, 'यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा महसूस कर रहे हैं। ओबीसी और बहुजन समाज नेताओं ने पार्टी को कड़ी मेहनत और खून से सींचकर बड़ा किया है। पार्टी नेतृत्व को कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उचित कदम उठाना चाहिए। मुझे बदनाम किया गया और सभी प्रकार की जांच बैठाई गई। अगर मैं दोषी हूं तो कार्रवाई करें, लेकिन मुझे जानबूझकर बदनाम किया गया।'

बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि उन्होंने खड़से को आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व में बनी सरकार में खड़से वरिष्ठ मंत्री थे, लेकिन भूमि संबंधी अनियमितता में उनके परिवार की संलिप्तता का आरोप लगने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।

अंदरूनी कलह के चलते थम गई कृषि संस्थानों के निदेशकों की भर्ती प्रक्रिया

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

कृषि क्षेत्र को नए मुकाम पर पहुंचाकर सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य भले ही तय कर लिया हो, लेकिन जिन संस्थानों पर इसकी जिम्मेदारी है, उनमें से ज्यादातर में न तो निदेशक हैं और न ही पर्याप्त वैज्ञानिक। गत ढाई वर्षों से आठ उप महानिदेशक, 60 निदेशकों समेत सैकड़ों कृषि वैज्ञानिकों के पद खाली हैं। छह माह पहले चालू हुई नियुक्ति प्रक्रिया अब अंदरूनी कलह के चलते ठप पड़ गई है।

कृषि वैज्ञानिकों की नियुक्ति के लिए स्थापित कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (एएसआरबी) ने छह महीने पहले रिक्त पदों को भरने की शुरुआत की थी। कड़ी मशक्कत के बाद काम पटरी पर लौटा और उप महानिदेशक और निदेशक समेत 72 प्रमुख पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन मांगे गए। लेकिन भर्ती बोर्ड और एएसआरबी के बीच के विवाद ने इसे अचानक रोक दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अगस्त, 2018 को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आइसीएआर) और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन (डेयर) के बीच दायित्वों के बंटवारे पर अपनी मुहर लगा दी।

- ढाई साल से 60 फीसद अनुसंधान संस्थान हैं मुखिया विहीन, ठप है कृषि वैज्ञानिकों की नियुक्ति प्रक्रिया

प्रतीकात्मक

सूत्रों के मुताबिक इस दायित्व वितरण में एएसआरबी को डेयर का हिस्सा बना दिया गया। लिहाजा कृषि वैज्ञानिकों और निदेशकों के पदों की नियुक्तियों में आइसीएआर के महानिदेशक की भूमिका समाप्त हो गई। लेकिन, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही महानिदेशक ने इस प्रावधान पर अपनी आपत्ति जताते हुए इसमें खुद को शामिल करने का आग्रह किया। परंतु भर्ती बोर्ड ने इसे मानने से इन्कार कर दिया। इस पर विवाद पैदा हो गया और नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई। तब यह मामला कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास अंतिम फैसला लेने के लिए भेज दिया गया। लेकिन, अभी तक फैसला नहीं हो पाया है।

केंद्र सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती में प्रक्रियागत बदलाव करने में डेढ़ साल का लंबा समय लग गया। इसके बाद ठप पड़े एएसआरबी में चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति कर इसे चालू किया गया। लेकिन, जब भर्ती प्रक्रिया चालू हुई, तो अफसरों के अहम आड़े आ गए और प्रक्रिया को रोक देना पड़ा। कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने वाली संस्था आइसीएआर के पूसा जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आइएआरआइ) की तर्ज पर तीन और संस्थान खोल दिए गए हैं। लेकिन एक में भी निदेशक नहीं हैं। सब जगह कामचलाऊ लोगों से काम लिया जा रहा है, जो स्थानीय स्तर पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। उप महानिदेशक स्तर के आठ पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने की शुरुआत हो चुकी थी। प्राप्त आवेदनों की छंटनी के बाद साक्षात्कार के लिए न्योता भेजा जाना था।

विफल हो गए ममता से बातचीत के सभी प्रयास : राज्यपाल

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा-तमाम प्रयास के बावजूद मुख्यमंत्री की ओर से नहीं आया कोई जवाब
- अब भी सीएमओ से सकारात्मक जवाब मिलने की है उम्मीद

बंगाल में राज्य सरकार और राजभवन के बीच जारी टकराव पर अभी विराम लगता नहीं दिख रहा। शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के साथ राजभवन या राज्य सचिवालय नवान्न कहीं भी किसी भी मुद्दे पर बातचीत को तैयार हूं, वहीं, शनिवार को उन्होंने कहा कि उनके द्वारा विवाद को खत्म करने के तमाम प्रयास के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। बातचीत के सभी प्रयास विफल हो गए हैं।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वह उनकी ओर से बातचीत की कोशिशों का जवाब तक नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से बातचीत के सभी प्रयास विफल हो गए, क्योंकि उनके अनुरोध पर मुख्यमंत्री के कार्यालय से कोई जवाब नहीं आया।

शनिवार को राज्यपाल ने ट्वीट किया, 'पिछले दरवाजों से संपर्क की कोशिशें विफल रहने के बाद मैंने बतौर राज्यपाल मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से उनकी पसंद की जगह, समय और दिन की सुविधा से चर्चा और संवाद के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि यही एकमात्र संवैधानिक तरीका था।' उन्होंने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री उन्हें राज्यपाल के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि उन्हें अब भी बनर्जी से सकारात्मक जवाब मिलने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि कई मुद्दों पर राज्यपाल व राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच लंबे समय से जुबानी जंग चल रह है। यहां तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इशारों में समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगा चुकी हैं। बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही यह कहते हुए दो दिनों के लिए स्थगित कर दी गई कि विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर ही नहीं किए थे। इसके बाद गुरुवार को राज्यपाल जब विधानसभा पहुंचे तो गेट बंद था और उन्हें दूसरे गेट से अंदर जाना पड़ा। इस बीच शुक्रवार को राज्यपाल ने कहा कि वे हर मुद्दे पर सीएम के साथ बातचीत को तैयार हैं।

पीएसए में गिरफ्तार एनआरआइ व्यापारी मुबीन शाह तीन महीनों के लिए रिहा

राज्य ब्यूरो, जम्मू

चार महीने पहले जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए गए कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष मुबीन शाह को तीन महीने के लिए रिहा कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद सात अगस्त को मुबीन को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था।

केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने शनिवार को एनआरआइ व्यापारी मुबीन को रिहा करने का आदेश जारी किया। यह आदेश जेल अधिकारियों को सौंपा गया। इसके बाद उन्हें तीन महीने के लिए सेंट्रल जेल आगरा से रिहा कर दिया गया। मुबीन को उनके भाई नियाज लेने गए थे।

मुबीन शाह उन चंद राजनीतिज्ञों व संगठनों के सदस्यों में शामिल हैं, जिन्हें जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद सरकार ने हिरासत में लिया था। वह मलेशिया में रहते हैं और वहां हैंडीक्राफ्ट का व्यापार करते हैं। वह इसी साल मई महीने में श्रीनगर आए थे। यहां उन्हें कश्मीर में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए

- चार महीने पहले कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हिरासत में लिया गया था
- कश्मीरी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रह चुके हैं मुबीन शाह
- उत्तर प्रदेश की आगरा जेल में थे बंद, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पीएसए के तहत हिरासत में रखा था।

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पांच अगस्त को कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस, पीपुल्स कांफ्रेंस सहित कश्मीर के कई राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेताओं को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया था। इनमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, नेकां के अली मोहम्मद सागर सहित 34 नेताओं को डल झील किनारे स्थित सेंटूर होटल में रखा गया था, लेकिन श्रीनगर में ठंड बढ़ने के बाद उनके स्वास्थ्य को देखते हुए सभी 34 नेताओं को अब श्रीनगर एमएलए हॉस्टल में रखा गया है।

अब सात मार्च को जिला अदालत में होना होगा पेश

मुबीन को अब अगले साल सात मार्च को जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर के समक्ष पेश होना होगा। उन्होंने अपने बांड में लिखकर दिया है कि तीन महीनों के दौरान वह ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, जिससे शांति व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगे। उनके परिजनों ने पीएसए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस केस की सुनवाई नौ दिसंबर को होगी। चार महीनों में मुबीन शाह रिहा होने वाले चंद लोगों में शामिल हैं। इससे पहले प्रशासन ने पीडीपी नेता दिलावर मीर और पूर्व मंत्री गुलाम हसन मीर को पिछले महीने रिहा कर दिया था। कुछ नेताओं को प्रशासन ने अपने परिजनों से मिलने के लिए अनुमति भी दी थी।

सांसदों को विदेश यात्रा की जानकारी देने से संबंधित निजी बिल पेश

नई दिल्ली, एएनआइ : भाजपा के राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन के लिए उच्च सदन में निजी विधेयक पेश किया है। इसमें सांसदों को अपनी विदेश यात्रा की विस्तृत जानकारी देने को अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। इस साल जुलाई में संसदीय कार्य मंत्री ने सभी सांसदों को इस सिलसिले में पत्र लिखा था। लेकिन जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 में इसे अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है।

विधेयक में कहा गया है कि संसद सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी विदेश यात्रा, इसका उद्देश्य और यात्रा मार्गों की जानकारी संबंधित सदन के महासचिव को दें, ताकि विदेश मंत्रालय इसके बारे में भारतीय मिशन को सूचित कर सके। निजी हैसियत से विदेश जाने वाले सांसदों को भी सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के संबंध में जानकारी दें। वैधानिक आवश्यकता के अभाव में इस सलाह का अधिकतर सांसदों द्वारा पालन नहीं किया जाता है। विधेयक में विदेश यात्रा के दौरान घूमे गए स्थानों, यात्रा की अवधि, खर्च, आमदनी का स्रोत और आतिथ्य को लेकर जानकारी देने का प्रस्ताव किया गया है।

भावी कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल पर अमरिंदर ने साधी चुप्पी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पंजाब के मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यसमिति पर छोड़ा मामला
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने खुलकर की राहुल की पैरोकारी

कांग्रेस पार्टी के भीतर वैसे तो राहुल गांधी के विकल्प के तौर पर कोई ऐसा नाम नहीं उभर रहा जिसपर सर्वसम्मति बन सके। खुलकर यह बातें कही भी जा रही हैं। लेकिन शनिवार को एक कार्यक्रम में कांग्रेस के ही दो मुख्यमंत्रियों-कैप्टन अमरिंदर सिंह और भूपेश बघेल का रुख अलग-अलग था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने न सिर्फ राहुल को फिर से अध्यक्षता दिए जाने की वकालत की, बल्कि यह भी कहा कि वही भविष्य के नेता हैं। जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर ने इसे कांग्रेस कार्यसमिति पर छोड़ दिया।

दरअसल, कार्यक्रम में दोनों से एक ही सवाल किया गया था- सोनिया गांधी कहती हैं कि वह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। आप किसे भावी अध्यक्ष के तौर पर देखते हैं? कैप्टन ने कहा- मैं अपनी कोई राय रखूं यह ठीक नहीं होगा। पार्टी कार्यसमिति इसका निर्णय लेगी, जिसके पास इसका अधिकार है। जबकि भूपेश ने राहुल का नाम लेते हुए कहा कि उनमें ही सीधा-सपाट बोलने और जनता की समस्याओं को रखने की हिम्मत है। इसके साथ ही उनमें जिम्मेदारी लेने की भी

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल फोटो

हिम्मत है। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली और इस्तीफे पर अड़े रहे। हालांकि उन्हें इस दौरान मनाने की काफी कोशिश हुई।

वैसे कैप्टन कांग्रेस के उन नेताओं में हैं, जो राहुल के इस्तीफे के वक्त से ही कहते रहे हैं कि कांग्रेस को युवा नेतृत्व चाहिए ताकि देश के युवा पार्टी से जुड़ सकें।

रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट से इलाज के लिए स्पेन जाने की अनुमति मांगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : विदेश में संपत्ति के मामले में मनी लांड्रिंग के आरोपित कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने इलाज कराने और व्यवसाय का हवाला देते हुए स्पेन जाने की अनुमति मांगी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। अदालत 9 दिसंबर को सुनवाई करेगी।

इससे पहले अदालत ने जून माह में प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को इलाज के लिए छह सप्ताह के लिए अमेरिका व नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी। हालांकि, उन्हें लंदन जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। दरअसल ईडी ने विरोध करते हुए कहा था कि अगर वाड्रा को लंदन जाने की अनुमति दी गई तो वह सबूत नष्ट कर सकते हैं। इससे पहले अदालत ने उन्हें एक अप्रैल को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी और कहा था कि वे बिना अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे। ईडी ने अग्रिम जमानत याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित है। वाड्रा पर लंदन में संपत्ति खरीदने में मनी लांड्रिंग का आरोप है। ईडी का आरोप है कि यह संपत्ति वाड्रा की है।

अद्वितीय प्रतिभा

धर्म विज्ञान के बाद आयुर्वेद और संस्कृत विभाग में भी चयन, कार्यकारिणी परिषद ने कुलपति के विवेक पर छोड़ा निर्णय

डॉ. फिरोज के पास बीएचयू में अब तीन विकल्प

जागरण संवाददाता, वाराणसी

बीएचयू के धर्म विज्ञान संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तैनाती के बाद से डॉ. फिरोज का विरोध करने वालों को मेधावी मुस्लिम शिक्षक की तरफ से अद्वितीय प्रतिभा का धनी होने का पैगाम मिला है। विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद ने जब लिफाफे खोले तो पाया कि डॉ. फिरोज का चयन आयुर्वेद संकाय संहिता एवं संस्कृत सहित कला संकाय के संस्कृत विभाग में भी हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कार्यकारिणी ने चयन पर स्वीकृति देते हुए गेंद कुलपति प्रो. राकेश भटनागर के पाले में डाल दी है। कार्यकारिणी ने स्पष्ट कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुस्लिम शिक्षक धर्म विज्ञान नहीं पढ़ा सकते हैं, फिर भी विश्वविद्यालय को यह देखना चाहिए कि यदि विकल्प है तो क्या कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। कार्यकारिणी ने मसले पर कुलपति को स्वतंत्र होकर निर्णय लेने का निर्देश दिया। हालांकि अंतिम निर्णय फिरोज लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे कहां अध्यापन करना चाहेंगे। नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार को बीएचयू के कार्यकारिणी परिषद की बैठक हुई। बैठक में कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सर्वाधिक गंभीर मसला डा. फिरोज का ही रहा जिस पर देर तक कार्यकारिणी ने विमर्श किया।

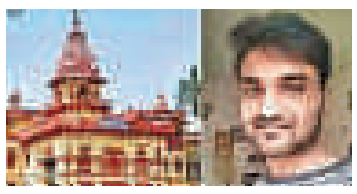

बीएचयू और डॉ. फिरोज की फाइल फोटो।

भविष्य निधि की राशि के डीएचएफएल में निवेश का मामला भी उठा : सूत्रों के अनुसार, कार्यकारिणी की बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारियों के भविष्य निधि के रुपयों के निवेश का मसला भी उठा। कुलपति द्वारा स्पष्ट किया गया कि पूर्व में कई वर्षों के दौरान कुल 180 करोड़ रुपये डीएचएफएल (दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) में निवेश किए गए थे जिसमें ब्याज सहित 175 करोड़ रुपये वापस भी मिल गए हैं, शेष फंसे फंड को लेकर विधिक परामर्श लिया जा रहा है। कार्यकारिणी ने विश्वविद्यालय की इनवेस्टमेंट कमेटी को निर्देश दिया कि कर्मचारियों के फंड को विश्वसनीय सेक्टर में ही निवेश करें। खासकर प्राइवेट सेक्टर को लेकर बेहद सतर्कता से कदम उठाया जाए।

कितनी स्वायत्तता चाहता है आइएमएस : बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आइएमएस) और अस्पताल को एम्स जैसा दर्जा दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में मांग उठी कि आइएमएस को और स्वायत्तता चाहिए। कार्यकारिणी ने सवाल उठाया कि आखिरकार उन्हें कितनी स्वायत्तता चाहिए। यह ध्यान रहे कि आइआइटी बीएचयू की तरह ही आइएमएस भी हमेशा विश्वविद्यालय के अधीन ही रहेगा। किसी भी सूरत में पूर्ण स्वायत्तता नहीं दी जाएगी। हां, यह भी है कि उन्हें मिलने वाली फंडिंग और उनके कार्यों में बेवजह बीएचयू प्रशासन द्वारा कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। बैठक में नीति आयोग के एक सदस्य ने इस संबंध में प्रजेंटेशन भी दिया। अंत में कार्यकारिणी ने कहा कि जो भी अपेक्षाएं हैं उसका विस्तृत प्रस्ताव अगली बैठक में लाया जाए।

अवमानना मामले में चुनौती

कार्यकारिणी की बैठक में न्यायालय से जुड़े विश्वविद्यालय के मामलों को लेकर भी चर्चा हुई। कुलपति ने कार्यकारिणी सदस्यों को बताया कि अभिषेक चंद्रा मामले में अवमानना को लेकर विश्वविद्यालय याचिका दायर करेगा।

ट्वीट मामले में निर्णय बाद में

कार्यकारिणी परिषद के समक्ष समाजशास्त्र के एक प्रोफेसर के खिलाफ एक छात्र द्वारा आपत्तिजनक ट्वीट किए जाने का मामला कार्रवाई के लिए लाया गया जिस पर अगली बैठक में विचार की सहमति बनी।

कह के रहेंगे माधव जोशी

74.44 फीसद मतदान हुआ है झारखंड के बहरागोड़ा विधानसभा सीट पर जो दूसरे चरण का सर्वाधिक रहा। वहीं, जमशेदपुर पूर्वी व जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर सबसे कम वोट पड़े हैं।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 8 दिसंबर 2019

झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव में छिटपुट हिंसा, एक की मौत

चुनावी रण ▶ 20 सीटों के लिए हुए चुनाव में 64 .39 फीसद मतदान

जमशेदपुर पूर्वी व जमशेदपुर पश्चिमी में सबसे कम मतदान

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण की 20 विधानसभा सीटों पर शनिवार को हुए मतदान के दौरान नक्सलियों ने अपनी धमक दिखाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। छिटपुट हिंसा के बीच दूसरे चरण में 64.39 फीसद मतदान हुआ।

बहरागोड़ा सीट पर जहां सर्वाधिक 74.44 फीसद मतदान हुआ, वहीं जमशेदपुर पूर्वी व जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर सबसे कम वोट पड़े हैं। गुमला के सिसई विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 36 पर पुलिस व ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों के पथराव में थाना प्रभारी समेत पुलिस के कई जवान घायल हुए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी के चालक सीताराम सिंह व पत्रकार सीताराम साहू को भी चोट लगी है। वहीं, नक्सलियों ने चाईबासा के बड़केला स्थित जोजहातु में चुनाव कार्य में लगी बस को फूंक दिया, जबकि गोइलकेरा में

झारखंड में चाईबासा विधानसभा के जोजो हातु गांव में मतदाताओं को लाने के लिए प्रशासन के द्वारा भेजी गई बस को नक्सलियों ने शनिवार को आग के हवाले कर दिया, घटनास्थल पर जलती बस। जागरण

मतदाताओं को लाने गई बस को नक्सलियों ने बंधक बना लिया। खूंटी के अड़की में मतदान के बाद लौट रहे मतदानकर्मियों का रास्ता रोक लिया। इस दौरान नक्सली व सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई है। इसमें किसी के हताहत की सूचना नहीं थी। नक्सलियों ने पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा क्षेत्र के गम्हरिया के चार बूथों और सरायकेला-खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड के पांच बूथों पर भी मतदान को प्रभावित किया।

सबसे 'हॉट' क्षेत्र में ठंड गुलाबी, मतदाता रहे 'चुपेचाप'

विश्वजीत भट्ट, जमशेदपुर

- जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में वोटरों में नहीं दिखा खास उत्साह
- कंपनी क्षेत्र की तुलना में बस्ती इलाकों के बूथों पर दिखी ज्यादा भीड़

झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों में सबसे हॉट का रुतबा पा चुकी जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर शनिवार को मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशी और मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनके खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय, झाविमो के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह प्रत्याशी गौरव वल्लभ समेत 20 प्रत्याशियों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद कर दी। प्रत्याशियों की जबर्दस्त तैयारी, प्रशासन की मुकम्मल व्यवस्था और मीडिया की भारी गहमागहमी के बीच मतदाताओं ने अपने मन का किया और वह भी चुपेचाप। गुलाबी ठंड में हुए मतदान के दौरान किसी भी बूथ पर वैसी गहमागहमी नहीं दिखी जैसी 2014 में दिखी थी। दलीय उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच भिड़ंत की आशंका भी मतदाताओं ने निर्मूल साबित कर दी। सरयू राय का यह एलान भी बेमानी हो गया कि हंगामा होने पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सियासी दलों के गढ़ समझे जाने वाले इलाकों में भी बूथों पर वोटरों का हुजूम नहीं दिखा और न ही किसी प्रत्याशी के टेंट में जनता का सैलाब उमड़ा। लोग आराम से आते रहे और वोट देकर जाते रहे।

मंथर गति से बढ़ा मतदान

सुबह नौ बजे	13.2 प्रतिशत
11 बजे	21.1 प्रतिशत
दोपहर एक बजे	34.9 प्रतिशत
शाम तीन बजे	46.41 प्रतिशत
शाम पांच बजे	49.12 प्रतिशत

3,06,607 वोटरों वाला यह विधानसभा क्षेत्र मुख्य रूप से दो भागों में बंटा है। एक कंपनी प्रदत्त नागरिक सुविधाओं वाला इलाका, यानि कंपनी क्षेत्र कहलाता है। दूसरा इलाका वैसी बस्तियों का है जहां सरकार की ओर से स्थानीय निकाय नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। दोनों इलाकों के मतदान केंद्रों पर प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था की थी। कई आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए थे। लेकिन, मतदाताओं ने सारी व्यवस्था और जागरूकता अभियान के बावजूद उतना उत्साह नहीं दिखाया। डीएवी पटेलनगर को छोड़कर शाम पांच बजे तक ऐसा एक भी मतदान केंद्र नहीं था जहां मतदाताओं की इतनी संख्या थी जिनका मतदान कराने में कुछ समय और खर्च करने पड़ते। इस क्षेत्र में सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक चला। वोट प्रतिशत 49.12 प्रतिशत रहा। मुख्यमंत्री रघुवर दास इसी क्षेत्र के वोटर हैं। उन्होंने भालूबासा स्थित हरिजन उच्च विद्यालय परिसर में बने केंद्र पर मतदान किया। आलम यह रहा कि जब वे मतदान केंद्र पर आए तो वोटरों की संख्या न के बराबर थी। नतीजतन उन्हें लाइन में लगने की नौबत ही नहीं आई। परिवार संग आए और आराम से वोट देने के बाद कुछ क्षण अपने टेंट में बैठकर वहां उमड़े मीडियाकर्मियों को मतदान वाली उंगली का निशान दिखाते हुए चले गए। पूरे क्षेत्र के सभी बूथों पर भाजपा से रघुवर दास, निर्दलीय सरयू राय, झाविमो के अभय सिंह और कांग्रेस के गौरव वल्लभ के टेंट लगे हुए थे। हर बूथ पर इनके एजेंट भी थे। लेकिन, मतदाताओं के चुपचाप आकर वोट डालने के अंदाज के कारण न कहीं बोगस वोटिंग की शिकायत आई और न कहीं अन्य तरह से हेराफेरी का ही अरोप लगा। अलबत्ता दिन में दो बजे के करीब जरूर बिरसानगर में भिड़ंत की अफवाह वायरल हुई, जो आधारहीन साबित हुई। मतदाताओं के ठंडे रुख से पूरी वोटिंग अवधि तक प्रत्याशियों, उनके रणनीतिकारों, चुनाव के पंडितों और नतीजों का अनुमान लगाने वाले दिग्गजों का दम फूलता रहा। कंपनी क्षेत्र से कम वोटिंग का निहितार्थ भी अपने हिसाब से प्रत्याशी निकालते रहे तो बस्ती इलाकों में अपेक्षाकृत ज्यादा वोटिंग के मायने भी बताए जाते रहे। मतदान समाप्ति के बाद चारों दमदार प्रत्याशियों के रणनीतिकारों ने रूटीन अंदाज में जीत के दावे किए। भाजपा बताती रही कि कम मत प्रतिशत का मतलब जीत के अंतर का कम होना नहीं होता। निर्दलीय सरयू राय के समर्थक निरूपित करते रहे कि वोट प्रतिशत गिरने का सीधा लाभ उन्हें मिलने की उम्मीद है। इन सबके बीच बूथ दर बूथ घूमते रहे झाविमो प्रत्याशी अभय सिंह बार-बार यह जताने का प्रयास कर रहे थे कि भाजपा और निर्दलीय भले सभी बूथ पर न दिखें, लेकिन उनकी उपस्थित हर बूथ पर है। मतदान के दौरान कांग्रेस के एजेंट और टेंट के साथ नेताओं की फौज भी अपनी उपस्थिति दिखाती रही। नतीजों को लेकर अटकलों का द्वार खोलकर मतदाता 'चुपेचाप' शाम पांच के बाद अपने घर हो लिए।

मतदान ड्यूटी में लगे उत्तर प्रदेश के एएसआइ की मौत

जागरण संवाददाता, बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम) : झारखंड के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के पचांडो कलस्टर में तैनात एएसआइ हरीश चंद्र गिरी की शनिवार की सुबह मौत हो गई। वे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाना क्षेत्र के दरबासागर गांव के निवासी थे। वे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में बिहार के बरौनी में तैनात थे। पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भेज दिया गया है।

बताया गया कि एएसआइ गिरी चुनाव कार्य में भाग लेने के लिए बहरागोड़ा आए थे। वे रात को सोए थे, लेकिन सुबह जगाने पर नहीं उठ पाए। इसके बाद उन्हें एंबुलेंस से बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घाटशिला के एसडीपीओ राजकुमार मेहता भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे थे।

स्मृति ईरानी के खिलाफ मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित

जागरण संवाददाता, गोड्डा

- लोकसभा चुनाव में झाविमो प्रत्याशी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द के प्रयोग का आरोप

बीते लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी रहे निशिकांत दूबे द्वारा झाविमो उम्मीदवार प्रदीप यादव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करने के मामले की सुनवाई अब धनबाद के फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।

गोड्डा के देवदांड़ में 11 मई 2019 को भाजपा की चुनावी सभा आयोजित की गई थी। झाविमो प्रत्याशी प्रदीप यादव के चुनाव अभिकर्ता संजीत अग्रवाल ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि इस सभा में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और निशिकांत दूबे ने प्रदीप के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद आयोग ने उक्त सभा के वीडियो फुटेज के आधार पर देवदांड़ थाने में स्मृति ईरानी और डॉ. निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। देवडांड़ पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में कोर्ट में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन कोर्ट ने मामले को फिर से संज्ञान लिया। प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि

स्मृति ईरानी फाइल

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से 14 दिसंबर 2017 को पारित आदेश में कहा गया है कि झारखंड राज्य में चुने गए सांसद, विधायकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य सरकार से परामर्श के बाद रांची एवं धनबाद में जिला न्यायाधीश स्तर के विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। यह फास्ट ट्रैक कोर्ट है। इसलिए स्मृति ईरानी और निशिकांत दुबे के मामले की सुनवाई अब धनबाद में ही होगी।

भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी : रूडी

राज्य ब्यूरो, रांची : भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने भी भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं की तरह पुनः भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा किया है। शनिवार को रांची में भाजपा के मीडिया सेंटर में रूडी ने 65 पार का लक्ष्य पार करने का पार्टी का दावा दोहराया। यह कहना भी नहीं भूले कि मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे।

रूडी ने कहा कि भाजपा ने ही राज्य को एक स्थिर सरकार दी और इस बार भी हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर पहले और अब भी झारखंड हमारे लिए महत्व रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड को देश का एक लाडला प्रांत मानते हैं। हमारा मानना है कि राज्य में अनंत संभावनाएं हैं। झारखंड आगे बढ़ रहा है। आदिवासी कल्याण, कृषि, आधारभूत संरचना सहित कई अन्य क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र व राज्य में एक जैसी सरकारें होती हैं, तो विकास में आसानी होती है।

उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के स्तर से अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक पर लिए गए निर्णयों का जिक्र किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी भाजपा की पहल से जोड़ा।

मतदान से पहले मुस्कुराए आदिवासी बोले-अपनों को ही देंगे वोट

भादो माझी, जमशेदपुर

- जमीन की सुरक्षा को लेकर मुखर उज्ज्वला समेत कई योजना से प्रभावित

लोकतंत्र के इस महापर्व में अगर मेले सा नजारा कहीं था तो गांवों में। खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में। सुबह-सुबह तालाब में नहाने के लिए शनिवार को आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी। नहा-धोकर वोट देने जो जाना था।

वोट डालने से पहले तालाब के घाट (जहां लोग नहाते हैं) पर ही आज झारखंड की सरकार तय हो रही थी। किसकी बनानी है, किसकी बिगाड़नी है। दांत से दातून पीसते सरकार की समीक्षा की जा रही थी। सीएनटी एक्ट से लेकर दो-दो गैस सिलिंडर मिलने तक पर माहौल बनाया जा रहा था। मुद्दा सीएनटी-सिलिंडर ही नहीं, मुद्दा यह भी था कि कौन नेता (प्रत्याशी) गांव में आया था, कौन नहीं। कुल मिलाकर ऐसे ही समीकरणों पर अपना सियासी नफा-नुकसान आंक कर आदिवासी वोटरों ने सुबह के नौ बजते-बजते मन की मुट्ठी बंद कर ली। तय कर लिया कि इस ओर जाना है, उसको हराना है। किसे वोट दे रहे हैं पूछने पर मुस्करा देते, और शिद्दत से झिझकते हुए कहते-'आबोइज् के गे।' (हमारे अपने को ही।) अब आप खुद समझ लीजिए कि 'हमारे अपने' के मायने इस विधानसभा सीट पर क्या हैं। बहरहाल, अब नौ बजने को थे, बूथ पर लाइन लंबी होती जा रही थी। बूथ के बाहर राजनीतिक दलों के नेता वोट का दाना चुगने को चहचहाने लगे थे। जो बूथ पर पहुंचता, उसे अपने हिसाब का समीकरण बताते, फायदे गिनाते। विपक्ष के नेता कान में फूंकते कि उधर (पक्ष) जाओगे तो जमीन से भी जाओगे। एक्ट-वेक्ट अधिकतर वोटरों को बहुत बुझाता नहीं। सो, सीधे-सीधे उनसे संताली में कहा गया-'हासा-बाड़गे बो ऐड़े ओचो आ।' (जमीन लुट जाएगी)। यह सुन वोटर सिर हिलाकर आगे चले जाते। आगे उन्हें पक्ष वाले सिलिंडर के साथ-साथ शौचालय, सड़क, आयुष्मान की याद दिलाते। यहां से भी पर्ची पकड़े वे बढ़ जाते। लाइन में खड़े होते। उंगली नीली करने के बाद बाहर निकलते तो चेहरे पर अलग ही सुकून लिए। सुकून इस बात का कि अब इसको वोट दो-उसको वोट दो के लिए उन्हें टोका नहीं जाएगा। दे दिया। बस। पोटका विधानसभा क्षेत्र के धिरोल गांव में वोटरों का यह मिजाज हर दूसरे चेहरे पर दिख रहा था। इस इलाके से भाजपा से मेनका सरदार तो झामुमो से संजीव सरदार मोर्चे पर हैं।

दिलचस्प बात यह कि इस इलाके के अधिकतर आदिवासी वोटरों को वोट देने तक यह ठीक-ठीक नहीं पता कि उनके वोट से मुख्यमंत्री तक तय होगा। संताली में पूछते भी हैं-'हें बबू लाय मेसे, मुदीये दाड़ेआ से सुनिया? (बाबू बताओ तो जरा कि इस बार मोदी जीत रहे कि शिबू।) उनका यह सवाल सुन आपको लगेगा कि ये राष्ट्रीय फलक को ध्यान में रखकर तो सियासी सवाल नहीं कर रहे, लेकिन नहीं। उन्हें तो दो ही नेता का नाम ठीक से पता है। वह हैं शिबू सोरेन और नरेंद्र मोदी। यही बात उन्हें परंपरागत वोटर भी बनाती है। परंपरागत वोटर, यानी उनके क्षेत्र में कौन खड़ा है, कौन नहीं, इसकी उन्हें जानकारी तक नहीं, बस जिसको देते आए थे, उसे देना है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की ओर बढ़ने पर वोटरों का उत्साह बढ़ता दिखा।

मप्र में विधायकों को वीआइपी पहचान दिलाने की कवायद

रवींद्र कैलासिया, भोपाल

- रेलवे रिजर्वेशन के सॉफ्टवेयर में अलग पहचान की होगी व्यवस्था
- टिकट लेते समय ही विस सदस्य की वीआईपी पहचान चिह्नित हो जाएगी

एक ओर जहां सरकारें वीआइपी संस्कृति समाप्त कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों को रेल यात्रा के लिए रिजर्वेशन में वीआइपी पहचान दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। इससे विधायकों को रेल यात्रा के दौरान अलग से किसी पहचान की जरूरत नहीं होगी, बल्कि रिजर्वेशन के दौरान ही विधायक की पहचान का चिह्न ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा।

कार्ड व्यवस्था पर सहमति : मप्र विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति ने नवंबर में रेल मंत्री पीयूष गोयल से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी। सूत्रों के मुताबिक रिजर्वेशन के लिए कूपन व्यवस्था के स्थान पर कार्ड सिस्टम लागू करने पर जब समिति ने रेल मंत्री से चर्चा की तो उन्होंने इस बारे में सभी राज्यों से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेने की बात रखी। साथ ही कहा कि कार्ड व्यवस्था के लिए सभी राज्यों की सहमति जरूरी है, क्योंकि पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। अन्यथा रेलवे को असुविधा होगी और दो तरह की व्यवस्था से परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं।

रेलमंत्री ने बताया-नई व्यवस्था की जा रही

सूत्र बताते हैं कि रेल मंत्री ने विस समिति को बताया कि वे विधानसभा सदस्यों को रिजर्वेशन, वीआईपी रिजर्वेशन कोटा और ट्रेन में पहचान की समस्या के लिए नई व्यवस्था करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर में ही रिजर्वेशन के समय काउंटर पर कूपन लेते समय विधानसभा सदस्य की पहचान के लिए विशेष चिन्ह अंकित कराया जा रहा है। इस चिन्ह से विधानसभा सदस्य के टिकट पर वीआईपी पहचान अंकित हो जाएगी। इससे रेल यात्रा के प्रतीक्षा सूची में टिकट होने पर वीआईपी रिजर्वेशन कोटे में आवेदन करने तथा ट्रेन में टिकट चैकिंग के दौरान पहचान पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

नागरिकता संशोधन बिल का पंजाब ने किया विरोध

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब के म ख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करते हुए कहा है कि वह इसे विधानसभा में पास नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि यह देश की लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। एक सवाल के जवाब में कैप्टन ने कहा कि प्रस्तावित नागरिकता संशोधन बिल को संसद से पास होने के बाद हमारी विधानसभा में आने दो, वहां हमारे पास दो-तिहाई बहुमत है।

हैदराबाद एनकाउंटर पर कैप्टन ने कहा कि मैं पुलिस द्वारा अपने ऊपर हुए हमले की सूरत में गोली चलाने के हक में हूं, लेकिन अदालतों से बाहर जाकर न्याय देने के खिलाफ हूं। यह देश की संवैधानिक भावना के उलट है। यदि पुलिस वालों पर अपराधी हमला करते हैं तो पुलिस की कार्रवाई जायज होती है। उन्होंने साफ किया कि एनकाउंटर जैसी कोई बात ही नहीं थी। पंजाब की पुलिस को ऐसे मुद्दों के बारे में अच्छी तरह पता है और वह आतंकवादियों, गुंडों व गैंगस्टरों को हथियारों का आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने के लिए कहती है।

बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएबी को चुनावी मुद्दा बनाएगी तृणमूल कांग्रेस

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- तृकां नेतृत्व का दावा-एनआरसी के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक भाजपा को पहुंचाएगा नुकसान
- मुख्यमंत्री ने कहा, मंजूर नहीं धार्मिक आधार पर नागरिकता, लड़ेंगे दूसरा स्वतंत्रता संग्राम

बंगाल में तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (तृकां) ने 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि भाजपा की ओर से पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने के खिलाफ प्रचार पार्टी की हित में रहा और जीत में मददगार साबित हुआ। अब पार्टी की योजना विधानसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को ही तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि आप तैयार रहें, आजादी के 72 साल बाद हम फिर एक आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि धार्मिक आधार पर नागरिकता हमें मंजूर नहीं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पार्टी चुनाव के दौरान उक्त विधेयक के खिलाफ प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसे पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने 'दूसरा स्वतंत्रता संग्राम' करार दिया है। दरअसल, इन नेताओं को लगता है कि आगामी चुनाव में 120 सीटें निर्णायक साबित होंगी, जहां अल्पसंख्यक और शरणार्थी आबादी अच्छी खासी तादाद में है।

बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है, जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं की राय है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के बाद यह नागरिकता संशोधन विधेयक 'बंगाल में भाजपा के ताबूत में आखिरी कील' साबित होगा। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'हम सभी ने देखा है कि लोकसभा चुनावों के केवल छह महीने बाद बंगाल में कैसे माहौल भाजपा के खिलाफ हो गया है। असम में एनआरसी ने उनके खिलाफ काम किया। अब यह नागरिकता संशोधन विधेयक भाजपा को और नुकसान पहुंचाएगा। वह इन दोनों मुद्दों पर जनता के मनोभाव को भांपने में नाकाम रहे हैं। उक्त नेता ने कहा कि हमने भी शरणार्थी कॉलोनियों को नियमित किया, लेकिन इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा। वे (भाजपा सरकार) नागरिकता देने के लिए मानदंड तय कर सकते हैं, लेकिन धर्म कभी भी मानदंड नहीं हो सकता।

...तो ममता करेंगी विधेयक का समर्थन

शुक्रवार को ममता बनर्जी ने कहा था कि वह इस विधेयक का समर्थन करेंगी, अगर हर शरणार्थी को नागरिकता दी जाए, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो। बनर्जी ने कहा था कि हम पहले स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं ले सके, जिससे हमें आजादी मिली, लेकिन हम दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे। हम एनआरसी और सीएबी का विरोध करेंगे।'

मनो ने किया इंटीग्रेडिट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को 38 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर 44 में आइआरसीटीसी बिल्डिंग में बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इस सुविधा वाला गुरुग्राम राज्य का पहला ऐसा शहर बन गया है। इस मौके पर केंद्रीय योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित थे।

वर्तमान में शहर के 160 सरकारी भवनों व पुलिस थानों को फाइबर नेटवर्क के साथ जोड़ा जा चुका है। जो बचे हैं, उन्हें इससे जोड़ा जाएगा। इस सेंटर में ऑनलाइन रियल टाइम एक्सेस, निर्णयों के लिए डाटा का मूल्यांकन और रिपोर्ट, पेपरलेस कार्य, वाई-फाई के साथ हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा के साथ ही विभिन्न कार्यालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा विश्लेषण व निगरानी के लिए सीसीटीवी प्रणाली, यातायात नियंत्रण व प्रबंधन, संपत्ति व भूमि रिकार्ड प्रबंधन, सार्वजनिक यातायात, स्ट्रीट लाइट निगरानी व नियंत्रण, ठोस कचरा प्रबंधन, एसटीपी पानी की गुणवत्ता की निगरानी, पेयजल आपूर्ति की निगरानी, पर्यावरण निगरानी, शहरी सेवा सहयोग केंद्र और मोबाइल एप के माध्यम से नागरिक भागीदारी की भी सुविधा दी गई है ताकि गुरुग्राम को बेहतर स्मार्ट सिटी बनाया जा सके। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी. उमाशंकर ने बताया कि अधिकतम नौ माह के भीतर शहर के सभी सरकारी भवनों को पब्लिक वाई-फाई से सुसज्जित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, नागरिकों को दी जाने वाली सभी नागरिक सेवाओं को एक मंच पर लाकर इस कमांड एवं कंट्रोल सेंटर हेतु एक मोबाइल एप भी विकसित किया गया है ताकि जनता मोबाइल एप के माध्यम से लाइव सुविधा को ले सकें। उन्होंने बताया कि यह एप अभी ट्रायल पर हैं और लेकिन इसे जल्द ही लांच करवाया जाएगा। इस सेंटर की पहुंच बढ़ाने के लिए 358 इंटरसेक्शन प्वांइट को चिह्नित कर योजना बनाई गई हैं और 1200 सीसीटीवी कैमरों को स्थापित किया जाएगा।

रिपोर्ट

अवैध शिकार से जुड़ी घटनाओं पर संसद में दी गई रिपोर्ट से मिली जानकारी, वन्यजीवों के शिकार की घटनाएं अब भी सबसे ज्यादा बंगाल में, 21 बाघों का भी हुआ शिकार

उप्र, महाराष्ट्र में बढ़ा वन्यजीवों का शिकार

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

बाघों की संख्या में बढ़ोतरी कर भारत ने भले ही वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर दुनिया में अपनी साख सुधारी है, बावजूद इसके वन्यजीवों के अवैध शिकार की घटनाओं में वैसी कमी नहीं आई है, जैसे दावे किए गए थे। स्थिति यह है कि 2018 में भी देश में वन्यजीवों के अवैध शिकार की कुल 346 घटनाएं रिपोर्ट हुईं, जो 2017 के मुकाबले थोड़ी ही कम है। 2017 में देशभर में अवैध शिकार के कुल 395 मामले रिपोर्ट हुए थे।

वन्यजीवों के अवैध शिकार को लेकर यह रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले दिनों संसद को सौंपी है। इसके मुताबिक, देश के ज्यादातर राज्यों में वन्यजीवों के अवैध शिकार की घटनाओं में जहां कमी आई है, वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम सहित करीब आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं, जहां ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। इनमें उत्तर प्रदेश अहम है, क्योंकि यहां अवैध शिकार से जुड़े अपराध की घटनाएं 2017 के मुकाबले 2018 में दोगुने से ज्यादा बढ़ी है। 2017 में जहां उत्तर प्रदेश में कुल 16 घटनाएं रिपोर्ट हुई थीं, वहीं 2018 में यह 35 रहीं।

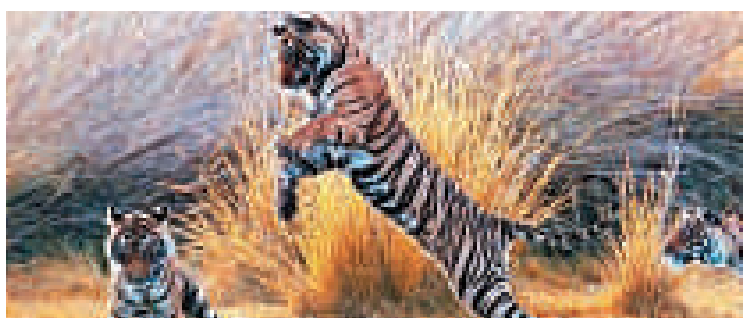

रिपोर्ट में सामने आया है कि 2018 में 21 बाघों का शिकार हुआ। फाइल

वन्यजीवों से जुड़े अपराध में पश्चिम बंगाल फिर से शीर्ष पर है। जहां 2018 में कुल 55 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। हालांकि, इनमें 2017 के मुकाबले थोड़ी कमी जरूर हुई है। 2017 में पश्चिम बंगाल में शिकार से जुड़ी 59 घटनाएं रिपोर्ट हुई थीं।

वन्यजीवों से जुड़े अपराध को लेकर यह हाल तब है, जब सरकार ने इसे लेकर कड़े कानून बना रखे हैं। इसके तहत इनमें प्रयुक्त होने वाले वाहन, उपकरण या हथियार को जब्त करने का प्रावधान भी है। बाघों के संरक्षण को लेकर छेड़े गए अभियान के बीच सरकार ने शिकार की घटनाओं को पूरी तरह से खत्म करने का वादा किया था। बावजूद इसके वर्ष 2018 में 21 बाघों का भी शिकार हुआ।

गौरतलब है कि हाल ही में बाघों को लेकर आए सर्वे में देश में बाघों की कुल संख्या 2967 बताई गई है। इसमें 2014 के मुकाबले करीब 33 फीसद बढ़ोतरी हुई है। वन्यजीवों के शिकार की घटनाओं में 2017 के मुकाबले 2018 में जिन राज्यों में बढ़ोतरी हुई है, उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, असम, गुजरात, पंजाब आदि शामिल हैं।

भारत बचाओ रैली में हरियाणा से शामिल होंगे दस हजार किसान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

नई दिल्ली के लाल किला मैदान में 14 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बचाओ रैली के लिए हरियाणा के कांग्रेसी तैयारी में जुट गए हैं। शनिवार को किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने प्रदेश पदाधिकारियों व जिलाध्यक्षों के साथ रैली को लेकर रणनीति बनाई। प्रदेश से दस हजार किसानों को रैली में पहुंचाने का लक्ष्य है।

मंथन बैठक के बाद किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रधान धर्मबीर और हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के कोआर्डिनेटर प्रीतपाल सिंह के साथ पत्रकारों से बात करते हुए सोलंकी ने कहा कि रैली को सफल बनाने के लिए किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि भारत बचाओ रैली में बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, बिगड़ी कानून व्यवस्था, आर्थिक मंदी सहित अन्य मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि 9 दिसंबर को हरियाणा किसान कांग्रेस नई दिल्ली में पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया जाएगा। एक अन्य प्रस्ताव में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष नाना भाई पटोले को महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी हाई कमान का धन्यवाद किया गया है। बता दें कि रैली को लेकर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद पहले ही प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही तमाम विधायकों और हारे हुए पार्टी प्रत्याशियों की बैठक ले चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस की होने वाली रैलियों में हरियाणा कांग्रेस की हमेशा ही अहम भूमिका रही है। रामलीला मैदान में चाहे सत्ता में रहते हुए कांग्रेस की रैलियां हुईं या फिर सत्ता से बाहर रहते हुए, सभी में एनसीआर में पड़ते गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, झज्जर तक से कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाई जाती है।

1.66 लाख दुष्कर्म के मामले पॉक्सो के तहत लंबित थे मार्च 2018 तक देश के विभिन्न न्यायालयों में। अगस्त, 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 1.61 लाख मामले अब भी लंबित हैं।

सीबीआइ जांच न हुई तो सामूहिक आत्मदाह

चेतावनी ▶ आरोपित पक्ष की महिलाएं पहुंचीं योगी सरकार के मंत्रियों के पास

पीड़िता की मौत के बाद दबाव को लेकर आरोपितों के परिवार में दहशत

जागरण संवाददाता, उन्नाव

दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद गुनहगारों पर कार्रवाई को लेकर बढ़े दबाव से आरोपित परिवार सहमे हैं। सियासी दलों की सक्रियता के बाद आरोपितों के बचाव में परिवार की महिलाएं उतर आई हैं। उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को रोकना चाहा, वह नहीं रुकीं तो पूर्व सांसद से सीबीआइ जांच की मांग उठाई। इसके बाद प्रदेश सरकार के मंत्रियों के काफिले को रोककर प्रदर्शन किया। सीबीआइ जांच न होने पर सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी।

शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा पीड़िता के घर पहुंची तो आरोपितों के स्वजन भी अपनी बात रखने के लिए दो सौ से ज्यादा महिलाएं लेकर पहुंच गए। वहां प्रियंका का काफिला रोकने के लिए महिलाएं सड़क पर लेट गईं। सुरक्षाकर्मियों ने बात कराने का भरोसा देकर उनको किनारे किया। इस बीच प्रियंका का काफिला निकल गया। प्रियंका के कार के शीशा भी न खोलने पर महिलाएं हंगामा करने लगीं तो पीछे से आ रही पूर्व सांसद अन्नू टंडन को अपनी कार रोकनी पड़ी। महिलाओं ने उनसे कहा कि मामले की सीबीआइ जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। उन्होंने उनकी बात प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। कहा कि कोशिश करेंगे कि किसी बेगुनाह को सजा न मिले। आरोपित उमेश बाजपेयी की बहन प्रिया व अंशिता, शिवम की मां सावित्री, शुभम की मां सरोज के अलावा सियादुलारी, शिवराना ने कहा कि यदि सरकार सीबीआइ जांच का आदेश नहीं देगी तो वे सामूहिक आत्मदाह कर लेंगी।

मंत्रियों का काफिला पीड़िता के घर से आगे बढ़ा तो रास्ते में खड़ी महिलाओं ने सहकारिता मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और प्रभारी मंत्री कमला रानी वरुण का काफिला रोककर प्रदर्शन किया तथा सीबीआइ जांच की मांग की। हर नेता को रोकने की कोशिश करने पर पुलिस को उन्हें धकियाना पड़ा लेकिन सहकारिता मंत्री ने उनकी बात सुनी।

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का पार्थिव शरीर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से शनिवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव स्थित उनके पैतृक गांव लाया गया। प्रेट्र

योगी ने कहा–मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर दिलाएंगे सजा

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कहा कि बालिका की मौत अत्यंत दुखद है। सरकार मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाएगी।

25 लाख का चेक देने पहुंचे मंत्रियों का विरोध : मुख्यमंत्री के निर्देश पर गांव पहुंचे सहकारिता मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिले की प्रभारी मंत्री कमल रानी वरुण व मरहम लगाने पहुंचे सांसद साक्षी महाराज को गांव वालों का जोरदार विरोध झेलना पड़ा। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 25 लाख रुपये का चेक दिया।

शव पहुंचा गांव, पिता बोले-हैदराबाद जैसा इंसाफ दो, वरना घर पर बम गिरवा दो : जिंदा जलाई गई दुष्कर्म पीड़िता की मौत से गम और गुस्से का उबाल फूट पड़ा है। शनिवार रात करीब नौ बजकर आठ मिनट पर उसका शव गांव पहुंचा तो रोते-बिलखते उसके भाई और पिता ने चीख-चीखकर हैदराबाद जैसा इंसाफ देने की मांग की। यह तक कहा कि यदि इंसाफ नहीं दे सकते तो घर पर बम गिरवाकर सबको मौत दे दो। पिता बोले, बिटिया का मुंह तक आखिरी बार नहीं देख पाए। पैसे वालों ने आवाज दबा दी। हम तो सालभर से सताए जा रहे थे, तब किसी ने एक न सुनी। भाई का कहना था कि बहन अग्निपरीक्षा तो पहले ही दे चुकी है, इसलिए उसे जलाएंगे नहीं दफनाकर समाधि बनाएंगे। रात ज्यादा हो जाने के कारण बिटिया को रविवार सुबह घर से करीब एक किलोमीटर दूर दफनाया जाएगा।

> मुख्यमंत्री, डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह हटाए जाएंगे, तभी प्रदेश सुधरेगा। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए डायल 100 जैसी सुविधा दी। उससे न जाने क्या दुश्मनी थी कि सरकार ने बदलकर 112 कर दिया। उन्नाव दुष्कर्म के आरोपितों पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, क्योंकि वह भाजपा से जुड़े हैं।
> **-अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष**

> न्याय की तलाश में प्रयासरत पीड़ित महिलाओं की हत्या करने व उन्हें जिंदा जलाने की दर्दनाक घटनाओं ने सभी को झकझोर दिया है। पुलिस प्रशासन अपराधियों को हर प्रकार का संरक्षण दे रहा है। आरोपितों को सख्त सजा दिलाने के बजाए उनकी आवभगत ही करता रहता है।
> **-मायावती, बसपा प्रमुख**

निर्भया की वकील लड़ेंगी उन्नाव पीड़िता की लड़ाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया को न्याय दिलाने वाली सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट सीमा समृद्धि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के लिए भी इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगी। शनिवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफदरजंग अस्पताल की फॉरेंसिक यूनिट के प्रमुख एमके वाही के नेतृत्व में डॉक्टरों के पैनल ने पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम किया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के साथ ही बिसरा सुरक्षित रख लिया गया है।

सफदरजंग अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचीं सीमा ने कहा कि उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने के लिए वह निशुल्क पैरवी करेंगी। इसके लिए वह यूपी पुलिस और पीड़िता के परिवार से संपर्क कर रही हैं।

भाई ने की आरोपितों को फांसी देने की मांग : अस्पताल में मौजूद मृतका के बड़े भाई ने कहा, 'मैंने बहन से वादा किया था कि उसे बचा लूंगा ताकि वह आरोपितों को मौत की सजा पाते देख पाती। लेकिन, बहुत दुख है कि बहन अब जीवित नहीं है।' उन्होंने कहा कि बहन ने पहले ही अग्निपरीक्षा पास कर ली है। इसलिए वह बहन का पार्थिव शरीर धरती मां की गोद में रखेंगे। आरोपितों को फांसी से कम सजा मिली तो यह मेरी बहन के साथ अन्याय होगा।

दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद लोगों में गम और गुस्से का गुबार दिखा। पोस्टमार्टम के समय यहां पर विरोध प्रकट करने के लिए दिल्ली के कई इलाकों से लोग पहुंचे थे। इसी दौरान एक महिला ने अपनी 10 साल की बेटी के सिर पर बोतल से पेट्रोल उड़ेल दिया। वह बेटी को आग लगाने ही वाली थी कि पुलिस ने उसे दबोच लिया। महिला का कहना था कि आज देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बच्ची से कोई हैवान दुष्कर्म करे और उसे आग के हवाले कर दे, इससे अच्छा तो यह है कि मैं आज ही खुद बच्ची को जला दूं। हालांकि पुलिस सूत्रों ने महिला को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया।

अनु दुबे भी पहुंचीं अस्पताल

पिछले दिनों संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर चर्चा में आई अनु दुबे भी सफदरजंग अस्पताल पहुंची। दैनिक जागरण से बातचीत में अनु ने कहा कि एक महिला अगर अपनी बच्ची को पेट्रोल जलाकर मारना चाहती है तो सरकार को इसका मर्म समझना चाहिए। आम लोगों को कानून व सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा है। सरकार को दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न के मामले में त्वरित व निष्पक्ष न्याय प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए। अनु ने कहा कि हैदराबाद मामले में जो हुआ, वह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी मां भी मुझे मना करती हैं। वह कहती हैं हैवानों के खिलाफ आवाज न उठाओ वरना वे कहीं तुम्हें भी अपना शिकार न बना लें। अगर मुझ पर कभी हमला हुआ तो कौन करेगा हमारी मदद।

बिफरी दुष्कर्म पीड़िता, क्या यहीं जलकर जान दे दूं

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे का वक्त। स्थान, प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यालय। नवाबगंज क्षेत्र के एक गांव में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़ित किशोरी एसपी गंगापार एनके सिंह से मिलकर बाहर निकलने के बाद बिफर पड़ी। रोते हुए पुलिस वालों के सामने अपने वकील से बोली, 'क्या चाहते हैं ये पुलिस अधिकारी, यहीं आग लगाकर जान दे दूं क्या। लगता है पुलिस वाले यही चाहते हैं। तीन महीने से चक्कर काट रही हूं इन लोगों का। रोज धमकी दी जा रही है कि सुलह कर लो वरना जान से मार दिया जाएगा।'

लगता है कि उन्नाव और हैदराबाद की घटनाओं के बाद भी प्रयागराज पुलिस गंभीर नहीं है। नवाबगंज थाने में 30 अगस्त को 15 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा लिखा गया। आरोप है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के चार लोग घर से असलहे के बूते उसे उठा ले गए थे। मगर पुलिस ने कह दिया कि पेशबंदी में केस लिखवाया गया है। पीड़िता को लेकर उसके पिता कई बार एडीजी जोन, डीआइजी व एसएसपी से गुहार लगा चुके हैं। धमकियों से घबराकर परिवार कौशांबी और फतेहपुर में रहने लगा है।

स्मृति ईरानी बोलीं, मृत्युदंड से ही लगेगी दुष्कर्मियों पर लगाम

नईदुनिया, इंदौर

केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ शब्दों में कहा है कि दुष्कर्मियों पर लगाम सिर्फ मृत्युदंड जैसी कठोरतम सजा से ही लगाई जा सकती है। इसका प्रावधान कानून में पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को महिलाओं का आदर और सम्मान करना सिखाएं। बच्चों के सामने महिलाओं की ऐसी छवि बनाएं कि वे खुद उन्हें सम्मान की नजर से देखें।

मध्य प्रदेश की व्यावसायिक व सांस्कृतिक नगरी इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को रोटरी क्लब की ओर से आयोजित समारोह में ईरानी ने उक्त राय व्यक्त की। हैदराबाद और उन्नाव दुष्कर्म कांड के बाद पीड़िताओं की हत्या के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इन दिनों दुष्कर्मियों पर सख्त से सख्त सजा के प्रावधान को लेकर चर्चा हो रही है। सरकार ने पहले ही इस अपराध पर मृत्युदंड तक का प्रावधान किया है। उनके लिए इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मीडिया, फिल्म और साहित्य भी ऐसे अपराधों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। अभिभावक के तौर पर यह हमेशा देखना चाहिए कि बच्चे के सामने हम महिलाओं की कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं। समाज के सामने चाइल्ड पोर्नोग्राफी नई चुनौती के रूप में उभर रही है। यह अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को महिलाओं के प्रति अच्छे व्यवहार की शिक्षा दें। देश में दुष्कर्म के मामलों की तेज गति से निपटान के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं। दुष्कर्म के मामलों में अदालतों से सजा पाने वाले अपराधियों पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस भी बनाया जा रहा है।

दो पुरुष सांसद मेरी ओर बढ़े थे : एक सवाल पर ईरानी ने कहा कि वे संसद में महिला उत्पीड़न पर बोल रही थीं तो दो पुरुष सांसद उनकी तरफ बढ़े। इसकी वजह बस यही थी कि मैं बोल रही थी। क्या महिलाओं के लिखने और बोलने से भी दूसरी महिलाओं का उत्पीड़न होता है?

सत्ता में बैठे व्यक्ति का हिंसा व निरंकुश शासन में यकीन : राहुल

वायनाड, एजेंसियां : हैदराबाद की बेटी के साथ दरिंदगी से देश में उबाल अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बर्बरता की शिकार हुई उन्नाव की बेटी की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के लिए सीधे-सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अपने संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा में राहुल ने कहा कि आज देश में महिलाओं, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसका प्रमुख कारण यह है कि देश में जो व्यक्ति सत्ता में है वह हिंसा और निरंकुश शासन में यकीन करता है।

राहुल गांधी ने कहा कि आप देख रहे हैं देश भर में हिंसा बढ़ गई है और कानून का राज नहीं रह गया है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म, उत्पीड़न और छेड़खानी की खबरें रोज पढ़ने को मिल रही हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है और उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ हिंसा और मारपीट की खबरें आ रही हैं। आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहा है उनकी जमीन छीनी जा रही है। इस सबके लिए सत्ता में शीर्ष पर बैठा व्यक्ति है। अगर आप हिंसा और नफरत में यकीन नहीं करते हैं तब उम्मीद कर सकते हैं कि देश में हिंसा और नफरत नहीं फैलेगी।

उन्होंने कहा कि यह दुनिया कभी नई दिशा, महात्मा गांधी, अहिंसा, प्यार और अपनत्व के लिए भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती थी। आज दुनिया कह रही है कि हमें अपनी महिलाओं के साथ व्यवहार करने नहीं आता, हम अपनी महिलाओं और बच्चियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा हो भी क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में जब भाजपा विधायक दुष्कर्म के मामले में आरोपी होता है तो प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द नहीं बोलते। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि दुनिया में भारत की पहचान दुष्कर्म की राजधानी के तौर पर होने लगी है।

इससे पहले, 'बेटी को न्याय दो' हैशटैग से ट्वीट कर राहुल ने उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस घटना से वह स्तब्ध और दुखी हैं। पीड़ित परिवार के प्रति उनकी पूरी संवेदना है। बता दें कि उन्नाव में 23 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को पांच दिसंबर को तड़के जला दिया गया था। दिल्ली के सफदरजंग अस्पतालमें शुक्रवार की देर रात को उसने दम तोड़ दिया।

'दुष्कर्म की राजधानी बनता जा रहा उप्र'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मौत पर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश दुष्कर्म की राजधानी बनता जा रहा है। कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि एक और बेटी ने न्याय और सुरक्षा की आस में दम तोड़ दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। सरकार इस मामले में पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए।

उन्होंने कहा कि योगी सरकार को आश्वासन देने की जगह कानून-व्यवस्था को सुधारने की दिशा में सख्त कदम उठाना चाहिए। उन्होंने पुलिस से पूछा कि चार महीने तक इस मामले में केस क्यों नहीं दर्ज किया गया और आरोपितों को जमानत कैसे मिल गई। मुख्यमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के भरोसे पर श्रीनेत ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।

समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी उन्नाव की पीड़िता को तुरंत न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। हैदराबाद मामले पर सिब्बल ने कहा कि अगर यह पाया जाता है कि यह एनकाउंटर फर्जी था, तो यह बहुत ही गंभीर मामला है।

'पब्लिक सब जानती है'

एएनआइ के ही मुताबिक पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भी हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'किशोर कुमार का लोकप्रिय गीत है, 'ये पब्लिक है ये सब जानती है। लोग इतने भोले नहीं हैं।'

मानवाधिकार आयोग ने शुरू की हैदराबाद मुठभेड़ की जांच

हैदराबाद, प्रेट्र : मानवाधिकार आयोग ने हैदराबाद मुठभेड़ की जांच शुरू कर दी है। आयोग की सात सदस्यीय टीम ने शनिवार को उस स्थान का दौरा किया, जहां महिला चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे जला देने के चार आरोपितों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। हालांकि, पुलिस का कहना है कि आरोपितों ने पहले पुलिस पर हमला किया और जवाबी गोलीबारी में चारों मारे गए। मानवाधिकार आयोग के दल में फोरेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

आयोग की टीम ने सबसे पहले महबूबनगर जिले के एक अस्पताल में रखे आरोपितों के शव की जांच की। इसके बाद टीम 50 किलोमीटर दूर चट्टनपल्ली गांव भी गई, जहां महिला चिकित्सक का जला हुआ शव मिला था और आरोपितों का एनकाउंटर किया गया। शमशाबाद क्षेत्र के डीसीपी एन प्रकाश रेड्डी ने कहा कि टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और वह मामले की जांच कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर : सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर हैदराबाद मुठभेड़ की जांच सर्वोच्च अदालत के सेवानिवृत न्यायाधीश की निगरानी में एसआइटी से करवाने की मांग की गई है। याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने मुठभेड़ में मारे गए हर आरोपित के परिवार को 20-20 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग की है। इसके अलावा एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस चलाने की मांग भी की गई है। महिला पशु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपितों के खिलाफ पुलिसकर्मियों पर 'हमला' करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपितों के खिलाफ आइपीसी की धारा 307, धारा 176 और भारतीय शस्त्र कानून की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

आयोग की टीम ने अस्पताल में रखे आरोपितों के शव की जांच की

उस जगह का भी दौरा किया, जहां पुलिस ने एनकाउंटर किया था

तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के शादनगर में महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के चारों आरोपितों को एनकाउंटर में ढेर किए जाने के बाद शनिवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों ने घटनास्थल का दौरा किया। प्रेट्र

एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दो याचिका

नई दिल्ली, एजेंसियां : हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दो जनहित याचिकाएं दायर की गईं। इनमें एनकाउंटर की एसआइटी से जांच और उसमें शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की गई है। शुक्रवार तड़के हुए एनकाउंटर में पुलिस ने महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या के चारों आरोपितों को मार गिराया था। अगले हफ्ते इन याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है।

जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में एसआइटी से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का भी आग्रह किया गया है। याचिकाओं में पुलिस एनकाउंटर को न्यायेतर हत्या बताया गया है।

राजघाट से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उन्नाव पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे लोगों ने इंडिया गेट से राजघाट तक कैंडल मार्च निकाला। राजघाट पर लोग बेकाबू हो गए। इन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी।

प्रदर्शन में दिल्ली महिला आयोग, एनएसयूआइ समेत कई संगठनों ने हिस्सा लिया। कैंडल मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर ही मोमबत्ती लगा कर विरोध जताया। इस कारण घंटों तक यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जब राजघाट से इंडिया गेट की तरफ शहीद पार्क के पास बैरिकेड लगा देखा तो वे उग्र हो गए और उसको लांघने का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस को पानी की बौछार कर उन्हें रोकना पड़ा। प्रदर्शन के कारण दिल्ली गेट से आइटीओ आने वाले बहादुर शाह जफर मार्ग सड़क की एक लेन को बैरिकेड लगा बंद किया गया। जिसके चलते दिल्ली गेट से आइटीओ आने वाले वाहनों को रिंग रोड की तरफ डायवर्ट किया गया।

स्वाति बोलीं-एक माह में उन्नाव कांड के दोषियों को मिले फांसी : दुष्कर्म के दोषियों को छह माह में फांसी देने के लिए मजबूत कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद शनिवार को छठे दिन भी आमरण अनशन पर रहीं। स्वाति ने उन्नाव पीड़िता के लिए 5 मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि दी और दुख जाहिर करते हुए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तुरंत मामले को फास्ट ट्रैक के जरिये दोषियों को एक माह के भीतर फांसी की सजा दिलवाने की अपील की। उनको समर्थन देने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व सांसद शरद यादव भी राजघाट पहुंचे। वहां पहुंचीं निर्भया की मां ने कहा कि आज 7 साल बाद भी संसद सड़क और न जाने कहां-कहां हाथ जोड़ने के बाद भी उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला। स्वाति के अनशन को समर्थन देने के लिए सोशल मीडिया पर 'खाली थाली अनशन' के नाम से एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है।

दुष्कर्मियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर निकाले गए कैंडल मार्च के दौरान दिल्ली गेट के करीब शहीद स्मारक के पास आंदोलनकारियों के उपर पानी की बौछार करते पुलिस। संजय

दो टूक

राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्यपीठ के नए भवन का रामनाथ ने किया उद्घाटन, कोविंद ने कहा– बहुत महंगी हो गई है न्याय प्रणाली

राष्ट्रपति की राय, न्याय सस्ता व सर्वसुलभ होना चाहिए

संवाद सूत्र, जोधपुर

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि न्याय प्रणाली बहुत महंगी हो गई है। न्याय सस्ता व सर्वसुलभ होना चाहिए। राष्ट्रपति राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्यपीठ के नए भवन के उद्घाटन अवसर पर जोधपुर में बोल रहे थे।

राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान ने सत्य की रक्षा करने का महत्वपूर्ण दायित्व न्यायपालिका को सौंपा है। पुराने दौर में राजा-महाराजाओं से न्याय मांगने के लिए कोई भी व्यक्ति उनके निवास के बाहर लगी घंटी को बजा सकता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। न्याय प्रणाली बहुत महंगी हो चुकी है। गरीब व्यक्ति के लिए हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। प्रत्येक नागरिक को सस्ता न्याय सुलभ कराने की दिशा में सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायधीशों से आग्रह किया कि यहां दिए जाने वाले फैसलों की जानकारी हिंदी में भी उपलब्ध कराई जाए। कार्यक्रम के पश्चात कोविंद जोधपुर के पूर्व नरेश गज सिंह के निमंत्रण पर ऐतिहासिक मेहरानगढ़ फोर्ट भी गए।

जाति-धर्म न देखें डॉक्टर : उधर, एम्स के दीक्षा समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टरों को किसी जाति-धर्म को नहीं देखना है। हर मरीज का इलाज साथी समझकर करना चाहिए। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि चिकित्सकों को शपथ को औपचारिक तौर पर नहीं लेना चाहिए।

राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेंध : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुरक्षा में उस समय सेंध लग गई, जब एक युवक उनसे मिलने जोधपुर के सर्किट हाउस की दीवार फांदकर अंदर पहुंच गया। सुरक्षाकर्मियों की नजरों से बचता हुआ वह राष्ट्रपति कोविंद तक पहुंचा और उनके छूए। युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उसकी पहचान अजमेर निवासी दिनेश के रूप में हुई। बताया गया है कि वह मानसिक रूप से परेशान है। मामले में सर्किट हाउस में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर गाज गिरने के साथ आधा दर्जन से अधिक सिपाहियों को निलंबित करने की सूचना है।

मेहरानगढ़ फोर्ट की ऐतिहासिकता से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (मध्य में) और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा (बाएं) को रूबरू करवाते पूर्व नरेश गज सिंह (दाएं)। नईदुनिया

राजनीति में लगता है दो नंबर का पैसा

हाई कोर्ट के नए भवन के उद्घाटन अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति में दो नंबर का पैसा लगता है। ऐसे में भ्रष्टचार कैसे कम हो सकता है। जब तब दलों को दो नंबर का पैसा मिलता रहेगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। उन्होंने राजनीति को दो नंबर का खेल तक कहा। गहलोत ने कहा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता कैसे लाई जा सकती है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे 45 साल से राजनीति में हैं और अच्छी तरह से जानते है कि राजनीति की शुरुआत कैसे होती है। चुनाव की शुरुआत ही ब्लैकमनी से होती है। ऐसे में ब्लैकमनी लेकर चुनाव जीतने वालों से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे देश से भ्रष्टाचार को समप्त करेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे इस मामले में स्वप्रेरणा से एक अपील कर उसकी सुनवाई करें।

केरल में दुष्कर्म के आरोपित की भीड़ ने की पिटाई

पलक्कड़, प्रेट्र : केरल के वायलार में दो नाबालिग दलित बहनों से दुष्कर्म और उन्हें खुदकशी के लिए मजबूर करने के एक आरोपित की शनिवार को भीड़ ने पिटाई कर दी। इस मामले में चार लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। इनमें तीन को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपित की मां का कहना है कि हमला करने वाले संघ परिवार से जुड़े हैं।

दुष्कर्म मामले के तीसरे आरोपित एम. मधु को हाल ही में कोर्ट ने बरी किया है। पलक्कड़ के पुलिस प्रमुख ने बताया, 'मधु जब कोयंबटूर से अपने घर पहुंचा तो एक समूह ने उसे दुष्कर्मी कहा। मधु ने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दीं और उनसे भिड़ गया। इस पर भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।'

पलक्कड़ जिले के वायलार में दो सगी बहनों से दुष्कर्म व उनकी मौत के मामले में सरकार ने हाल ही में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। दुष्कर्म पीड़ित 13 वर्षीय किशोरी 13 जनवरी 2017 को अपने घर में फांसी से लटकती हुई पाई गई थी। इसके 52 दिनों बाद उसकी नौ वर्षीय छोटी बहन भी फंदे से लटकती हुई पाई गई थी।

पुलिस ने इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक को इसी साल सितंबर में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने तीन अन्य को 25 अक्टूबर को बरी कर दिया। पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल अफेंस) एक्ट कोर्ट ने आरोपितों को बरी करते हुए जांच टीम को फटकार लगाई थी और कहा था कि वह वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही।

वायलार में नाबालिग दलित बहनों से दुष्कर्म और उन्हें खुदकशी के लिए मजबूर करने के मामले में था नामजद

96 प्रशिक्षित जेंटलमैन कैडेट अधिकारी के रूप में सेना में शामिल हुए। इनमें टेक्निकल एंट्री स्कीम और स्पेशल कमीशन ऑफिसर के कैडेट लेफ्टिनेंट बने हैं। इन सभी ने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, गया में प्रशिक्षण हासिल किया है।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 8 दिसंबर 2019

पाकिस्तान जैसे पड़ोसी से निपटने को तैयार रहना होगा : राजनाथ

कड़ा प्रहार ▶ कहा, पड़ोसी मुल्क ने आतंकवाद को अपनी राष्ट्र नीति बना लिया है

जागरण संवाददाता, देहरादून

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी राष्ट्र नीति बना लिया है। वहां चरमंपथी तत्व इतने मजबूत हैं कि राजनीति के केंद्र में बैठे लोग उनके हाथों की कठपुतलियों से ज्यादा कुछ नहीं लगते। हमें पाकिस्तान जैसे पड़ोसी से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। चीन पर टिप्पणी करते हुए राजनाथ ने कहा कि भारत और चीन की क्षेत्रीय अवधारणाएं एक-दूसरे से अलग हो सकती हैं, लेकिन चीन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बाकी दुनिया के साथ खड़ा है।

शनिवार को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में आयोजित शानदार पासिंग आउट परेड के बाद 306 युवा अधिकारी भारतीय सेना में शामिल हुए। नव सैन्य अफसरों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सेवा एवं शांति का संदेश दुनिया तक पहुंचाएं। कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत की कभी भी अतिरिक्त क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं नहीं रही हैं। हमने दुनिया में किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। किसी की एक इंच भूमि भी भारत के कब्जे में नहीं है। इसके बावजूद सीमाओं पर ऐसे खतरे मंडराते रहते हैं जहां आपको वीरता के साथ विवेक की भी जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि विचित्र पड़ोसी है, सुधार के रास्ते पर चलने को तैयार ही नहीं है। हमारे साथ उसने चार लड़ाइयां लड़ीं और हर बार मुंह की खायी, पर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता।

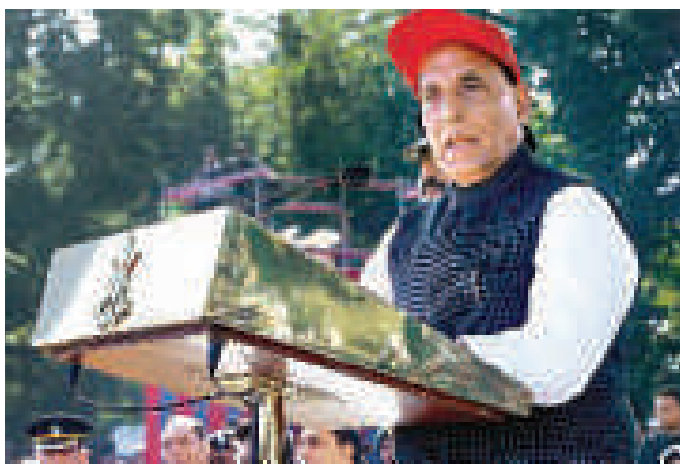

देहरादून में शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी में दीक्षा परेड के बाद नव सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एएनआइ

रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक मल्टी प्रोम्प्ट स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद सदा सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है यह आज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने 9/11 और 26/11 की घटना देखी है। आज किसी भी सभ्य देश की आतंकवाद के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। दुनिया जानती है कि 26/11 को अंजाम देने वाले संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लोग पाकिस्तान में बैठे हैं। मुम्बई हमले में जो 166 बेगुनाह मारे गए, उनके परिवार को उस दिन न्याय मिलेगा जिस दिन 26/11 को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।

चीन के साथ संबंधों पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमांकन कार्य लंबे समय से लंबित होने के चलते चीन के साथ सीमा को लेकर कुछ मतभेद जरूर हैं। इस स्थिति में उत्तरी व पूर्वी सीमा पर सेना को अक्सर वीरता के साथ ही विवेक से भी काम लेना पड़ता है। इसका परिचय भारतीय सेना ने कई बार दिया है। जब डोकलाम में एक अलग परिस्थिति बनी तो सेना ने मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय देने में भी परहेज नहीं किया। नव सैन्य अधिकारियों को भविष्य के खतरों से आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर वॉर एक बड़ी चुनौती बन रहा है। ऐसी-ऐसी चालें सामने आएंगी कि आपको सोचना पड़ेगा कि अस्त्र-शस्त्र का इस्तेमाल कहां और किस रूप में किया जाए। ऐसे में साइबर वॉर में भी महारत हासिल करनी होगी।

देश को मिले 306 युवा सैन्य अफसर : भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक बनेंगे हम। भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में इस गीत पर कदमताल करते जेंटलमैन कैडेट ड्रिल स्क्वायर पहुंचे, तो लगा कि कोई विशाल सागर उमड़ आया है। शनिवार को आइएमए की ड्रिल स्क्वायर में अंतिम पग भरते ही 306 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 71 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए।

इन्हें मिले सम्मान

स्वार्ड ऑफ ऑनर व स्वर्ण पदक	विनय विलास गरड़
रजत पदक	पीकेंद्र सिंह
रजत पदक (टीजी)	शिवराज सिंह
कांस्य पदक	ध्रुव मेहला
सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट	कुएंजंग वांगचुक भूटान
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर	केरन कंपनी

वतन की रक्षा के लिए समर्पित जम्मू-कश्मीर के युवा

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▶ विभिन्न जिलों के 404 युवा सेना में शामिल, परेड में दिखा जोश

▶ ले. जनरल ढिल्लो ने युवाओं को निस्वार्थ भाव से देश सेवा करने के लिए कहा

नए जम्मू-कश्मीर के युवा जब वतन की हिफाजत के लिए शपथ ले रहे थे तो उनका जोश हिलोरे मार रहा था। परिजनों की खुशी की ठिकाना नहीं था। भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। मौका था जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों के 404 युवाओं के सेना में शामिल होने का। जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनने के बाद पहली बार हुई पासिंग आउट परेड में नवारक्षकों ने देश के लिए मर मिटने की कसम खाई।

पासिंग आउट परेड श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र रंगरेट में जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के रेजीमेंटल सेंटर में हुई। इसमें चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो मुख्यातिथि थे। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि 11 महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद 404 युवा सेना में शामिल हुए हैं। युवाओं को निशानेबाजी सहित हर प्रकार की ट्रेनिंग दी गई।

लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो ने सभी युवाओं को मुबारकबाद देते हुए निस्वार्थ भाव से देश सेवा करने के लिए कहा। इस मौके पर युवाओं ने शानदार परेड की, जिसकी सलामी जीओसी ढिल्लो ने ली। परेड के बाद उन्होंने जब देश सेवा की कसम खाई तो पूरा क्षेत्र उनके जोश से गूंज रहा था। उनका साथ मैदान में बैठे उनके परिजन भी दे रहे थे।

इलियास की बहादुरी को सलाम : पॉसिंग आउट परेड में मौजूद सेना से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए इलियास की बहादुरी को हर किसी ने सलाम किया। वह सेना से सेवानिवृत्त होने के बावजूद अब भी पहले की तरह ही लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोर कमांडर ने सेवानिवृत्त कैप्टन इलियास अहमद को सम्मानित भी किया। कैप्टन इलियास को हिमस्खलन में लोगों की जान बचाने का विशेषज्ञ भी माना जाता है। इलियास को दो सेना मेडल मिलने के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्रशंसा पत्र पांच बार मिल चुका है। वह सेवानिवृत्त होने के बावजूद अब भी जवानों के साथ बचाव कार्य में पहले की तरह भाग लेते हैं। हाल ही में टंगडार में हुए हिमस्खलन में उन्होंने एक जवान को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी।

जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों के 404 युवा शनिवार को सेना की जम्मू-कश्मीर लाइट इंफेंटरी रेजीमेंट का हिस्सा बन गए। श्रीनगर में आयोजित पासिंग आउट परेड में जब इन युवाओं ने गरजती आवाज में देश के लिए मर मिटने की शपथ ली तो हर कोई गर्व से भर गया। इस मौके पर मौजूद परिजनों ने अपने लाडलों को सैन्य वर्दी में देख गले लगा लिया। कामरान रशीद बट

न्यूज गैलरी

तीन लाख से भरा एटीएम ले भागे चोर

नागपुर : महाराष्ट्र के नागपुर जिले के एक गांव से शुक्रवार सुबह चोर लगभग तीन लाख रुपये से भरा इंडियन ओवरसीज बैंक का एटीएम ले उखाड़ ले गए। क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक चोरों ने सबसे पहले एटीएम का कनेक्शन बैंक के सर्वर से काटा और फिर अपने साथ लाए वाहन में लादकर एटीएम ले गए। पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे भी हरियाणा के मेवात जिले के उसी गैंग का हाथ हो सकता है जिसने कुछ दिनों पहले एक और एटीएम को चोरी करने का असफल प्रयास किया था। पुलिस का कहना है कि वह जल्द ही वारदात को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (प्रेट्र)

केरल हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की सुरक्षा वापस ली गई

कोच्चि : केरल हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और राज्य की सत्तारूढ़ माकपा नीति सरकार के मुखर आलोचक बी केमल पाशा को दी गई सुरक्षा शनिवार को अचानक वापस ले ली गई। यह फैसला गृह सचिव के स्तर से शुक्रवार को लिया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा कि उनसे सुरक्षा तब वापस ली गई जब केरल का आइएस गुट उनको धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में एक बार फिर विचार करना चाहिए। (प्रेट्र)

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहन का निधन

मुजफ्फरनगर : फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहन शायमा तमशी सिद्दीकी का ब्रेस्ट कैंसर के कारण निधन हो गया। शायमा पुणे के अस्पताल में भर्ती थीं। अभिनेता की बहन की मृत्यु की खबर से कस्बे में शोक छा गया। नवाजुद्दीन के छोटे भाई अयाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि शनिवार सुबह करीब तीन बजे अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी बहन ने अंतिम सांस ली। वह पिछले करीब आठ साल से ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी शूटिंग के लिए अमेरिका में हैं। बहन की मृत्यु की खबर पाते ही वह मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना आने के लिए वहां से रवाना हो गए हैं। उनके छोटे भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी शायमा के शव को लेकर पुणे से बुढ़ाना आ रहे हैं। शायमा की शादी बीते वर्ष 26 जनवरी को सहारनपुर के रहने वाले फैसल के साथ हुई थी। शायमा पति के साथ दिल्ली में रह रही थीं। शायमा को रविवार सुबह आठ बजे सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा, वहीं नवाजुद्दीन रविवार देर रात तक बुढ़ाना पहुंच पाएंगे। (जासं)

13 से 16 तक विजय दिवस समारोह मनाएगी सेना

जागरण संवाददाता, कोलकाता

1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में होगा आयोजन

▶ बांग्लादेशी मुक्ति योद्धाओं का 72 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल समारोह में लेगा हिस्सा

1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय की ओर से 13 से 16 दिसंबर तक कोलकाता में विजय दिवस समारोह मनाया जाएगा। शनिवार को फोर्ट विलियम स्थित मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूर्वी कमान के एमजीजीएस मेजर जनरल एनडी प्रसाद ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि 1971 में मिली जीत भारतीय सेना व पूर्वी कमान के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं के साथ मिलकर पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उन्होंने बताया कि कोलकाता में 13 से 16 दिसंबर तक विजय दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस बार समारोह में बांग्लादेश का 72 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा, जिसमें 30 मुक्ति योद्धा व उनके परिवार के सदस्यों के अलावा वहां के सेना के अधिकारी होंगे। यहां चार दिनों तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में वे हिस्सा लेंगे।

मेजर जनरल प्रसाद ने बताया कि 13 दिसंबर को प्रिंसेप घाट पर मिलिट्री बैंड कंसर्ट से समारोह की शुरुआत होगी। इसे आम लोग भी देख सकेंगे। वहीं, 14 व 15 दिसंबर को आरसीटीसी ग्राउंड में भव्य मिलिट्री टैटू का आयोजन होगा, जिसमें सेना के जांबाज हैरतअंगेज प्रदर्शन कर अपनी शौर्य का परिचय देंगे। इसमें हेलीकॉप्टर शो, घोड़ा दौड़, डॉग शो, मार्च पास्ट, मोटरसाइकिल करतब आदि का प्रदर्शन कर पराक्रमी योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस भव्य कार्यक्रम को दोनों दिन आम लोग भी देख सकेंगे, जिसका उन्हें सालभर इंतजार रहता है। वहीं, 15 दिसंबर को फोर्ट विलियम स्थित अलबर्ट एक्का ऑडिटोरियम में मुक्ति योद्धाओं व 1971 युद्ध में भाग लेने वाले सेना के पुराने युद्धाओं के बीच मुलाकात व संवाद होगा। 15 दिसंबर को रेड रोड पर टाटा स्टील मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं, 16 दिसंबर को फोर्ट विलियम में विजय स्मारक पर 1971 के वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ समारोह का समापन होगा।

पृथ्वी पर बांग्लादेश का सबसे सच्चा दोस्त है भारत : बशीर उद्दीन

इस मौके पर कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के कौंसुलर मोहम्मद बशीर उद्दीन ने कहा कि 1971 के युद्ध के लिए बांग्लादेश हमेशा भारत व भारतीय सेना का ऋणी रहेगा। इस युद्ध में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों ने अपना जीवन बलिदान कर बांग्लादेश को आजाद करवाया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर बांग्लादेश का सबसे सच्चा दोस्त भारत है। हम भारत के साथ हमेशा मधुर संबंध बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि 1971 में करीब एक करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को बंगाल में शरण मिली थी और यहां के लोगों ने खाना-पानी से लेकर सबकुछ उन्हें दिया था। बशीर ने कहा कि भारत के साथ हर क्षेत्र में हमारा संबंध और मजबूत हो रहा है।

क्यों मनाते हैं विजय दिवस

1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में 93000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक है। 1971 के युद्ध में करीब 3900 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और करीब 10 हजार जवान घायल हुए थे।

सेना का काफिला उड़ाने की बड़ी साजिश नाकाम, आइईडी बरामद

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▶ आतंकियों ने सोपोर-कुपवाड़ा हाईवे पर लगाया था विस्फोटक

▶ सेना की रोड ओपनिंग पार्टी ने आइईडी का पता कर किया निष्क्रिय

सेना ने शनिवार को जिला बारामुला में सोपोर-कुपवाड़ा हाईवे पर सगीपोरा में सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम बनाते हुए एक शक्तिशाली आइईडी बरामद कर लिया। इसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, सेना की रोड ओपनिंग पार्टी (आरओपी) सोपोर-कुपवाड़ा हाईवे पर गश्त कर रही थी। इस दौरान सगीपोरा क्षेत्र में जवानों को डिटेक्टर से सड़क में बिछाई गइ आइईडी होने का संकेत मिला। जवानों ने तुरंत हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया और बम निरोधक दस्ते को सूचित किया। दस्ते ने जब जांच की तो एक जगह सड़क को खोदा हुआ पाया। उन्होंने सावधानीपूर्वक खोदाई कर शक्तिशाली आइईडी बरामद कर ली। इसके बाद सेना, सीआरपीएफ और एसओजी के जवानों ने सगीपोरा गांव की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच, बम निरोधक दस्ते ने आइईडी को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे निष्क्रिय कर दिया। पुलिस के अनुसार, इस मार्ग पर आम लोगों के अलावा सेना के काफिले भी गुजरते हैं। सुबह सेना का काफिला भी यहां से मूव करना था। आशंका है कि आतंकी इसी काफिले को निशाना बनाना चाहते थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह आइईडी काफी शक्तिशाली थी। अगर इसकी चपेट में नागरिक वाहन या सैन्य वाहन आ जाते तो काफी नुकसान हो सकता था।

बता दें कि इससे पहले 25 नवंबर को भी आतंकियों ने अनंतनाग में हाईवे पर सुरक्षाबलों के काफिले को निशाना बनाने के लिए कुकर में शक्तिशाली आइईडी लगाई थी, लेकिन तब भी सेना की चौकसी से वारदात को नाकाम बना दिया गया था।

रणजीत हत्या मामले में सीबीआइ जज जगदीप को बदलने की मांग

जागरण संवाददाता, पंचकूला

▶ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह है मुख्य आरोपित

▶ सह आरोपित ने दायर की याचिका, कहा- जज पर विश्वास नहीं

डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह हत्या मामले में सह आरोपित ने विशेष सीबीआइ जज गुरदीप सिंह को बदलने की मांग की है। विशेष अदालत में दाखिल याचिका में उसने कहा है कि विशेष जज पर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं है।

शनिवार को यहां विशेष अदालत में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपित सुनारिया जेल में बंद डेरा मुखी गुरमीत सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुआ। अन्य आरोपित प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई में फाइनल बहस शुरू होनी थी, जो नहीं हो पाई। सहआरोपित कृष्ण लाल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि विशेष जज जगदीप सिंह साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के केस में गुरमीत सिंह के खिलाफ पहले ही सजा सुना चुके हैं, इसलिए तीसरे मामले में वह किसी और जज से सुनवाई कराना चाहते हैं। विशेष जज जगदीप सिंह पर उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि इस बार भी वह उनके खिलाफ ही फैसला देंगे। उधर, सीबीआइ ने अपने जवाब में याचिका में कही गई बातों को झूठा करार देते हुए इसे जानबूझकर देरी कराने की कोशिश बताया गया है। अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी।

चिट्ठी लीक करने के संदेह में हुई थी हत्या

10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की हत्या हुई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआइ जांच की मांग की थी।

अब रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग में बाधा नहीं बनेगी बड़ी उम्र

राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग के शौकीनों के लिए खुशखबरी। अब उम्रदराज लोग भी इन साहसिक और रोमांचकारी खेलों और अभियानों का लुत्फ उठा सकेंगे। रिवर राफ्टिंग के लिए न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष की गई है। मंत्रिमंडल ने अहम फैसला लेते हुए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग (चतुर्थ संशोधन) नियमावली को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए अहम फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग नियमावली के मौजूदा नियमों में 14 वर्ष की आयु से कम और 65 वर्ष की आयु से अधिक के पर्यटकों को रिवर राफ्टिंग की मनाही थी। इसी तरह 18 वर्ष की आयु से कम और 50 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों को क्याकिंग की अनुमति नहीं थी। अब नियमावली में संशोधन के बाद 12 वर्ष से कम आयु वालों के साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटक भी रिवर राफ्टिंग कर सकेंगे। 12 से 14 वर्ष आयु के पर्यटकों के लिए ग्रेड-दो स्तर तक रैपिड पर ही राफ्टिंग की अनुमति होगी।

छत्तीसगढ़ के सारकेगुडा में तैयार किया जाएगा जलियांवाला जैसा बाग

नईदुनिया, बीजापुर

▶ जवानों पर फर्जी मुठभेड़ के नाम से सारकेगुड़ा में 17 लोगों को मारने का आरोप

▶ सात साल से न्याय की लड़ाई लड़ने वाली काका कमला कर रही है पहल

सारकेगुड़ा मामले में पिछले सात साल से न्याय के लिए लड़ने वाली गांव की युवती काका कमला का कहना है कि जिस तरह जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां बरसा कर निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की थी, उसी तरह छत्तीसगढ़ के सारकेगुड़ा में सुरक्षा बल के जवानों ने किया। निर्दोष ग्रामीणों पर गोली चलाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। अब जलियांवाला बाग की तरह सारकेगुडा के घटनास्थल पर मारे गए लोगों की याद में एक विशाल स्मारक तैयार किया जाएगा।

काका कमला ने बताया कि इसके लिए जन सहयोग से धनराशि एकत्र की जाएगी। गांव के हर घर से कुछ राशि चंदे के तौर पर जमा की जाएगी। श्रमदान कर गांव वाले स्मारक और पार्क का निर्माण करेंगे। इस निर्माण से पहले गांव में बैठक भी आयोजित की जाएगी। कमला ने बताया कि वह स्थल जहां 17 लोगों की हत्या की गई, उसमें उस जमीन के मालिक इरपा नारायण की भी मौत हो गई थी। उनके परिवार और परिजनों से बात कर उसी जगह पर स्मारक तैयार किया जाएगा।

गौरतलब है कि 28 जून 2012 को बीजापुर व बासागुड़ा से निकले कोबरा बटालियन व सीआरपीएफ जवानों ने सारकेगुड़ा गांव में ग्रामीणों पर गोलियां चलाईं थीं, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। इसमें आठ स्कूली बच्चे भी शामिल थे। ग्रामीण मुठभेड़ को फर्जी बताकर इसकी जांच की मांग लेकर मानवाधिकार आयोग तक पहुंचे। तब विपक्ष में रही कांग्रेस ने मुद्दे को आगे बढ़ाया। भाजपा सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट में मुठभेड़ को फर्जी बताया गया है। रिपोर्ट विधानसभा में भी पेश की जा चुकी है।

सारकेगुड़ा में धरना खत्म, सरकार को कार्रवाई का मौका देंगे आदिवासी : सारकेगुड़ा में आदिवासियों एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने शनिवार को थाने में जारी धरना खत्म कर दिया। धरने का नेतृत्व कर रहे हिमांशु कुमार ने बताया कि रात भर थाने में धरना जारी रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा से फोन पर बात हुई। वर्मा ने कहा कि सरकार अभी आयोग के रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। इसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट जारी करेंगे। अभी एफआइआर की जिद करेंगे तो कोई फायदा नहीं। इसके बाद धरना स्थगित करने का निर्णय लिया। मौके पर लीगल एंड ग्रुप की शालिनी गेरा भी पहुंची थीं।पुलिस को जो शिकायत पत्र दिया गया है, उसकी पावती लेने के साथ धरना खत्म किया गया। आंदोलनकारियों ने थाने में जो पत्र दिया है उसमें कहा गया है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को दोबारा शुरू किया जाएगा।

आए आगे

मप्र के टीकमगढ़ का है मामला, विद्यार्थियों ने प्रमुख सचिव के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं सुमन, इसलिए तबादले का विरोध

कलेक्टर का तबादला रुकवाने को घेरा दफ्तर

नईदुनिया, टीकमगढ़

मध्य प्रदेश के आइएएस अफसरों की तबादला सूची में टीकमगढ़ कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन का नाम शामिल होने से जिले के विद्यार्थी नाराज हो गए हैं। शनिवार को कलेक्टर का तबादला रुकवाने के लिए सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने प्रदेश के प्रमुख सचिव के नाम डिप्टी कलेक्टर विकास आनंद को ज्ञापन दिया। विद्यार्थियों का कहना है कि कलेक्टर सुमन निशुल्क कोचिंग देकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे थे, उनके तबादले से हमारी तैयारी प्रभावित होगी।

अकादमी का संचालन कर कलेक्टर स्वयं पढ़ाते थे : ज्ञापन देने पहुंची छात्राओं सोनम रिछारिया, शैली मिश्रा आदि ने बताया कि कलेक्टर सुमन द्वारा निशुल्क प्रशासनिक सेवा अकादमी का संचालन किया जाता है, इसमें गरीब परिवारों की छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए कलेक्टर स्वयं पढ़ाते थे।

398 विद्यार्थी अध्ययनरत : यह अकादमी जुलाई माह से लगातार संचालित हो रही है। 398 छात्र-छात्राएं वर्तमान में अकादमी में अध्ययनरत हैं। इसके अलावा जिले की शिक्षा व्यवस्था को भी उन्होंने सुधारा, लेकिन शासन ने उनका तबादला कर दिया। इससे नाराज छात्र-छात्राओं ने सौरभ कुमार सुमन को जिला कलेक्टर पद पर कायम रखने की मांग की है।

तबादला नहीं रोका तो आंदोलन : विद्यार्थियों ने कहा कि अगर कलेक्टर का तबादला आदेश निरस्त नहीं किया जाता है, तो सड़कों पर आकर आंदोलन किया जाएगा।

टीकमगढ़ के कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी करते जिले के विद्यार्थी। नईदुनिया

प्रशासन ने जम्मू बंद बनाया बेअसर

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पैंथर्स पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जम्मू बंद को विफल बना दिया। पार्टी ने मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रहने, सरोर टोल प्लाजा खुलने, बढ़ती महंगाई समेत अन्य मुद्दों के खिलाफ शनिवार को जम्मू बंद का आह्वान किया था। पुलिस ने पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह को तो गत दिवस घर में नजरबंद कर दिया था। पार्टी के प्रदेश प्रधान व पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया, यशपाल कुंडल समेत कुछ कार्यकर्ता जब सुबह प्रदर्शन करने प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे तो पहले से तैनात पुलिस बल सभी को हिरासत में लेकर जिला पुलिस लाइन ले गई।

अन्य क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं को नहीं आने दिया : पुलिस ने 40 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पार्टी के प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आरएसपुरा, ऊधमपुर, सांबा, विजयपुर व अन्य इलाकों से जम्मू पहुंचना चाहते थे जिन्हें जम्मू पहुंचने नहीं दिया गया। वहां से पुलिस ने वापस कर दिया। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि वे शांतिपूर्ण ढंग से जम्मू बंद करना चाहते थे।

आइएस केरल मॉड्यूल के दो सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

नई दिल्ली, आइएएनएस : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने आतंकी संगठन आइएस के केरल-तमिलनाडु मॉड्यूल के दो सदस्यों के खिलाफ शनिवार को आरोपपत्र दाखिल कर दिया। इनमें समूह का मास्टरमाइंड मुहम्मद अजरुद्दीन भी शामिल है। वह श्रीलंका में हुए ईस्टर धमाकों के मुख्य आरोपित जाहरान हाशिम से भी जुड़ा रहा है।

▶ एनआइए ने खुद संज्ञान लेते हुए छह आरोपितों के खिलाफ इसी साल मई में दर्ज किया था मुकदमा

एनआइए के प्रवक्ता ने दिल्ली में बताया कि एजेंसी ने एर्नाकुलम स्थित विशेष अदालत में अजरुद्दीन के अलावा शेख हिदायतुल्लाह के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है। एनआइए ने दोनों आरोपितों को इसी साल 12 जून को कोयंबटूर से गिरफ्तार किया था।

एजेंसी के अधिकारी के अनुसार, अजरुद्दीन श्रीलंका के ईस्टर धमाकों के मास्टरमाइंड जाहरान से फेसबुक पर जुड़ा हुआ था। इन धमाकों में करीब ढाई सौ लोग मारे गए थे। केंद्रीय एजेंसी ने खुद संज्ञान लेते हुए 30 मई को तमिलनाडु के कोयंबटूर निवासी छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसे सूचना मिली थी कि आरोपित केरल व तमिलनाडु के युवाओं को आइएस में भर्ती करना चाहते थे। इसके लिए वे सोशल मीडिया पर आतंकी विचारधारा का प्रचार करते थे।

प्रवक्ता ने बताया कि अजरुद्दीन व हिदायतुल्लाह वर्ष 2017 से ही आइएस की आतंकी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे। अजरुद्दीन इस मॉड्यूल का सरगना था और उसने फेसबुक पर बाकायदा 'खिलाफाहजीएफएक्स' नामक पेज भी बना रखा था। उन्होंने कहा, 'कोयंबटूर के अन्य स्थानों के अलावा वे अपने घरों में भी आइएस के समर्थन में गुप्त बैठकें करते थे। वे सोशल मीडिया पर जाहरान को फॉलो करते थे और उसके भड़काऊ भाषणों को डाउनलोड कर प्रसारित भी करते थे।'

अश्लीलता की असलियत

हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद एक बार फिर इंटरनेट पर सर्वसुलभ मुफ्त में उपलब्ध अश्लील सामग्री पर रोक लगाने की पूरे देश में चर्चा छिड़ गई है। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने इस अश्लीलता के प्रसार को रोकने के लिए सांसदों की एक समिति से कारगर सुझाव मांगकर इस चर्चा को आगे बढ़ा दिया है। यह बहस का विषय है कि इंटरनेट पर मौजूद पोर्नोग्राफिक सामग्री से किशोर, तरुण और युवा विकृत मानसिकता के शिकार होकर दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल इंटरनेट पर अश्लील सामग्री देखने की प्रवृत्ति में तेजी टेलीकॉम कंपनियों में गलाकाट प्रतिस्पर्धा के बाद आई, जिसके तहत उन्होंने लगभग मुफ्त में उपभोक्ताओं को डाटा मुहैया कराना शुरू किया। टेलीकॉम उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार भारत में कुल इंटरनेट देखने में 70 फीसद हिस्सा सिर्फ पोर्नोग्राफी देखने में किया जाता है। इस बात की पुष्टि कुछ पोर्न वेबसाइटें भी करती हैं। पोर्न हब के अनुसार भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद उसका तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। 2013 से 2017 के बीच यहां पोर्न ट्रैफिक में 121 फीसद उछाल आया है। 2013 में इसका 39 फीसद ट्रैफिक मोबाइल फोन से आता था।

साल 2017 में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 86 फीसद हो गई है। यह टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा सस्ता डाटा दिए जाने के बाद इस प्रवृत्ति में बढ़ोतरी की बात की तस्दीक करता है। सरकार सेवाओं के डिजिटलीकरण पर जोर दे रही है। पेपरलेस दफ्तरों और सरकारी कामकाज की परिकल्पना कर रही है। उसकी सोच रही है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी सुविधाएं लोग आसानी से हासिल कर पाएंगे। इस क्रम में वह टेलीकॉम कंपनियों पर दबाव बनाती है कि लोगों को सस्ता इंटरनेट सुलभ हो। सरकार खुद भी जगह-जगह मुफ्त वाई-फाई और ब्रॉड बैंड लगाकर अपनी मंशा स्पष्ट करना चाह रही है, लेकिन पटना स्टेशन पर लगे मुफ्त वाई-फाई स्पॉट से अधिकांश अश्लील सामग्री देखने वाले उपभोक्ता उसके मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं। बड़ा मुद्दा यही है कि सस्ता डाटा उपलब्ध कराकर हम देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं-पोर्नोग्राफी व एंटरटेनमेंट या शिक्षा-संस्कार और नैतिकता के रास्ते में। इससे अच्छा डाटा को महंगा कर दिया जाए। टेलीकॉम कंपनियों की जर्जर हालत भी ठीक होगी और अश्लीलता के मायाजाल से भी मुक्ति मिलेगी।

28 घंटा भारतीय लोग हर हफ्ते इतने घंटे अपने स्मार्ट फोन पर बिताते हैं

जनमत

क्या पोर्नोग्राफी की सहज-सर्व सुलभता बाधित होनी चाहिए, इसके लिए सख्त नियम कानून बनने चाहिए।
हां 96%
नहीं 04%

क्या इंटरनेट पर सर्व सुलभ पोर्नोग्राफी हैदराबाद या निर्भया कांड जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं?
हां 92%
नहीं 08%

तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश

इंटरनेट डाटा सस्ता मिलने के चलते भारत में अश्लील सामग्री देखने के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि दिखी है। अश्लील सामग्री के लिए मशहूर वेबसाइट पोर्नहब के आंकड़े बताते हैं कि उसके उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर भारत तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। पहले और दूसरे पर क्रमश: अमेरिका और ब्रिटेन हैं।

सस्ता इंटरनेट से बढ़ी प्रवृत्ति

वीडियो व्यूअरशिप की निगरानी करने वाली संस्था विडूली के अनुसार जब से टेलीकॉम कंपनियों के बीच गलाकाट प्रतिस्पर्धा के चलते इंटरनेट के दाम बहुत सस्ते (लगभग मुफ्त) हुए तब से अश्लील सामग्री देखने वालों की संख्या में 75 फीसद इजाफा हुआ है। यही नहीं, देखने के समय में भी 60 फीसद इजाफा हुआ। टेलीकॉम कंपनियों के इस कदम से दूसरे और तीसरे स्तर के कस्बों में भी यह प्रवृत्ति महामारी की तरह फैल गई।

डाउनलोड से ज्यादा लोकप्रिय स्ट्रीमिंग

क्लीनेर पर्किंस की इंटरनेट ट्रेंड्स रिपोर्ट 2017 बताती है कि उस दौरान एक दौर ऐसा भी आया जब लोग डाउनलोड की जगह वीडियो की स्ट्रीमिंग करना ज्यादा पसंद करने लगे। इसकी वजह दूसरे और तीसरे दर्जे के कस्बों में लोगों के पास बहुत महंगे स्मार्ट फोन नहीं होते हैं। उनमें स्टोरेज क्षमता कम होती है। लिहाजा वे डाउनलोड की जगह सीधे वीडियो देखना ज्यादा पसंद करने लगे। देश की पूरी व्यूअरशिप में 60 फीसद हिस्सेदारी इन श्रेणी के कस्बों की रही है। 2017 के मार्च के अंत तक हर महीने डाटा खपत 130 करोड़ जीबी तक पहुंच गई जो पिछले साल के मुकाबले नौ गुना ज्यादा थी।

लोगों की पहुंच में कीमतें

एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। ऐसी हालत में कसैलेपन को कोई भी महसूस कर सकता है। देश में अश्लील सामग्री देखने की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए दो सकारात्मक कारकों का एक साथ मिल जाना रहा है। एक तो 3जी और 4जी को सपोर्ट करने वाले स्मार्ट फोन की कीमतें तेजी से गिरीं। वे औसत आय वाले लोगों तक पहुंचे। दूसरे इंटरनेट डाटा की कीमतें दुनिया में यहीं पर सबसे सस्ती रहीं। मार्च, 2017 में औसतन एक जीबी डाटा की कीमत 0 .33 डालर (करीब 22 रुपये) रही।

स्मार्टफोन के साथ लंबा वक्त

औसतन हर भारतीय स्मार्ट फोन के साथ लंबा वक्त बिताने लगा है। कांतार आइएमआरबी के अनुसार लोग हर हफ्ते 28 घंटा अपने स्मार्ट फोन पर बिताते हैं। यह आंकड़ा टेलीविजन पर बिताए जाने वाले वक्त से सात गुना अधिक है। स्मार्ट फोन पर बिताए जाने वक्त का 45 फीसद समय केवल मनोरंजन के लिए होता है।

ट्रैफिक वृद्धि के मामले में शीर्ष पर

पोर्नहब के आंकड़ों के अनुसार मोबाइल पर पोर्न देखने के मामले में 2013 से 2017 के बीच भारत में 121 फीसद वृद्धि हुई है। यह दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है।

देश	ट्रैफिक वृद्धि
भारत	121
जापान	115
कनाडा	65
यूके	49
अमेरिका	38

(फीसद में) (2013 से 2017 के बीच)

पोर्नहब देखने वाले आयुवार भारतीय

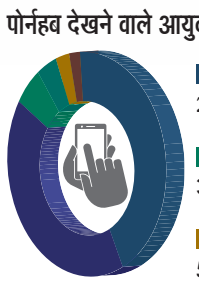

लैंगिक हिस्सेदारी: 30% महिलाएं, 70% पुरुष

जानकारी ही बचाव

दिव्या वैष्णव
निदेशक और सह संस्थापक, बड फाउंडेशन

प्रतिबंध लगाना या डाटा महंगा करना इस समस्या का हल कतई नहीं है। तमाम सकारात्मक उद्देश्यों के लिए युवा इंटरनेट का लाभ उठाते हैं। आवश्यकता है एक ऐसे जागरूकता अभियान की, जिसमें बच्चों व युवाओं को सटीक जानकारी दी जाए।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के मुताबिक व्यापक स्तर पर यौन शिक्षा (सीएसई) का उद्देश्य बच्चों व युवाओं में जानकारी, कौशल, व्यवहार और जीवन-मूल्य को बढ़ाना है, जिससे उनकी एक सकारात्मक सोच अपने मानसिक और सामाजिक विकास के संदर्भ में तैयार हो सके। सीएसई युवाओं को उनकी गरिमा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जरूरी जानकारी मुहैया कराती है। इसमें लैंगिक समानता, मर्दानगी, स्त्रीत्व, यौन, प्रजनन स्वास्थ्य, यौन पहचान के बारे में चर्चा होती है। इसमें हिंसा के विभिन्न रूपों और अभिव्यक्तियों के पहचानने पर जोर दिया जाता है। हमारे युवा जिन्हें इस तरह की शिक्षा से वंचित रखा जाता है, अक्सर गलत तरीकों से अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं, इसमें गलती उनकी नहीं है, परिवारों में सेक्स, शारीरिक बदलाव या रिश्तों के बारे में बिल्कुल बात नहीं की जाती है।

आज भी आप महिलाओं को माहवारी के बारे में खुल कर बात करते हुए नहीं पाते हैं। उम्र के जिस पड़ाव पर बच्चों को एक संतुलित मार्गदर्शन व सही जानकारी की जरूरत है, उस वक्त अगर उन्हें पोर्नोग्राफिक वेबसाइट के जरिए जानकारी मिलती है, जिससे यौनिकता, सहमति व यौन संबंधों के बारे में उनकी समझ पर गलत प्रभाव पड़ता है। इन वेबसाइट्स पर आत्मीय रिश्तों में अक्सर यौनिक हिंसा दिखायी जाती है, जिससे देखने वाले सहमति, स्वस्थ और अस्वस्थ रिश्तों के बारे में एक विकृत सोच बना लेते हैं। अगर उनके पास पहले से सटीक जानकारी होगी और इन विषयों के बारे में खुलकर बात करने की आजादी होगी, तो वे अपने मन में उठने वाले सवालों व शंकाओं को दूर कर पाएंगे। इस पितृ सत्तात्मक समाज में बच्चे एक छोटी उम्र से ही घर और आसपास के मर्दों को असंवेदनशील, हिंसक और सदस्यों पर हावी होते हुए देखते हैं, इस तरह के माहौल में बच्चों की सोच पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। किस तरह से हम अपने युवाओं को संवेदनशील बना सकते हैं- इसके लिए हमें विषाक्त पुरुषत्व के विचारों को बदलना होगा, परिवारों में लैंगिक समानता लानी होगी, हर तरह की हिंसा पर शुरू से ही रोक लगानी होगी। किसी परिवार में अगर बच्चों के साथ उनके लिंग के आधार पर भेदभाव होता है यह एक तरह की हिंसा ही है। इसके बारे में सबको जागरूक होना है और रोकना है। अगर परिवार में एक महिला अकेली ही घर के सारे काम करती है, यह भी एक तरह की हिंसा है, उसके अधिकारों का हनन है। हम कितने मर्दों को घर के काम खुशी से करते हुए देखते हैं? घर में बुजुर्ग महिलाओं को भी अपनी सोच में बदलाव लाते हुए लड़का लड़की का पालन पोषण एक समान करना चाहिए।

किसी भी वेबसाइट को प्रतिबंधित करना इस समस्या का हल कतई नहीं है। न ही मैं यह मानती हूं कि डाटा महंगा करना चाहिए क्योंकि पोर्नोग्राफी के अलावा बहुत सारे सकारात्मक उद्देश्यों के लिए युवा इसका लाभ उठाते हैं। आवश्यकता है एक ऐसे जागरूकता अभियान की, जिसमें बच्चों व युवाओं को सटीक जानकारी दी जाए। समुदायों में वर्जित समझे जाने वाले विषयों पर खुलकर चर्चा की जाए। स्कूलों, कॉलेजों के नियमित पाठ्यक्रमों की व्यापक यौनिकता शिक्षा अनिवार्य हिस्सा होनी चाहिए।

डाटा की आसान उपलब्धता आज शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर तमाम क्षेत्रों में लोगों के जीवन को आसान करने का काम कर रही है। इसके महंगा होने की स्थिति में इन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। बड़ी संख्या में लोग इसके सकारात्मक लाभ से वंचित रह जाएंगे।

हम सबको मिलकर समाज के पुरुषों को संवेदनशील बनाने में उनकी मदद करनी है, एक भावुक पुरुष का मजाक उड़ाने की बजाय उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सुरक्षित खुशहाल समाज समानता पर ही आधारित हो सकता है। किसी पर हावी होने से या कुछ बैन करने से डर का माहौल बनता है। लिहाजा जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए।

पूर्ण प्रतिबंध नहीं, अंकुश की दरकार

डॉ निमेष जी देसाई
निदेशक, इहबास (मानव व्यवहार व संबद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली)

जिस मानव व्यवहार पर रोक लगाई जाती है, वह उतना ही तेजी से पनपता है। इसलिए हमें अंकुश की तरफ ध्यान देना होगा। पारिवारिक, सामाजिक और कानूनी बंदिशें लगानी होंगी।

मानव का मन और हृदय कोमल होता है। यह आसानी से किसी भी चीज से प्रभावित हो सकता है। खासकर नकारात्मक चीजों को आसानी से ग्रहण करता है। हमारे मस्तिष्क में पांच तरह के सेंस (इंद्रिय) होते हैं। इनमें दो-तीन सेंस ऐसे हैं जो पोर्नोग्राफी के कारण प्रभावित होते हैं। मानव को हिंसक भी बनाता है। लेकिन ऐसा कहना गलत है कि पोर्नोग्राफी ही पूरी तरह से बढ़ते दुष्कर्म और इससे संबंधित घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। आज भले ही यह लोगों को आसानी से उपलब्ध है। लेकिन 30-40 साल पहले तो ऐसा नहीं था। तब भी दुष्कर्म की जघन्य वारदातें सामने आती थीं। हां यह जरूर है कि इसने हर उम्र के लोगों के बीच अपनी जगह बना ली है। जिसका स्वभाव हमलावर है, वह इन चीजों से प्रभावित होकर वारदात कर सकता है।

कुछ दशक पहले की हमारी पीढ़ी को स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है। यानी साहित्य समाज की सच्चाई दर्शाता है। साहित्य का संबंध एकतरफा था। कोई उस पर त्वरित प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। लेकिन आज हर घर में इंटरनेट पहुंच चुका है। लोग प्रिंट मीडिया और रेडियो युग को पार कर आज टीवी और सोशल मीडिया के दौर में आ चुके हैं। यहां संबंध और संवाद दोतरफा हो चुके हैं।

इंटरनेट की वजह से पोर्नोग्राफी भी हर किसी की पहुंच में है। लेकिन जिस स्थिति में आज हम पहुंचे तो उसमें कई विकसित देश 30 से 40 साल पहले पहुंच चुके थे। वहां भी इस तरह की घटनाएं होती है। इस पर कई शोध हुए। उसके निष्कर्षों पर कहीं कोई सहमति नहीं बन पाई। लेकिन इस पर सहमति जरूर है कि ये मानव व्यवहार को प्रभावित करती है। इसमें यह भी बात सामने आती है कि व्यवहार को नियंत्रित करने और सही निर्णय लेने की क्षमता एक उम्र के बाद ही आती है। दुष्कर्म की वारदातों में सिर्फ किशोर और युवा ही शामिल हैं, ऐसा नहीं है। इसमें अधेड़ और बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। जब ऐसे लोगों की बात करते हैं तो कारण बदल जाते हैं। दरअसल किशोर और युवा उत्तेजना पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। वहीं अधेड़ और बुजुर्ग लोगों की दबी हुई इच्छाएं पोर्नोग्राफी को देखकर उनके मस्तिष्क पर हावी हो जाती हैं। कुछ लोग इस पर नियंत्रण कर लेते हैं और कुछ अपराध कर जाते हैं। पोर्नोग्राफी लोगों को एक आभासी दुनिया में लेकर जाती है। जहां वह परदे पर दिखाई जा रही कहानी और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाते हैं।

ऐसे में जरूरी है कि पोर्नोग्राफी पर अंकुश हो। पूर्णतया बंद करना, इसका हल नहीं है। अगर यह हल होता तो कई विकसित देशों में इस पर प्रतिबंध लगा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे भी यह देखा जाता है कि जिस मानव व्यवहार पर रोक लगाई जाएगी, वह और पनपेगा। इसलिए हमें अंकुश की तरफ ध्यान देना होगा। पारिवारिक, सामाजिक और कानूनी बंदिशें लगानी होंगी। घर और समाज में बच्चों को यह लैंगिक ज्ञान देना जरूरी है। साथ ही उनमें अच्छे आचरण देने की जिम्मेदारी भी परिवार और समाज को उठानी पड़ेगी। उन्हें बताना पड़ेगा कि महिलाओं का सम्मान किस तरह से किया जाए। उन्हें आभासी और वास्तविकता के बीच के अंतर को बताना पड़ेगा। तब जाकर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी में सुधार होगा।

(स्वदेश कुमार से बातचीत पर आधारित)

कमजोर कवायद

इंटरनेट पर अश्लील सामग्री और वेबसाइट की भरमार है। यदा-कदा अदालतों की सख्ती के बाद सरकार ने इन पर लगाम लगाने की कवायद भी की है, लेकिन सरकार डाल-डाल तो अश्लीलता परोसने वाली वेबसाइट्स पात-पात। नतीजा सिफर ही रहा।

प्रतिबंध की कार्रवाई

अगस्त, 2015 में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने अश्लीलता परोसने के आरोप में 857 वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने का कदम उठाया। बाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भारत सरकार के टेलीकॉम विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को अश्लील सामग्री वाली 827 वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने का फरमान सुनाया।

नाम नया, काम वही

केंद्र की सख्ती के बावजूद अश्लील साइटों पर रोक नहीं लग पा रही है। सरकार वेबसाइट को प्रतिबंधित करती है तो वह दूसरे डोमेन के साथ काम शुरू कर देती है। कुछ समय पहले जब विश्व की सबसे बड़ी पॉर्न वेबसाइट को बैन किया तो उसने भारतीय दर्शकों के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा नए डोमेन के बारे में बताया।

ब्राउजर के लिए नहीं है बैन

बैन के बावजूद भी कुछ ब्राउजर हैं, जहां पर आपकी पहुंच बैन पोर्टल्स तक भी हो सकती है। इनमें यूसी ब्राउजर सबसे लोकप्रिय पोर्टल है।

इंटरनेट के अलावा भी तरीके

इंटरनेट पर पोर्न बैन भी कर दिया जाए तो कई माध्यमों द्वारा यह सर्वसुलभ है। भारत में ऑफलाइन पॉर्नोग्राफी का बड़ा मार्केट है। कोई भी महज 20-30 रुपए खर्च कर अश्लील डीवीडी खरीद सकता है। वहीं आजकर पैन ड्राइव में अश्लील सामग्री डालने वाले दुकानदार भी मौजूद हैं, जो बहुत कम राशि में आपको पोर्न उपलब्ध करा रहे हैं।

अकेले में पॉर्न देखना नहीं है अपराध

भारत में अकेले में पोर्न देखना अपराध नहीं है। हालांकि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी अपराध है। साथ ही अश्लील सामग्री का निर्माण और उसे लोगों को बांटना अपराध है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने भी उन्हीं वेबसाइट को बंद किया है जिनमें बाल अश्लीलता परोसी जा रही है।

आपकी आवाज

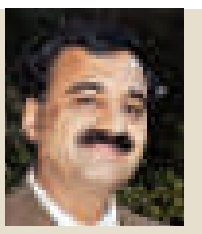

पोर्नोग्राफी भी बहुत हद तक दुष्कर्म के मामलों के लिए जिम्मेदार है। सरकार को पोर्न की साइटों पर रोग लगा देनी चाहिए। **अवधेश सिंह यादव**

देश में दिन-प्रतिदिन बढ़ते अनैतिक कामों को रोकना है तो इसके लिए देश में पोर्नोगाफी को बैन करने के साथ उन टीवी सीरियलों, फिल्मों, नशे को और हर उस प्रणाली को बंद करना होगा, जो समाज को पथभ्रष्ट करती हों। **राजेश कुमार चौहान**

इंटरनेट पर सर्व सुलभ अश्लील सामग्री निश्चित रुप से समाज में हो रही दिल दहला देने वाली घटनाएं एक प्रमुख कारण है, इस पर जितना जल्द संभव हो सख्त व प्रभावी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। **रुपेश तिवारी**

जब तक समाज के हर वर्ग का व्यक्ति महिला को भोग्या स्वरूप प्रस्तुत किए जाने वाले सभी हथकंडों का खुला विरोध नहीं करेगा तब तक आप लाख कोशिश करलें कोई न कोई निर्भया और दिशा जैसे हादसे हमारे सामने आते ही रहेंगे। **नीरज मिश्रा**

बड़ी आसानी से इंटरनेट पर पोर्न वीडियो उपलब्ध होना युवाओं के लिए खतरनाक है। सरकार को पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। **रनवीर कुमार।**

अश्लील विज्ञापन और फिल्में भी दोषी हैं। परिवार से अच्छे संस्कार न मिलना भी एक बड़ा कारण है। **रमेश प्रसाद**

दुष्कर्म की घटनाओं की जड़ इंटरनेट में सहज उपलब्ध अश्लील वीडियो है। सरकार को चाहिए कि इसपर रोक लगाए। **आकाश।**

ढंग से लागू हों कानून

डॉ पवन दुग्गल
साइबर विशेषज्ञ

कानून में बदलाव और कड़े प्रावधान करने होंगे। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। जागरूकता भी इसी कदम का अहम हिस्सा बने।

एक देश के रूप में भारत साइबर स्पेस में चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें पोर्नोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर यह सुनिश्चित करना कि अश्लीलता का देश के युवाओं के दिमाग पर किसी भी तरह का नकारात्मक असर न पड़े, बहुत मुश्किल डगर लग रही है। भारत में संसद ने ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है, जो प्रभावशाली ढंग से ऑनलाइन अश्लीलता देखने पर रोक लगा सके। हालांकि जब कोई व्यक्ति अश्लील इलेक्ट्रॉनिक सूचना को प्रकाशित अथवा प्रसारित करता है तो जरूर कानूनी घेरे में आता है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 67 के तहत ऐसा करना अपराध है। प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67 में अश्लीलता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि भाषा की गिरावट जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट में जो कि कामुक हो अथवा कामुकता को बढ़ाने वाली हो या मानसिकता को बिगाड़ने वाली हो चाहे फिर वो पढ़ने, देखने या सुनने वाली हो, का यह उल्लेख करता है। यह इतना विस्तृत है कि ऑनलाइन अश्लील सामग्री के सभी तत्वों को शामिल कर सकता है फिर चाहे वे दृश्य, श्रव्य, तस्वीर या लिखित रूप में हों।

2008 में सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 में दो विशिष्ट अपराधों को जोड़ा गया है। धारा 67ए के मुताबिक अश्लील इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को प्रकाशित करना अथवा प्रसारित करना अपराध है। इसे पांच साल की कैद अथवा दस लाख रुपए के जुर्माने के साथ और ज्यादा गंभीर अपराध बनाया गया है। साथ ही पहली बार 2008 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के प्रावधानों को भी जोड़ा गया। इसके तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी का न केवल प्रकाशन और प्रसारित करना बल्कि इसे ब्राउज करना भी धारा 67बी के तहत जघन्य अपराध है। इसके तहत दस साल की सजा और दस लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इन प्रावधानों के कानून में होने के बावजूद इनका विस्तृत रूप से उपयोग नहीं किया जा सका है। इसके परिणामस्वरूप, इन मामलों में सजा कम ही मिल सकी है। इसके अतिरिक्त आरोपितों की प्रवृत्ति और उनके जमानत पर बाहर आने के बाद वह संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। इसमें साइबर अपराध के लिए सजा का अकाल और योगदान देता है। अब वह समय आ चुका है जब देश को इंटरनेट और मीडिया पर मौजूद अश्लील सामग्री के खिलाफ कड़ा और इसे हतोत्साहित करने वाला संदेश देना चाहिए। कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट रूप से लागू करने की आवश्यकता है और उससे भी ज्यादा आवश्यकता अश्लील सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण में लगे ऐसे लोगों को रोकने के लिए कानून में संशोधन की है।

सोशल मीडिया पर मौजूद अश्लील सामग्री के बड़े उपयोग और प्रसार पर लगाम कसने के लिए सोशल मीडिया की प्रभावी निगरानी जरूरी है। इस मामले में सबसे ज्यादा जरूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वालों को रोकना और भी महत्वपूर्ण है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 2 (1)(डब्ल्यू) के अंतर्गत सभी सोशल मीडिया सेवा प्रदाता और मध्यस्थ इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए धारा 79(2) के अंतर्गत बाध्य किया जा सकता है। यह अनिवार्य है कि इन मध्यस्थों और सेवा प्रदाताओं को अपने उद्यम के मानकों पर पोर्नोग्राफी और अश्लीलता संबंधी सामग्री को रोकने के संबंध में उपयुक्त और प्रभावी होना चाहिए। यह सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी है कि वो यह सुनिश्चित करे कि अश्लील इलेक्ट्रॉनिक सामग्री उसके प्लेटफॉर्म से प्रसारित नहीं होगी। अगर उन्हें सूचित किया जाता है तो उन्हें कानून के अनुसार तुरंत ऐसी चीजों को हटाना या नष्ट कर देना चाहिए।

कानून में बदलाव के अतिरिक्त यह मौजूदा कानूनी प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना भी अहम है। अश्लील इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के बीमार करने वाले खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने पर निर्भर करता है। यह काफी महत्वपूर्ण है कि हम इस मुद्दे को स्कूलों में पहली कक्षा से ही उठाएं। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इंटरनेट को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने की शुरुआत करें।

दैनिक जागरण

सहनशीलता में भी एक अद्भुत शक्ति समाई होती है

सस्ती सियासत

उन्नाव में दुष्कर्म के आरोपियों की ओर से जलाई गई युवती की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत के बाद यदि लोगों को गुस्सा फूट पड़ा है तो यह स्वाभाविक है, लेकिन कुछ नेता और राजनीतिक दल इस गुस्से को जिस तरह भुनाने में लगे हुए हैं वह राजनीति नहीं, घटिया राजनीति का ही शर्मनाक उदाहरण है। उन्नाव की घटना पर विपक्षी नेता धरना-प्रदर्शन के साथ सरकार और पुलिस को इस तरह कोसने में लगे हुए हैं जैसे वह अपराधियों के बचाव में खड़ी हो। दुष्कर्म के मामलों को लेकर राजनीतिक लाभ हासिल करने की लालसा किस हद तक पहुंच चुकी है, इसका पता राहुल गांधी के इस बयान से चलता है कि भारत दुष्कर्म की राजधानी बन गया है। आखिर यह संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश में देश को बदनाम करने वाला बयान नहीं तो और क्या है? इससे इन्कार नहीं कि हाल के समय में दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं और दुष्कर्मी तत्वों के खिलाफ वैसी त्वरित कार्रवाई भी नहीं हो पा रही जैसी होनी चाहिए, लेकिन आखिर इस नतीजे पर कैसे पहुंचा जा रहा है कि भारत दुष्कर्म की राजधानी में तब्दील हो गया है? क्या ऐसे भारत से कांग्रेस शासित प्रदेश बाहर हैं या फिर राहुल यह कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में सब ठीक है?

इससे बुरा और कुछ नहीं कि राजनीतिक दल दुष्कर्म सरीखे घिनौने अपराध पर राजनीतिक रोटियां सेंकते नजर आएं, लेकिन यह प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है और उसका प्रदर्शन संसद से लेकर सड़क तक किया जा रहा है। जो दल जहां सत्ता में है वह वहां के दुष्कर्म की घटनाओं की अनदेखी कर अन्य राज्यों की ऐसी ही घटनाओं पर आपा खोने का दिखावा कर रहा है। जो विपक्ष में हैं वे ऐसा दिखा रहे जैसे उनके सत्ता से हटते ही दुष्कर्म की घटनाएं बेलगाम हो गई हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बिना सोचे-समझे दुष्कर्म के आरोपियों को हैदराबाद सरीखी मुठभेड़ का शिकार बनाने की मांग कर रहे हैं। यह सस्ती और छिछली राजनीति है। दुष्कर्म की घटनाएं कोई राजनीतिक समस्या नहीं हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध और खासकर दुष्कर्म एक सामाजिक समस्या हैं। इस समस्या का समाधान सड़कों पर शोर मचाने से नहीं, सामाजिक माहौल और साथ ही लोगों की मानसिकता बदलने से होगा। क्या राजनीतिक दल इसमें सहयोग कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या वे पुलिस को समर्थ बनाने और न्यायिक प्रक्रिया की खामियों को दूर करने में सहायक बन रहे हैं? हालात यही अधिक बयान करते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाने के बहाने गैर जिम्मेदारी का ही परिचय दे रहे हैं।

नया आतंकी संगठन

बांग्लादेश से घुसपैठ कर बंगाल समेत देश के कई राज्यों में जड़े जमाने वाले आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) पर नकेल कसने में जांच एजेंसियां काफी हद तक सफल हुई हैं। इन सबके बीच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को नए आतंकी संगठन 'अंसारुल्लाह बांग्ला' का पता चला है, जिसने कर्नाटक, बंगाल और मेघालय में चुपके-चुपके अपने पैर पसार लिए हैं। एनआइए इस आतंकी संगठन से जुड़े सदस्यों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में है। एनआइए की टीम को अंसारुल्लाह बांग्ला के बारे में तब जानकारी मिली, जब मेघालय से फरहान नामक युवक की गिरफ्तारी हुई। कोलकाता लाए गए फरहान ने जांच एजेंसी को पूछताछ में बताया कि वह बेंगलुरु में एक छात्र के रूप में रह रहा था। उसके साथ एक और संदिग्ध था, जो फरार है। एनआइए ने फरहान से मिली सूचनाओं का सत्यापन शुरू किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस आतंकी संगठन के इरादे खतरनाक हैं। वह भारत में अशांति फैलाने के साथ ही अपना विस्तार करना चाहता है। माना जा रहा है कि अंसारुल्लाह बांग्ला की जड़ें भी बांग्लादेश में हैं क्योंकि पड़ोसी देश में सक्रिय आतंकी संगठनों की नजर हमेशा से भारत, खासकर सीमावर्ती देशों पर रही हैं। गतिविधियों के तार जुड़े होने की आशंका तो बहुत पहले से थी लेकिन दो अक्टूबर, 2014 को तत्कालीन बर्द्धमान जिले के खागरागढ़ में एक घर में हुए धमाके ने सुराग दे दिए। उस धमाके में दो लोग मारे गए थे। एनआइए ने जब इस धमाके की जांच शुरू की तो पता चला कि इसमें जेएमबी का हाथ है। इसका जाल पूरे बंगाल ही नहीं, असम, झारखंड और बिहार तक फैला हुआ है। बाद में जेएमबी के अलकायदा और आइएसआइएस से जुड़े होने के प्रमाण भी मिले। कार्रवाई शुरू हुई तो परत-दर-परत खुलती चली गई। असम, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों से जेएमबी ने अपने तार जोड़ लिए थे। इसके बाद जेएमबी के स्लीपिंग सेल्स की गिरफ्तारी शुरू हुई तो फिर नए रहस्य उजागर होने लगे और कई गिरफ्तारियां भी हुईं। असल में उनका लक्ष्य ग्रेटर बांग्लादेश का निर्माण था, जिसमें मुर्शिदाबाद व मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों को शामिल कर सीमा विस्तार था। यह संगठन ग्रेटर बांग्लादेश बनाकर वहां शरिया कानून लागू करने का भी ख्वाब देख रहा था और उस दिशा में ठोस रणनीति भी बनाई गई थी। उनके खतरनाक इरादों की भनक लगते ही एनआइए ने पूरी रणनीति विफल कर दी। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ तो अंसारुल्लाह बांग्ला की भी हकीकत सामने आ गई।

नागरिकता निर्धारण का सही तरीका

संजय गुप्त

नागरिकता विधेयक पर विचार करते समय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाए, न कि वोट बैंक की राजनीति को। यह राजनीति पहले ही देश का बहुत नुकसान कर चुकी है

अवधेश राजपूत

मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में अपने चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए किस तरह प्रतिबद्ध है, इसका एक उदाहरण तीन तलाक पर कानून का निर्माण करने से मिलता है और दूसरा कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने से। इन दोनों वायदों को पूरा करने के बाद मोदी सरकार अब नागरिकता कानून में संशोधन को लेकर संकल्पबद्ध दिख रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के मसौदे का कई राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले दल वही हैं जो अतीत में पूर्वोत्तर में होने वाली घुसपैठ को लेकर शुतुरमुर्गी रवैया अपनाए रहे। इसी रवैये के कारण वे असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का भी विरोध कर रहे हैं। इन दलों के विपरीत भाजपा प्रारंभ से यह कहती आ रही है कि असम में घुसपैठ रोकने के साथ ही बाहर और खासकर बांग्लादेश से आए लोगों की पहचान होनी चाहिए। नागरिकता रजिस्टर के जरिये यही काम किया गया है। भाजपा की यह भी दलील है कि अवैध घुसपैठ से न केवल देश के संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है, बल्कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में स्थानीय संस्कृति के लिए खतरा भी पैदा हो रहा है। यह खतरा काल्पनिक नहीं है, क्योंकि असम में बांग्लादेश से आ बसे लाखों लोगों के कारण स्थानीय भाषा, संस्कृति खतरे में पड़ गई है। इन लोगों ने स्थानीय नेताओं का संरक्षण पाकर राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र तक हासिल कर लिए हैं। ऐसे लोगों को वोट बैंक राजनीति के चलते अभी भी संरक्षण मिल रहा है।

बांग्लादेश से अवैध रूप से असम आए लोगों के कारण इस राज्य के साथ अन्य पड़ोसी राज्यों के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक-सामाजिक माहौल बदल गया है। कई हिस्सों में स्थानीय लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं या फिर उनके वोटों के बजाय बाहरी लोगों के वोट निर्णायक बन गए हैं। हैरानी है कि कई राजनीतिक दल इस सच्चाई का संज्ञान लेने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। वे इसकी भी अनदेखी कर रहे हैं कि कहीं बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? बांग्लादेश से आए लोगों में एक बड़ी संख्या मुसलमानों की है और वे उत्पीड़न नहीं, बल्कि बेहतर आर्थिक जीवन की लालसा में अवैध रूप से भारत आए हैं, जबकि हिंदू और बौद्ध उत्पीड़न से त्रस्त होकर। इसी को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आस्था रखने वाले पड़ोसी देशों से आए सैकड़ों परिवारों की नागरिकता का रास्ता खुलेगा तो उससे उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा। पता नहीं नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे दल यह देखने को तैयार क्यों नहीं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी कितनी तेजी से घटती जा रही है? इन तीनों देशों में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, ईसाइयों, पारसियों आदि की आबादी में कमी का एक बड़ा कारण उनका उत्पीड़न है। इस उत्पीड़न से बचने के लिए आम तौर पर वे भारत की ओर ही रुख करते हैं। इसका कारण उनका यह भरोसा है कि वे यहां निर्भय होकर अपना जीवन बिता सकते हैं, लेकिन उनकी नागरिकता विवाद का विषय बन गई है। इसी के साथ एनआरसी के जरिये 19 लाख लोगों को बाहरी करार देने का मसला भी विवाद का कारण बना हुआ है। असम के लोग जहां इससे नाखुश हैं कि इतने कम लोगों को ही अवैध नागरिकों के तौर चिन्हित किया गया वहीं भारत सरकार की समस्या यह है कि इनमें तमाम हिंदू हैं। असम के कई संगठन इन बांग्लाभाषी हिंदुओं को भी शरण देने का विरोध कर रहे हैं। इनमें से कुछ नागरिकता विधेयक के भी विरोध में हैं।

नागरिकता संशोधन विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, ईसाइयों और पारसियों को कुछ शर्तों के साथ नागरिकता देने का प्रावधान है। इन देशों के मुसलमानों को इसलिए बाहर रखा गया है, क्योंकि बहुसंख्यक होने के नाते उनके उत्पीड़न की गुंजाइश नहीं। सरकार का तर्क है कि इन तीनों देशों के जो मुसलमान भारत आते हैं वे बेहतर जीवन-यापन के इरादे से आते हैं और ऐसे लोगों को उत्पीड़ित लोगों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वास्तव में उत्पीड़न के शिकार लोगों और बेहतर जीवन की तलाश में आए लोगों में भेद करने को न तो अन्याय कहा जा सकता है और न ही यह दलील दी जा सकती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यक भारत के अलावा अन्य किसी पड़ोसी देश में आसानी से शरण पा सकते हैं।

कांग्रेस समेत अन्य दलों का मानना है कि प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक भारतीय मूल्यों और खासकर पंथनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है, लेकिन आखिर वे इसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैं कि भारतीय कानून भारत के लोगों पर लागू होते हैं, न कि बाहर से गैर कानूनी तौर पर आए लोगों पर। अगर इस तथ्य को अनदेखा किया जाएगा तो फिर दुनिया भर के देशों से अवैध रूप से आए लोग यही मांग करेंगे कि उनमें और भारतीय नागरिकों में भेद न किया जाए। क्या यह मांग मानना संभव है?

भारतीय संविधान का समानता संबंधी कानून उन्हीं पर लागू हो सकता है जो भारतीय नागरिक हों। नागरिकता विधेयक का विरोध कर रहे दलों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह तय करने का अधिकार भारत के पास है कि वह किसे शरण अथवा नागरिकता दे या न दे? इस अधिकार का इस्तेमाल करते समय राष्ट्रीय हितों पर ध्यान देना आवश्यक है। क्या यह राष्ट्रीय हित में होगा कि पूर्वोत्तर भारत में बाहर से आए ऐसे लोगों को भी बसने दिया जाए जो स्थानीय संस्कृति के लिए खतरा बन रहे हैं? जो विपक्षी दल नागरिकता विधेयक का विरोध कर रहे हैं उन्हें यह समझना होगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों और वहां के बहुसंख्यकों को एक नजर से देखने का औचित्य नहीं बनता। बेहतर होगा कि इस विधेयक पर विचार करते समय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाए, न कि वोट बैंक की राजनीति को। यह राजनीति पहले ही देश का बहुत नुकसान कर चुकी है। जिन लाखों लोगों की पहचान घुसपैठियों के रूप में की जा चुकी है उनकी कानूनी हैसियत तय करना भी एक जटिल मसला है। इस मसले को सुलझाना ही होगा, क्योंकि इन लाखों लोगों को उनके मूल देश भेजना संभव नहीं। यह भी स्पष्ट है कि उन्हें लंबे समय तक शिविरों में रखना भी संभव नहीं। उचित यह होगा कि नागरिकता निर्धारण के उचित तरीकों पर आम राय बनाने के साथ ही इस पर भी सहमति कायम हो कि शरणार्थियों को क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए और क्या नहीं? नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे दलों को इससे भी परिचित होना चाहिए कि मोदी सरकार वही कर रही है जो करने का उसने वायदा किया था और जिसके लिए उसे जनादेश भी मिला।

response@jagran.com

तारीख पर तारीख पाता न्याय

हास्य-व्यंग्य

संतोष त्रिवेदी

'हम तो शपथ भी सत्य की खाते हैं। इसके बाद खाने को कुछ बचता ही नहीं।' सरेआम यह सुनकर सत्य भी शरमा गया

इन दिनों 'लोकतंत्र' और 'सत्य' लगातार खबरों में बने हुए हैं। इससे पुष्टि होती है कि ये दोनों अभी तक जीवित हैं। इसके बावजूद हर दूसरे दिन 'लोकतंत्र की हत्या' होने की मुनादी पिटती है, पर यह सशक्त लोकतंत्र का कमाल ही है कि वह अगले दिन सही-सलामत और दुरुस्त पाया जाता है। अचानक 'लोकतंत्र की जीत' होती है। कुछ ऐसा ही बेचारे 'सत्य' के साथ भी घटित होता है। जब भी लोकतंत्र को थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, वह सत्य का टॉनिक पी लेता है। 'सत्य' स्वाभिमानी होता है। वह सदन से उठकर पांचसितारा होटलों में सुकून की सांस लेता है और तब तो 'सत्य की जीत' जरूर होती है जब किसी आरोपी को सहसा 'न्याय' मिल जाता है।

अपना देश कोई आम लोकतंत्र नहीं है। जैसे देश का आखिरी आदमी मरते-मरते जी उठता है, ठीक वैसे ही अपना लोकतंत्र भी अंतिम सांस निकलने से पहले एकदम से चिहुंक उठता है। यह लोकतंत्र का चमत्कार ही है कि न्याय की आस में पीड़ित का दम निकलता है तो निकल जाए, पर 'न्यायिक-व्यवस्था' का बाल-बांका भी नहीं होता! दस साल में न्याय दस कदम भले न बढ़ पाए, मगर उसकी फाइलें नौ दिन में अढ़ाई कोस जरूर चल लेती हैं। अंधा होने के कारण कानून खुद नहीं देख पाता। इसीलिए व्यवस्था उसे 'टॉर्च' दिखाती है। वैसे 'सत्य' है भी बड़ा अनूठा। एक ही समय में वह सबके पास होता है। सबका अपना 'सत्य' होता है। यहां नींव भले असत्य की हो, लेकिन उस पर झंडा सत्य का ही फहरता है। साधक को जो दिखता है, वह सत्य होता है। जो नहीं दिखता वही असल सत्य होता है। इसमें एक और खास बात है। वह यह कि सत्य हमेशा 'सबल' होता है। बलवान के पास ही रहता है। निर्बल तो सत्य को परेशान करने की जहमत भी नहीं उठाता। बाहुबलियों को अपने सत्य पर पूरा भरोसा होता है। परम ज्ञानियों ने इन्हीं वजहों से इसे अपना जीवन-वाक्य बनाया है। इसमें एक बात कि सत्य को हमेशा प्रिय पसंद है। अप्रिय सत्य दुखकारी होता है। इसीलिए साधुजन सदैव सत्य बोलते हैं।

महान लोगों के 'सत्य' को स्थापित करने में जिस घटक की खास भूमिका है, वह है लोकतंत्र। यह ऐसा अभेद्य कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता। बड़े-बड़े संकट 'लोकतंत्र' की छतरी के नीचे समाधान पाते हैं। 'खतरे' सदैव सुरक्षित होते हैं और फलते-फूलते भी हैं। इसीलिए हमारा लोकतंत्र अब तक मजबूत बना हुआ है। सड़क से संसद तक इसके जबरदस्त पैरोकार हैं। यह रैलियों और भाषणों का सार होता है। चुनावों में इसे बड़े आदर से पूजते हैं। बाद में श्रद्धापूर्वक इसका आचमन भी किया जाता है। ये बड़ा संवेदनशील होता है। जरा सी बात पर 'हर्ट' हो लेता है और बड़ी बात पर संज्ञा-शून्य। आजकल 'प्राइम-टाइम' की सारी बहस इसी पर टिकी हुई हैं। वहां 'लोकतंत्र' और 'न्याय' में सीधी टक्कर चल रही थी। लोकतंत्र का कहना था कि 'न्याय' ने उसकी व्यवस्था में सीधा दखल दिया है जबकि उसे कुछ करने का नहीं, सिर्फ देखने का अधिकार है। यह उसकी 'अति-सक्रियता' है। ऐसे में लोकतंत्र कैसे चलेगा? 'सत्य' तो उसके साथ है। जीत भी उसी की होनी चाहिए। ऐसे ही चलता रहा तो अराजकता फैल जाएगी!

इस पर 'न्याय' ने भी अपने तर्क दिए। हम कब तक मूकदर्शक बने रहेंगे? इंसान हमारी ओर टकटकी लगाए देख रहा है। अब तो पट्टी-बंधी इन आंखों में दर्द भी होने लगा है। 'लोकतंत्र' का लोक लुप्त हो रहा है। यह सुनकर सत्य ने बगल में बैठी 'व्यवस्था' को कोहनी मारी। वह जोर से हंसी। कहने लगी, 'तुम सभी हमारे सहयोग के लिए बनाए गए हो। केवल काम करिए। सोचने का काम हमारा है। अगर हमें कुछ हुआ तो तुम एक भी नहीं बचोगे। रही बात आदमी की, यह सब उसके लिए नया नहीं है। 'लोकतंत्र' तो बना ही हम दोनों से है। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। हम तो शपथ भी सत्य की खाते हैं। इसके बाद खाने को कुछ बचता ही नहीं।' सरेआम ऐसे सत्यवचन सुनकर सत्य भी शरमा गया। वह पानी-पानी होता, इससे पहले ही लोकतंत्र ने बचा लिया। बहस देखता आदमी सकते में था। तभी न्याय ने तनिक झेंपते हुए कुछ कहना चाहा, पर उसे अगली तारीख मिल गई। इस तरह बहस में भी 'लोकतंत्र की जीत' हुई।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | देश के प्याज उत्पादन में राज्यों की हिस्सेदारी

(आंकड़े प्रतिशत में)

स्रोत: कृषि मंत्रालय

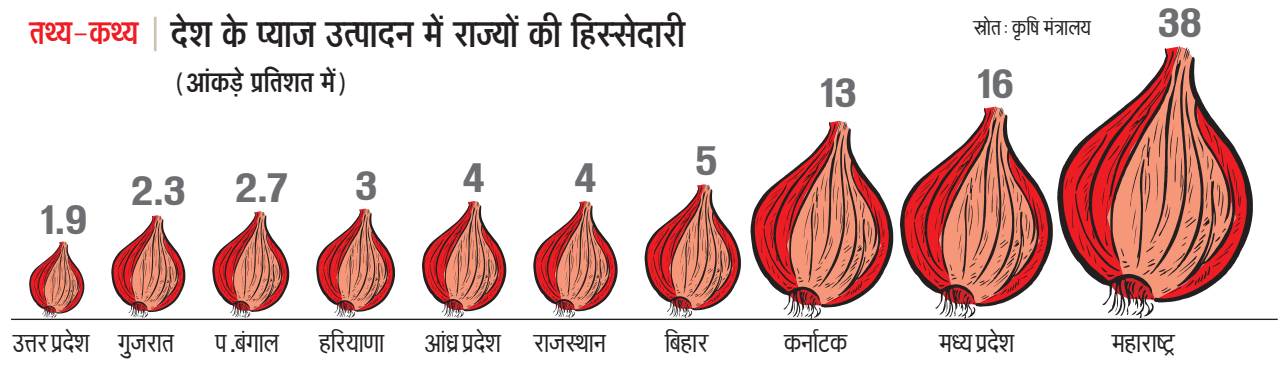

ऊर्जा

असफलता से सबक

जीवन में सफलता और असफलता का क्रम चलता रहता है। असफलता कुछ देर के लिए निराश व हतोत्साहित जरूर कर देती है, लेकिन यह हमें एक नया अवसर भी प्रदान करती है। अतः असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी माना जाता है। सफलता का असली आनंद भी असफलता के बाद ही आता है। वही व्यक्ति अपेक्षित एवं मनवांछित सफलता अर्जित कर पाता है जो अपनी गलतियों से सबक लेना जानता है। अक्सर कुछ लोग असफल होने के बाद अपने बचाव के लिए नाना प्रकार के बहाने गढ़ने लग जाते हैं। मसलन, मैं तो गरीब था। मेरे पास तो सुविधाओं की कमी थी। धन के अभाव में अच्छी कोचिंग नहीं ले सका आदि-इत्यादि। ऐसे ढेरों बहानों की आड़ में कुछ लोग अपनी असफलता को छिपाने व औरों की नजरों में सहानुभूति का पात्र बनने में लग जाते हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान रहते हैं कि असफलता भी एक पड़ाव है और उसका सफलता से बहुत गहरा सरोकार है।

बहानों के आवरण में अपनी असफलता को छिपाने वाले व्यक्ति न तो स्वयं कभी सफल हो पाते हैं और न ही किसी के लिए प्रेरणास्रोत बनते हैं। अपनी असफलता के बाद आंखों से पानी बहाने वाले सफलता के लिए पसीना बहाने की बात से कभी सहमत नहीं होते हैं। उनका जीवन अंधकार की गुहा सरीखा होकर रह जाता है। असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है भटकाव। आज अधिकांश छात्र इसीलिए सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे दिशाहीन होकर भटक जाते हैं। यह भटकाव उनको दिनोंदिन झूठे सपनों के साकार होने की आस में अपनी मंजिल से दूर करता जाता है। ऐसे लोग अपनी असफलता के लिए प्रायः यह कहते पाए जाते हैं कि आजकल नौकरियां कहां मिल पाती हैं? अब तो पुरुषार्थ के बजाय लोगों की पहुंच ज्यादा काम आती है। इन गलतफहमियों में जीने वाले न तो असफलता के बाद स्वयं का आकलन करते हैं और न ही अपने भटकाव को समझ पाते हैं। सोचिए कि अगर यही धारणा तमाम नवप्रवर्तकों ने अपनाई होती तो क्या वे मिसाल बन पाते।

देवेंद्रराज सुथार

अनोखे तारे और अनूठे ग्रह की जोड़ी

मुकुल व्यास

यह ग्रह दस दिन में अपने तारे की परिक्रमा पूरी करता है और इस दौरान मुख्य रूप से तीन गैसें उत्सर्जित करता है

वैज्ञानिकों को पहली बार एक 'मृत' तारे के इर्दगिर्द परिक्रमा करने वाले एक विशाल ग्रह का प्रमाण मिला है जो किसी तारे की मृतावस्था में रूपांतरण को झेलने में सफल रहा हो। इस दूरवर्ती ग्रह का प्रमाण गैस डिस्क से मिला है जो उसके वाष्पशील वायुमंडल से उत्पन्न हुई है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया नेप्च्यून यानी वरुण जैसा ग्रह संभवतः पृथ्वी के आकार जितने तारे से चार गुना बड़ा है। यह विशाल ग्रह प्रत्येक दस दिन में अपने तारे की परिक्रमा पूरी करता है। ऐसा करते हुए वह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर युक्त गैस छोड़ता है।

यह ग्रह जिस तरह के तारे की परिक्रमा कर रहा है उसे 'व्हाइट ड्वॉर्फ' कहा जाता है। यह दरअसल ऐसे तारों के अवशेष होते हैं जिनका आणविक ईंधन समाप्त हो चुका है। व्हाइट ड्वॉर्फ तारों का द्रव्यमान लगभग सूरज के बराबर होता है, लेकिन उनका अर्धव्यास पृथ्वी जितना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे बहुत ज्यादा घने होते हैं। व्हाइट ड्वॉर्फ तारे का आकार घटकर मूल तारे का सौवां हिस्सा ही रह जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके इर्दगिर्द चक्कर लगाने वाले ग्रहों को पहले की तरह गर्मी नहीं मिलेगी। किसी ग्रह को अपनी सतह पर तरल पदार्थ की मौजूदगी के लिए व्हाइट ड्वॉर्फ की परिक्रमा करते हुए जो दूरी रखनी होगी, वह पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी की तुलना में 75 गुना अधिक निकट होनी चाहिए।

नए ग्रह की खोज ब्रिटेन की वॉरविक यूनिवर्सिटी और अमेरिका की वेलप्राइसो यूनिवर्सिटी के खगोल वैज्ञानिकों ने की है। इसका विवरण 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों का दावा है कि किसी व्हाइट ड्वॉर्फ के इर्दगिर्द चक्कर लगाने वाले विशाल ग्रह का यह पहला प्रमाण है। उनका कहना है कि यह तारा पृथ्वी से करीब दो हजार प्रकाश वर्ष दूर है। 'डब्ल्यूडीजे 0914 + 1914' नामक तारे की पहचान 10,000 व्हाइट ड्वॉर्फ तारों के पर्यवेक्षण के दौरान की गई। शोधकर्ताओं ने चिली स्थित यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप का प्रयोग कर यह पता लगाया कि इस तारे और उसके इर्दगिर्द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर मौजूद हो सकते हैं। अध्ययन के प्रमुख लेखक और वॉरविक यूनिवर्सिटी के डॉ. बोरिस गेनसिक का कहना है, 'शुरू में हमने इसे दो तारों वाली प्रणाली समझा था, लेकिन गहन पर्यवेक्षण के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह दरअसल एक अनोखा तारा है। वेलप्राइसो यूनिवर्सिटी के डॉ. मैथियास श्राइबर ने हिसाब लगाया कि 28,000 सेल्सियस के तापमान वाला व्हाइट ड्वॉर्फ तारा बर्फीले ग्रह पर तीव्र ऊर्जा वाले फोटोन कणों की बमबारी से धीरे-धीरे उसे वाष्पित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तारे के पास एक ग्रह है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, लेकिन तारा इतना गर्म है कि वह ग्रह को वाष्पित कर रहा है और हम उस वायुमंडल को डिटेक्ट कर सकते हैं जिसे वह खो रहा है। पिछले दो दशकों के दौरान वैज्ञानिकों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि ग्रह तारों की व्हाइट ड्वॉर्फ अवस्था को झेल सकते हैं। इस संदर्भ में नई खोज महत्वपूर्ण है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

परिवार की परंपरा

राजनीति के बारे में अमूमन कहा जाता है कि यहां अपने भी पराये हो जाते हैं। इसकी तमाम मिसालें भरी पड़ी हैं, लेकिन अक्सर परिवारवाद के आरोपों से जूझने वाली लोजपा ने तो पारिवारिक स्नेह के मामले में अनूठा उदाहरण ही पेश किया है। रामविलास पासवान के पुत्र और अब लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान जब 2014 में लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे तो चाचा रामचंद्र पासवान ने उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित कराया था। बाद में जब रामविलास के दूसरे नंबर के भाई पशुपति पारस लोकसभा पहुंचे तो रामचंद्र ने उन्हें भी संसद से अवगत कराया। अब रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस उपचुनाव में जीतकर लोकसभा पहुचें हैं तो चिराग ने यह जिम्मेदारी खुद संभाली। मसलन नए नवेले सांसद के साथ आना, साथ जाना और संसद में चल रही कार्यवाही का पूरा अर्थ समझाना तथा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। खुद बिहार में ही जब राजद के अंदर परिवार में तीखी लड़ाई छिड़ी हो, हरियाणा में एक परिवार के लोग एक दूसरे की आंखों में खटक रहे हों तो लोजपा ने पारिवारिक कड़ियों को जोड़कर एक अलग ही मिसाल कायम की है।

सदन में ठहाके

संसद में तीखी नोकझोंक, नारेबाजी और हंगामा तो अक्सर होता रहता है, लेकिन ऐसे मौके कम ही आते हैं जब सदन में सदस्यों के बीच हंसी-ठिठोली की गूंज भी सुनाई देती हो। राज्यसभा में बीते दिनों ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि शून्यकाल के दौरान भाजपा के राज्यसभा सदस्य प्रभात झा ने मैथिली भाषा में बोलते हुए मैथिली भाषा को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने की मांग की। उन्होंने सभापति वेंकैया नायडू से कहा कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, ऐसे में आपके द्वारा इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। वैसे भी दिल्ली में बिहार के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, ऐसे में मैथिली भाषा पढ़ाई ही जानी चाहिए। खास बात यह रही कि झा ने मैथिली में ही धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त की। जैसे ही उनकी बात पूरी हुई, सभापति ने भी अपने अंदाज में कहा कि आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद..छे। (है) इसके बाद तो पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा।

नए माहौल में बदली जुबां

कूटनीति की दुनिया में वैसे तो अभी तक अंग्रेजी का ही बोलबाला रहा है जो बहुत हद तक स्वाभाविक भी है, लेकिन अब धीरे-धीरे हिंदी भी असर छोड़ने लगी है। कुछ साल पहले तक विदेश मंत्रालय के गलियारों में हिंदी का प्रचलन बेहद सीमित था। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कार्यकाल में इस मोर्चे पर भारी बदलाव दिखा। अब यह बदलाव इस कदर आकार ले रहा है कि दूसरे देशों के राजनयिक भी हिंदी बोलने लगे हैं। शुक्रवार को भारत दौरे पर पहुंचे लिथुआनिया के विदेश सचिव तलत केलप्सा ने एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी में बोलकर भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को भी अचंभित कर दिया। संतोष की बात यह रही कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विजय गोखले दोनों बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। गोखले ने तो केलप्सा के साथ कुछ देर हिंदी में ही बात की। पिछले महीने भारत की यात्रा पर आईं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी हिंदी बोलकर वाहवाही लूटी थी। इन दिनों कई विदेशी राजनयिक फिलहाल हिंदी सीखने की कोशिश में जुटे हैं।

वर्चस्व की लड़ाई

सत्ता संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार राजनीति है, जिसके जरिये वर्चस्व की लड़ाई परवान चढ़ती है। सियासी गलियारों में तो यह आम है, लेकिन अब इसकी तपिश नौकरशाही के हलकों तक पहुंच गई है। यह मामला कृषि भवन के एक बड़े मंत्रालय में दो आला अफसरों के बीच शीत युद्ध से जुड़ा हुआ है। वरिष्ठता क्रम को दरकिनार कर बैठने की होड़ तो रहती ही है। उनमें बड़ा ऑफिस और ऊंची कुर्सी पर कब्जा जमाने की प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। दरअसल, बड़े साहब के नजदीक काम करने वाले इन अफसरों में नेताओं की देखादेखी कुर्सी पर कब्जा करने की हसरतें जोर मारने लगीं। दोनों अफसरों के कमरे वैसे तो अलग-अलग हैं, लेकिन मौका देखकर एक साहब ने कमरा ही बदल लिया। बस अंदरूनी मतभेद गहराने लगा। मंत्रालय में इन अफसरों की आपसी शह-मात की चर्चा भी अब आम हो गई है। पीएस के कमरे में ओएसडी का कब्जा हो गया है, जिसे वह छोड़ने को राजी नहीं है। माना जा रहा है कि बड़े साहब के हस्तक्षेप के बाद ही मामला सुलझ पाएगा।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

50 वां स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है मैसूर स्थित भारतीय भाषा संस्थान का, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक संस्थान है। लेकिन इस महत्वपूर्ण संस्थान के निदेशक का पद खाली है।

अनंत विजय

आजकल

कला-संस्कृति को लेकर उदासीनता

देश के अधिकांश हिस्सों में रहने वाले लोग या देश की एक बड़ी आबादी कला-संस्कृति के प्रति भले ही संजीदा हो, लेकिन सरकार के स्तर पर शायद उस तरह की संजीदगी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि देश में कला-संस्कृति से जुड़ी ज्यादातर संस्थाओं के प्रमुखों का पद पिछले काफी समय से खाली पड़ा हुआ है। हालांकि इस तरह का सामाजिक विषय कम ही सरकारों की प्राथमिकता में रहा है, फिर भी मौजूदा सरकार द्वारा इस क्षेत्र के प्रति उदासीनता कुछ ज्यादा ही चिंता पैदा करती है

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली फाइल फोटो

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली फाइल फोटो

हाल ही में एक सेमिनार में जाने का अवसर मिला जहां समाजशास्त्रियों को सुना। इस सेमिनार में संस्थाओं के बनाने और उसको सुचारू रूप से चलाने पर बात हो रही थी। सभी वक्ता अपनी-अपनी बात तर्कों के साथ रख रहे थे। ज्यादातर वक्ता नई संस्थाओं को बनाने के लिए तर्क दे रहे थे, कुछ तो मौजूदा संस्थाओं को कैसे अच्छे से चलाया जाए और उनको मजबूत किया जाए, इस बारे में दलीलें दे रहे थे, और सलाह भी। सबसे दिलचस्प तरीके से बात रखी एक बेहद अनुभवी समाजशास्त्री ने, जिन्होंने कहा कि संस्थाओं को बनाने को लेकर बहुत सारी बातें हुईं, लेकिन वह इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि संस्थाओं को कैसे कमजोर किया जा सकता है और उन्होंने इसके दो प्रमुख अलिखित नियम बताए। उनका कहना था कि जब भी किसी संस्थान की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है तो इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। पहला अलिखित नियम यह कि संस्था के प्रमुख के पद पर किसी की नियुक्ति मत करो, वह संस्था धीरे-धीरे इतनी कमजोर हो जाएगी कि अपने गौरवशाली अतीत को भी खो देगी और भविष्य में उसको अपने बनाए मानदंडों तक पहुंचने में भी लंबा वक्त लगेगा। दूसरा औजार यह कि संस्था में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करो जिसकी उस काम में रुचि नहीं है जो दायित्व उसको दिया गया हो। उनकी बातों को सुनते-सुनते मेरे दिमाग में उन संस्थाओं के नाम घुमड़ने लगे जिनके प्रमुख का पद कई महीनों से खाली है और जिनको चलाने की जिम्मेदारी जिन पर है या जो उन संस्थाओं के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं।

यह माना जाता है कि मौजूदा सरकार शिक्षा और संस्कृति को लेकर बेहद संजीदा है और इन क्षेत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाता है। संस्कृति को लेकर बहुत बातें होती हैं, पर संस्कृति पर कितना ध्यान है इस पर आगे विचार किया जाएगा, लेकिन पहले हम समझ लें कि संस्कृति क्या है और उसका निर्माण कैसे होता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति पर गहराई से विचार किया है और उस पर काफी लिखा है। दिनकर ने लिखा है, 'संस्कृति ऐसी चीज नहीं है जिसकी रचना दस-बीस या सौ-पचास वर्षों में की जा सकती है। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते-पीते, पढ़ते-लिखते, सोचते-समझते और राज-काज चलाते अथवा धर्म-कर्म करते हैं, उन सभी कार्यों से उनकी संस्कृति उत्पन्न होती है। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। संस्कृति वह चीज मानी जाती है जो हमारे समग्र जीवन को व्यापे हुए है तथा जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ है। संस्कृति असल में शरीर का नहीं आत्मा का गुण है। सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है, तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म-जन्मांतर तक चलता रहता है।' दिनकर ने आगे लिखा है, 'संस्कृति के उपकरण हमारे पुस्तकालय, संग्रहालय, नाटकशाला और सिनेमागृह ही नहीं, हमारे राजनीतिक और आर्थिक संगठन भी होते हैं, क्योंकि उन पर भी हमारी रुचि और चरित्र की छाप होती है।'

जिन उपकरणों की ओर दिनकर जी ने इशारा किया है जरा हम उस पर विचार करें। हमारे यहां राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, इसकी बहुत प्रतिष्ठा है, यहां से पढ़कर निकले बहुत सारे कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से ना केवल इस संस्थान का नाम रोशन किया, बल्कि अभिनय कला को भी समृद्ध किया। यहां निदेशक का पद दिसंबर 2018 से खाली है यानी संस्था को चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी जिसकी है वह व्यक्ति यहां लगभग एक वर्ष से नहीं है। इससे भी दिलचस्प कहानी है यहां के अध्यक्ष की। रतन थियम का कार्यकाल 2017 में समाप्त हो गया और तब से यहां नियमित अध्यक्ष नहीं है और संस्था के उपाध्यक्ष डॉ. अर्जुनदेव चारण ही दायित्व संभाल रहे हैं। ये कहानी सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नहीं है। अब संस्कृति मंत्रालय से संबद्ध एक और महत्वपूर्ण संस्था राष्ट्रीय अभिलेखागार पर विचार करते हैं। यह संस्था भारत सरकार के सभी अभिलेखों की संरक्षक है। इस संस्था में सालों से नियमित महानिदेशक नहीं है। बीच में अल्प अवधि के लिए राघवेंद्र सिंह को यहां का प्रभार मिला था, लेकिन जल्द उनका भी तबादला हो गया। यहां का अतिरिक्त प्रभार संस्कृति मंत्रालय के अफसरों के पास है। एक और संस्था है राष्ट्रीय संग्रहालय। इस संस्था की जिम्मेदारी है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व की पुरावस्तुओं व कलाकृतियों का प्रदर्शन, सुरक्षा व शोध के प्रयोजन से संग्रहीत करना। इस संस्था के मुख्य कार्यकारी का पद खाली है। एक और बेहद महत्वपूर्ण संस्था है नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, और इस संस्था के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 15 अक्टूबर 2019 को इसके निदेशक का प्रभार राघवेंद्र सिंह को दिया गया है, वह भी छह महीने के लिए या जब तक नए निदेशक की नियुक्ति नहीं हो जाती। राघवेंद्र सिंह भारत सरकार में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही सीईओ, डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम और कल्चरल स्पेस का पद संभाल रहे हैं। नियमित निदेशक नहीं होने से कामकाज पर असर पड़ रहा है जिसकी झलक इसकी वेबसाइट को देखने से मिल सकती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कई संस्थाओं में भी उसके प्रमुख कार्यकारी नहीं हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक का पद भी खाली पड़ा है। इस सरकार को हिंदी को प्रमुखता देने के लिए भी जाना जाता है, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध एक संस्था है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसमें वर्षों से नियमित निदेशक नहीं हैं और इसका काम अतिरिक्त प्रभार के जुगाड़ से ही चल रहा है। मैसूर में स्थित भारतीय भाषा संस्थान अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रही लेकिन बगैर निदेशक के। इस संस्थान के निदेशक का पद रिक्त है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही एक संस्थान है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल। इसके निदेशक की जिम्मेदारी भी वहां के रजिस्ट्रार संभाल रहे हैं।

दिनकर जी ने पुस्तकालय, संग्रहालय, नाटकशाला और सिनेमागृह को संस्कृति के उपकरण के तौर पर रेखांकित किया है। उनके इन औजारों के आधार पर इस विवेचन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की संस्थाओं पर नजर डालें तो वहां भी कई संस्थानों में प्रमुख के पद खाली हैं। फिल्म समारोह निदेशालय में नियमित निदेशक का पद महीनों से खाली पड़ा है। इस संस्था के पास अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन से लेकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के आयोजन की जिम्मेदारी है। इसके अलावा भारतीय जन संचार संस्थान यानी आइआइएमसी के महानिदेशक का पद भी लंबे समय से खाली है। इस संस्थान की देश दुनिया में प्रतिष्ठा है, लेकिन इसके भी महानिदेशक के पद पर प्रभारी हैं। इसके अलावा दूरदर्शन के निदेशक का पद खाली है। आकाशवाणी के निदेशक का पद इसी महीने के अंत में खाली हो जाएगा। हालांकि ये दोनों पद विज्ञापित हो गए हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए भी ये पद खाली रहते हैं तो संस्थान के काम-काज पर तो असर पड़ेगा। क्या इन संस्थानों में यह व्यवस्था नहीं है कि एक व्यक्ति के कार्यकाल खत्म होने के पहले ही दूसरे की नियुक्ति हो जाए, जैसा गृह सचिव या कैबिनेट सचिव के पद के लिए होता है। इस बात पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जाना चाहिए कि इतने सारे संस्थानों के पद क्यों खाली हैं? क्या अफसर नहीं चाहते कि इन पदों को भरा जाए, क्योंकि इनके नहीं भरे जाने का लाभ उनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में मिलता है। या क्या मंत्रियों की रुचि नहीं है।

जिन मंत्रालयों के कामकाज से संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है या कहें कि संस्कृति के निर्माण में जिनकी भूमिका है उनके प्रति इस तरह की उदासीनता का ये आलम प्रश्नाकुल कर देता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको प्रदर्शित भी करें। इस कहावत को अगर हम अपनी संस्कृति से जोड़कर देखें और विचार करें तो यह कहा जा सकता है कि अगर हम अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं तो हमें इसका प्रदर्शन भी करना चाहिए। यह प्रदर्शन कैसे होगा इसका सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हम संस्कृति के प्रति गंभीर रहें, गंभीर दिखें।

फिर से

पुरुष भी अपनाएं मर्यादित आचरण

क्या महिलाओं के भीतर इच्छाएं नहीं होती हैं? क्या उनके भीतर काम भावनाएं जागृत नहीं होती हैं? सच तो यह है कि साथी ना होने पर भी महिलाएं बेहद सलीके से स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखती हैं। वे सामाजिक मर्यादा को बनाए रखती हैं। कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त ने एक घटना का जिक्र किया था। दरअसल एक कैब ड्राइवर अपनी एक महिला सवारी को ले जाते समय खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। कैब में सवारी के रूप में पीछे बैठी हुई महिला ने चुपचाप उसकी इस हरकत का वीडियो भी बनाया। ड्राइवर 'मास्टरबाथ' कर रहा था।

हैदराबाद की महिला पशु चिकित्सक या फिर दिल्ली की निर्भया ही नहीं, या उन्नाव की पीड़िता ही नहीं, देश भर में तमाम लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। कुछ मर जाती हैं, तो कुछ इसे जीवन का सच जान पचा जाती हैं। सेक्स कोई पाप नहीं, लेकिन इन अपराधियों के कृत को देखकर यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि उन्हें ऐसी सजा दी जानी चाहिए ताकि वे नपुंसक हो जाएं।

आखिर कभी ऐसा क्यों नहीं सुनाई देता कि किसी महिला ने पुरुष के साथ दुष्कर्म कर लिया। हर पुरुष को अपने भीतर महिलाओं सी सहनशीलता लानी चाहिए। प्रकृति महिला को हर माह कम से कम तीन दिन का कष्ट देती है। उन तीन दिनों के दौरान दर्द में भी वह घर की जिम्मेदारी, नौकरी पर काम करने से कभी इन्कार नहीं करतीं। पुरुष के पास तो ऐसा कोई कष्ट भी नहीं। फिर भी वह मानसिक रूप से कितना कमजोर होता है। मैंने कई पुरुषों को देखा है जो प्रेमिका से रिश्ता टूटने पर समाज में उसका उपहास उड़ाते हैं। इसके बदले में उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। पुरुष जानता है कि इज्जत की गठरी को महिला ही उठाएगी, और वह बिना कुछ कहे दूर हो जाएगी।

मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे देश-समाज में पुरुषों को घर से संस्कार मिलने बंद हो गए हैं। जबकि जरूरत इस बात की है कि उन्हें घर से कान मरोड़ कर ही निकालना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाओं में ईर्ष्या की भावना ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। एक वास्तविक उदाहरण से मैं इसे समझने का प्रयास कर रही हूं। दो सहपाठी लड़का और लड़की प्रेम में होते हैं। किसी कारणवश उनका रिश्ता दरकने लगता है। लड़की बात करना बंद कर देती है। वह जिंदगी में रोज एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी। लड़का उतनी मेहनत नहीं कर रहा था। वह हर स्थिति में लड़की को रोकना चाहता था। वह किसी भी तरीके से लड़की को पाना ही चाहता था। लड़की अडिग रहती है। आखिरी दांव के रूप में लड़का उसे ब्लैकमेल करना शुरू करता है। उसकी सभी यादों को मोहरा बनाता है। प्रेम में जो भी उसने अपने बारे में बताया, उसके साथ किया, उसे डिस्क्लोज करता है। इतना ही नहीं, उसने यहां तक आरोप लगाया कि लड़की शारीरिक व्यापार करके तरक्की कर रही है। लड़की सोच नहीं

प्रतीकात्मक

पा रही थी कि जिसे उसने चाहा, वह इस स्तर तक भी जाएगा। वह परेशान होती है। रोती है। इस घटना ने लड़की को और भी परिपक्व बना दिया। उसने जो निर्णय लिया था वह सही होता नजर आ रहा था। यह कहानी मेरी एक विद्यार्थी ने सुनाई।

आज देश भर में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों पर समाज को संजीदगी से सोचना होगा। हमारे आसपास बहुत से ऐसे नामर्द घूमते हैं जो परिचय बढ़ा कर इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। लड़की पढ़ेगी, लड़की बढ़ेगी, तो घर से बाहर भी तो निकलेगी। घर में बैठने के लिए तो वह शिक्षा नहीं हासिल कर रही है। मेरा अनुरोध इस सरकार से है कि प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, संस्थान आदि में पुरुषों की क्लास लगाई जाए। उन्हें खुद पर संयम रखना सिखाया जाए। इस समस्या का यही समाधान है। वरना लड़की के पढ़ने लिखने का कोई अर्थ नहीं।

(डॉ. सीमा सिंह की फेसबुक वॉल से साभार)

ट्वीट-ट्वीट

कुछ लोग दुष्कर्मियों का धर्म देखते हैं तो कुछ लोग उसकी जाति देखते हैं। कुछ इसी बात पर अटके रहते हैं कि अपराध किस पार्टी के शासन वाले राज्य में हुआ। ऐसे लोगों से बचकर रहिए। स्त्री का अपमान पूरी मानवता का अपमान है। इसमें भी जाति, धर्म और राजनीति को घुसाने वाले मानव नहीं, दानव हैं।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

हैदराबाद में हुई दुष्कर्म की घटना बहुत ही बर्बर थी, लेकिन जब कानून बनाने वाले ही एनकाउंटर का जश्न मनाने लगें तो यह चिंता का विषय है। मारे गए लोगों पर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। उन्हें कानून के हिसाब से ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी।
तवलीन सिंह @tavleen_singh

अपराधियों को मारना आसान है, लेकिन लोगों को ऐसी शिक्षा देना कठिन काम है कि वे जीवन में कभी अपराध का रास्ता ही अख्तियार न करें। आदतन हम लोग आसान रास्ता ही पकड़ते हैं।
तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

कुछ बड़े उद्यमी सरकार से खुलेआम कह रहे हैं कि अगर सरकारी मदद नहीं मिली तो उन्हें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। कल्पना करिए कि अगर देश के पंद्रह करोड़ किसान भी सरकार से दो-टूक ऐसा ही कह दें और वह दिन ज्यादा दूर भी नहीं कि वे केवल अपने खाने-पीने की वस्तुएं उगाएंगे। तब सरकार कितना आयात करके काम चलाएगी?
रमणदीप सिंह मान@ramanmann1974

जागरण जनमत
कल का परिणाम

क्या हैदराबाद दुष्कर्म के आरोपितों का एनकाउंटर करने से अपराधियों के मन में डर बैठेगा?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या न्यायिक प्रक्रिया में देरी हैदराबाद एनकाउंटर को मिले व्यापक जनसमर्थन की एक वजह है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

न्याय व्यवस्था यदि समय पर दे सकती न्याय,
तो काहे को ढूंढना पड़ता अलग उपाय।
पड़ता अलग उपाय न चुनती पुलिस 'बहाना',
सुन-सुनकर जो ऊब चुकी थी सबका ताना।
लोकतंत्र में 'लोक' चुने खुद अपना रस्ता,
उससे पहले काश! ठीक हो न्याय व्यवस्था!!
- ओमप्रकाश तिवारी

रचनाकर्म

दारा शुकोह का बहुविध व्यक्तित्व

जयप्रकाश पांडे

उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने वाले दारा शुकोह के बहुआयामी व्यक्तित्व और उनके समावेशी चरित्र को समेटती है यह किताब...

पुस्तक : दारा शुकोह, द मैन हू वुड बी किंग
लेखक : अवीक चंदा
प्रकाशक : हार्पर कालिंस, नोएडा
मूल्य : 699 रुपये

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉ. कृष्ण गोपाल ने दारा शुकोह को लेकर एक बात कही थी कि अगर उन्होंने भारत पर राज किया होता तो यहां इस्लाम बेहतर तरीके से पनपता और हिंदू भी इस्लाम को बेहतर तरीके से समझ पाते। कृष्ण गोपाल ने दारा शुकोह के समावेशी चरित्र को भी सामने रखा था और इस बात को भी रेखांकित किया था। कृष्ण गोपाल के उस बयान के बाद दारा शुकोह को लेकर, उनके चरित्र, कार्यों और रचनात्मकता को लेकर काफी बातें होने लगीं। लोग दारा शुकोह के बारे मे जानने को उत्सुक भी हुए। लगभग उसी वक्त या उससे कुछ बाद में अवीक चंदा की पुस्तक 'दारा शुकोह, द मैन हू वुड बी किंग' के नाम से प्रकाशित हुई।

दारा शुकोह शाहजहां के पुत्र थे और माना जाता था कि अपने पिता के बाद वही मुगल सल्तनत की बागडोर संभालेंगे, लेकिन औरंगजेब ने साजिश करके युद्ध में उनको परास्त कर दिया और मुगल सल्तनत पर कब्जा जमा लिया। उसके बाद की बातें इतिहास में दर्ज हैं। चूंकि दारा शुकोह बादशाह नहीं बन सके, इस वजह से उनके बहुत सारे काम कम ज्ञात रहे। अवीक चंदा की यह पुस्तक दारा शुकोह के व्यक्तित्व के उन पहलुओं को ही सामने लाती है। लेखक ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की है कि अगर दारा शुकोह मुगल सल्तनत की गद्दी संभालते तो क्या होता। क्या तब भारत की तस्वीर कुछ और होती या भारत इतनी जल्दी गुलाम नहीं होता? क्या इनके गद्दी संभालने से वैमनस्यता बढ़ती? ये ऐसे सवाल हैं, जिन पर पहले भी इतिहासकार मंथन करते रहे हैं। माना जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगलिया सल्तनत का विस्तार तो हुआ, लेकिन इस विस्तार की बुनियाद औरंगजेब की क्रूर नीतियां बनीं। इसके अलावा औरंगजेब को मंदिरों को तोड़नेवाला, तानाशाही बादशाह, भाई का कातिल और धार्मिक असहिष्णुता का पैरोकार माना गया।

अवीक चंदा ने इस किताब में दारा शुकोह की जिंदगी और पिता शाहजहां की विरासत पर विचार किया है। इस पुस्तक में लेखक ने दारा शुकोह की जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों को समेटने की कोशिश की है। इसमें उनका बचपन भी है। दारा शुकोह को मुमताज महल ने वर्ष 1615 में जन्म दिया। वह जीवन के अंत तक अपने पिता के बेहद करीब रहे। फिर उनकी जिंदगी का खूबसूरत दौर आता है, जिसमें उनकी शादी नादिरा बेगम के साथ होती है। फिर दारा शुकोह की जिंदगी में वह दौर भी आता है, जब वह अपने पिता की सेना के कमांडर थे और पुस्तकों से दूर थे। उस दौर में उनकी मानसिकता को लेखक ने सूक्ष्मता से पकड़ा है। लेखक का मानना है कि दारा शुकोह युवावस्था में अपने पिता के साथ छाया की तरह रहते थे, कह सकते हैं कि परोक्ष रूप से वही राजकाज संभालते थे।

किताब में चंदा ने मुगल सल्तनत के दौरान उत्तराधिकार के खूनी जंग को भी विश्लेषित किया है और इस बात को भी रेखांकित किया है कि बड़े लड़के के पास स्वतः बादशाह होने का हक नहीं आ जाता था। इस क्रम में वह शाहजादा खुर्रम के बादशाह शाहजहां बनने में हिंसक तौर-तरीकों का जिक्र भी करते हैं।

आधुनिक बुद्धिजीवी दारा शुकोह का एक ऐसे विद्वान के तौर पर रेखाचित्र प्रस्तुत करते हैं, जहां वह एक सूफी भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, अपने लेखन में इतिहास के कालखंड को क्रम भी देते हैं और कला के संरक्षक के तौर पर भी उभरकर सामने आते हैं। पुस्तक को पढ़ने के बाद पाठकों को इस बात का एहसास होता है कि दारा शुकोह का मूल्यांकन युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के अलावा सामाजिक क्षेत्र में हो सकता है। दारा शुकोह ने जिस बहुलतावादी समाज की परिकल्पना की थी, उसे उनकी रचना 'मजमा-उल बहरैन' में देखा जा सकता है। इसके अलावा दारा शुकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, हालांकि उनके जीवन काल में उनके इस काम को तवज्जो नहीं मिली, लेकिन जब अठाहरवीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी विद्वान ने इसका लैटिन में अनुवाद किया तो दुनिया की नजर इस काम पर गई। कुल मिलाकर, इस पुस्तक को पढ़कर दारा शुकोह के बहाने मुगल सल्तनत के विशेष कालखंड का इतिहास भी सामने आता है।

वायु का नायकत्व स्थापित करता काव्य

अमित तिवारी

पुस्तक : वायु पुरुष
कवि : उपेंद्र कुमार
प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ
मूल्य : 250 रुपये

वायु अर्थात प्राण तत्व। जीवन के लिए जरूरी पंच महाभूतों में से एक है वायु। माना जाता है कि जीवन में जो गति है, वह वायु की ही देन है। ऐसे में जीवन का इतना महत्वपूर्ण घटक होने के बाद भी साहित्य में वायु को नायक के रूप में यथोचित स्थान नहीं मिलना एक कमी का बोध कराता है। कवि उपेंद्र कुमार ने इसी कमी को भरने का प्रयास किया है अपने प्रबंध काव्य 'वायु पुरुष' के माध्यम से।

दो गजल संग्रह और नौ कविता संग्रह प्रकाशित करा चुके उपेंद्र कुमार ने इस प्रबंध काव्य से एक नया आयाम रचने का प्रयास किया है। उन्होंने एक अलग लीक पर चलते हुए वायु को नायक के रूप में चुना है। इस प्रबंध काव्य का नायक 'वायु पुरुष' अपने भीतर नायकत्व और देवत्व के समस्त गुण संजोए हुए है। यह नायक प्रेम रस में पगा है, तो साथ ही वीरता भी इसके पोरों में बसी है। यह वायु पुरुष पक्षियों, पौधों, शाखाओं, बादलों, नदियों को अपने आलिंगन में भरकर प्रेम करना जानता है। उसके प्रेम से प्रकृति का विस्तार होता है। प्रबंध काव्य का यह नायक स्वाभिमानी भी है। उसे अपना अपमान स्वीकार नहीं है। यही कारण है कि प्रकृति से खिलवाड़ में लगे मानवों पर यह नायक क्रोध भी बरसाता है।

कवि ने बहुत सुंदर तरीके से वायु या पवन देवता से जुड़ी मिथकीय कथाओं को नवीन रूप में ढाला है। वह वायु पुराण से लेकर मिस्र की लोक कथाओं तक का जिक्र करते हैं। उनका काव्य कुंती से लेकर मां अंजना तक की गाथाओं को समेटता है। इसका हर सर्ग नायक के कद को बड़ा करता जाता है। साथ ही इसके नए-नए रूप भी दिखाता जाता है।

कवि ने अपनी कलम को केवल कथाओं तक नहीं समेटा, बल्कि वह वर्तमान समस्याओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट करते हैं। वह सभ्यता की सीमा पार कर गई मानवजाति को भी संभलने के लिए चेताते हैं। मानवों के व्यवहार से व्यथित उनका नायक जब क्रोध में होता है, तो बिना तबाही के उसका क्रोध शांत नहीं होता। तूफान और चक्रवात के सामने स्वयं को सृष्टि की सर्वोत्तम रचना मानने वाला मानव घुटने टेक देता है। 'वायु पुरुष' प्रबंधकाव्य इसलिए भी पठनीय है, क्योंकि यह वायु को समझने की नई दृष्टि देता है।

फिर सियासत के केंद्र में आ गया किसान

आशीष व्यास
संपादक, नई दुनिया, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

मध्य प्रदेश के सियासी समीकरणों में किसान को केंद्र में रखकर राजनीति करना कोई नई बात नहीं है। किसानों के जरिये लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीतने वाली पूर्व भाजपा सरकार किसान कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा करती रहती थी। खेत-खलिहान से अपने सरोकारों को सिद्ध करने में जुटी कांग्रेस सरकार ने भी किसान कर्ज माफी के रास्ते ही सत्ता के सिंहासन पर कब्जा किया। लेकिन दूर देहात से लेकर नगरों-कस्बों से आ रही खबरें किसानों के असंतोष को बार-बार सामने ला रही हैं।

बीती बारिश में बादलों का कहर झेल चुके किसान अब यूरिया खाद की कमी से परेशान हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में यूरिया का संकट बना हुआ है। किसान जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं। हालात यह हो गए हैं कि खाद वितरण करवाने के लिए पुलिस-प्रशासन की मदद लेनी पड़ रही है। सरकार का दावा है कि अब तक 18 रैक से ज्यादा यूरिया आ चुका है और 11 दिसंबर तक 49 रैक यूरिया और आ जाएगा। उधर, राज्य में गहराते यूरिया संकट को लेकर भाजपा ने प्रदेश सरकार के दावों पर सवाल उठाया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव किसानों के पक्ष में खड़े नजर आए जब उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि यूरिया संकट से किसान परेशान नहीं हैं। तो फिर किसानों को यूरिया के बदले लाठियां क्यों मिल रही हैं? क्यों यूरिया के लिए किसानों की कतारें लग रही हैं? पुलिस थानों से यूरिया क्यों बांटा जा रहा है?' बयानों की इस राजनीतिक लड़ाई में सरकार का बचाव करने सामने आए कृषि मंत्री सचिन यादव ने दावा किया, 'इस वर्ष पिछले वर्ष से ज्यादा यूरिया आ रहा है। भोपाल में किसानों की शिकायत और समस्याओं को जानने के लिए राज्य स्तरीय यूरिया वितरण शिकायत कक्ष भी बना दिया गया है।'

दरअसल इस पूरी राजनीतिक लड़ाई के पीछे श्रेय का संघर्ष ज्यादा है। भाजपा अपने रणनीतिक प्रबंधन के जरिये यह प्रयास करने में जुटी है कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने में लगातार असफल हो रही है। भाजपा नेताओं द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि कर्ज माफी की तरह यूरिया संकट भी गंभीर है और सरकार दिखावे की कार्रवाई कर केवल औपचारिकता निभा रही है। यूरिया के बहाने प्रदेश में शुरू हुई इस नई सियासत का केंद्र इस बार राजधानी भोपाल नहीं है। प्रदेश में जारी खाद किल्लत को लेकर

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदर्शन करने बीते शुक्रवार को सागर पहुंचे। उन्होंने यूरिया की समस्या को लेकर धरना दिया, जनसभा को संबोधित करने के बाद गिरफ्तारी भी दी। शिवराज सिंह ने कहा कि जब क्षेत्रीय विधायक (प्रदीप लारिया- नरयावली विधानसभा) किसानों के साथ उनकी मांगों को लेकर धरना देते हैं तो सरकार उन पर एफआइआर दर्ज कर डराने का प्रयास करती है। स्वाभाविक है कि किसानों के हक की यह लड़ाई राजधानी के बजाय अब सागर जैसे संभाग-जिलों तक पहुंचने लगी है। सागर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार ज्यादा आक्रामक नजर आए।

किसानों के पक्ष में सड़कों पर उतरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम इस प्रयास में है कि यूरिया संकट के बहाने फिर से कमलनाथ सरकार के वादों-इरादों की पोल खोल सके। सागर में प्रदर्शन के दौरान शिवराज सिंह ने बिजली बिलों को आग लगाकर ऐलान किया कि 100 रुपये से ज्यादा बिल आया, तो ऐसे बिलों में आग लगाएंगे। यदि किसानों की बिजली काटी तो भाजपा नेता जोड़ने जाएंगे। एक वर्ष पूरा कर रही कमलनाथ सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का यह सामूहिक हमला पहली बार मध्य प्रदेश में सक्रिय विपक्ष की उपस्थिति का अहसास करवा रहा है।

ताई का राजनीतिक तालमेल : 'मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तब अहम मुद्दों को लेकर मैं चुप रहती थी, क्योंकि यह मेरी ही पार्टी (भारतीय जनता पार्टी) की सरकार थी। लेकिन जब मुझे लगता था कि इंदौर की जनता के हित के लिए कुछ मुद्दों को उठाना चाहिए, तो मैं कांग्रेस के नेताओं का सहारा लेती थी।' मध्य प्रदेश के राज्यपाल की मौजूदगी में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस 'राजनीतिक-रहस्य' को खोलते हुए भोपाल से दिल्ली तक तालमेल की राजनीति को चर्चा का नया विषय बना दिया। बयान की राजनीतिक विवेचना शुरू हो जाए इससे पहले ताई अपनी बात आगे बढ़ा चुकी थीं, 'मेरी सरकार के खिलाफ मैं नहीं बोल सकती थी। लिहाजा कोई बात उठाने के लिए मैं जीतू पटवारी और तुलसी सिलावट को धीरे से कहती थी कि तुम करो कुछ।' दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने अपने घर में संवाद का एक कार्यक्रम रखा था। इसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद थे। इसी दौरान ताई ने बिना लागलपेट के यह बात कही थी।

सूचीबद्ध होने लगे माफिया! क्या कमलनाथ सरकार ने माफियाराज खत्म करने का निर्णय ले लिया है? हनीट्रैप के दौरान सामने आए इंदौर के माफिया जीतू सोनी के खिलाफ हुई कार्रवाई से यह सवाल अब प्रदेश में हर कहीं पूछा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब माफिया का राजनीतिक रसूख सरकार पर नहीं चलेगा। जो भी दोषी सामने आएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चर्चा इस बात की भी ज्यादा है कि इंदौर के साथ भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में सक्रिय बड़े माफियाओं को सूचीबद्ध भी किया जा रहा है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा पहले ही दोहरा चुके हैं कि प्रदेश में जो भी कानून हाथ में लेगा, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सरकारी तंत्र में अचानक आई यह सक्रियता उम्मीद तो जगा रही है कि कठोर निर्णय आगे भी लिए जाएंगे। अब देखना केवल यह है कि यह ईमानदारी कब तक बनी रहती है?

133 साल पुराने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ज्यादा पर्यटक गुजरात स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ रहे हैं रोजाना। सरदार सरोवर नर्मदा निगम के मुताबिक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने औसतन 15,036 पर्यटक रोजाना पहुंचते हैं, जबकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को रोजाना करीब 10 हजार लोग देखते हैं।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 8 दिसंबर 2019

सर्वेंट क्वार्टर से तय किया जज की कोठी का सफर

इनसे मिलिए

कुमार रजत, पटना

नवंबर के आखिरी सप्ताह में जब 2018 में हुई 30वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा का परिणाम जारी हुआ तो बिहार का एक घर खुशियों से महक उठा। अदालत से इस परिवार का संबंध दशकों पहले से रहा, लेकिन इस बार कहानी बदल गई। कभी जिस परिवार का मुखिया अदालत में चपरासी था, आज उसी परिवार की बिटिया जज बन गई। सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर जज की कोठी तक पहुंचने की यह कहानी है पटना के हनुमान नगर की रहने वालीं अर्चना कुमारी की। उनके सफर में तमाम उतार-चढ़ाव और रुकावटें आईं, लेकिन बचपन में देखा सपना मन में ऐसा बसा था कि उसे पूरा करके ही दम लिया। आज वह बिहार में 'जज बिटिया' के नाम से जानी जा रही हैं।

अर्चना के सफर की शुरुआत होती है सोनपुर रेलवे कोर्ट से, जहां उनके पिता गौरीनंदन प्रसाद चपरासी थे। अर्चना बताती हैं, 'छह सदस्यों का हमारा परिवार एक कमरे के सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। क्वार्टर के सामने ही जज साहब की कोठी थी। पिता जी दिनभर जज साहब के पास खड़े रहते। बस, न्यायाधीशों को मिलने वाला सम्मान ही मेरे मन में घर कर गया। तभी मैंने जज बनने का सपना पहली बार देखा।'मूल रूप से पटना से सटे धनरूआ के मानिक बिगहा गांव की अर्चना ने सपना तो देख लिया, लेकिन उसे पूरा करना आसान नहीं था। वह कहती हैं, 'बचपन में ही मुझे अस्थमा हो गया। अक्सर बीमार रहने लगी। घर में कमाने वाले एक और खाने वाले छह लोग। नतीजा, पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। हालांकि, पिता जी ने पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी।'

पति राजीव रंजन के साथ अर्चना। सौजन्य : अर्चना

अगर सपना सच्चे दिल से देखा जाए और उसे पूरा करने के लिए इरादा मजबूत हो तो सारी कायनात उस सपने को पूरा करने में आपका सहयोग करती है। ऐसा ही हुआ बिहार की **अर्चना कुमारी** के साथ, जिन्होंने बचपन में पिता को जज के चपरासी के रूप में देख खुद जज बनने का सपना देखा...इतना संघर्ष किया कि जिंदगी की तमाम चुनौतियों ने घुटने टेक दिए और उन्हें पहुंचा दिया जज की कुर्सी तक...

...पिता का जाना : अर्चना ने पटना के शास्त्री नगर राजकीय कन्या उच्च विद्यालय से 12वीं की और पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हर इंसान के सामने ऐसे कई पल आते हैं, जब जिंदगी उसकी परीक्षा लेती है। अर्चना के सामने वह बुरा समय 2005 में आया। वह कहती हैं, 'स्नातक के आखिरी वर्ष 2005 में पिता जी की मृत्यु हो गई। उनकी पेंशन से घर खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए पढ़ाई जारी रखने के लिए मैं उसी स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाने लगी, जहां से मैं खुद पढ़ी थी। समय का चक्र एक बार फिर घूमा। मेरी उम्र 21 साल हो गई थी। तीन बहनों में सबसे बड़ी थी, तो घरवालों ने शादी तय कर दी। लगा कि पढ़ाई अब छूट जाएगी। घर-परिवार को सही से चला लूं, यही असली शिक्षा होगी।'

पति के सहयोग से जारी रही पढ़ाई : अगर सपना सच्चे दिल से देखा जाए और उसे पूरा करने के लिए इरादा मजबूत हो तो सारी कायनात उस सपने को पूरा करने में सहयोग करती है। अर्चना के साथ भी ऐसा ही हुआ। पटना मेडिकल कॉलेज में क्लर्क पद पर कार्यरत राजीव रंजन से उनकी शादी 2006 में हो गई। राजीव बताते हैं, 'शादी के समय अर्चना ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रही थी। उसमें पढ़ने की ललक देखकर मुझे महसूस हो गया था कि यह जीवन में कुछ अच्छा करेगी, इसलिए मुझसे जो बन सका मैंने किया। आज बेहद खुश हूं कि उसने छह साल की उम्र में जो सपना देखा था, वो पूरा हो गया।' अर्चना के शादी के बाद के सफर के बारे में राजीव बताते हैं, 'शादी के तुरंत बाद वह पुणे यूनिवर्सिटी से लॉ करने चली गई। वह शुरू से हिंदी मीडियम से थी और वहां का माहौल अंग्रेजी वाला था। इसलिए शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हुई। कुछ रिश्तेदारों ने तंज भी कसा, जिससे वो टूटी नहीं, बल्कि उसके हौसले और बुलंद होते चले गए। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2011 में अर्चना पटना लौटी। 2012 में हम माता-पिता बने। अर्चना ने कभी भी अपने सपने को मातृत्व पर हावी नहीं होने दिया। दोनों में संतुलन बनाकर चली।'

दिल्ली में छात्रों को लॉ पढ़ाकर पूरी की अपनी पढ़ाई : लॉ के साथ अर्चना प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रही थीं। मंजिल पाने का सफर उन्हें एक बार फिर पटना से बाहर ले गया। पांच माह के बेटे और विधवा मां को साथ लेकर दिल्ली आ गईं। एलएलएम की पढ़ाई के साथ वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी लगी रहीं। आर्थिक भार के कारण उनकी पढ़ाई न छूट जाए, इसलिए एक संस्थान में छात्रों को लॉ पढ़ाकर दिल्ली में रहने-खाने का खर्च निकालने लगीं। लगातार संघर्ष का परिणाम रहा कि उन्होंने 30वें बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में सामान्य श्रेणी में 227वीं और ओबीसी श्रेणी में 10वीं रैंक हासिल की।

भगवान ऐसी बेटी सबको दे

कभी पति को जज के चपरासी के रूप में देखने वाली प्रतिमा देवी ने जब बेटी अर्चना को जज बनते देखा तो उनके लिए यह किसी स्वप्न के साकार होने से कम नहीं था। वह खुद तो सातवीं तक पढ़ी हैं, लेकिन बेटी का सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह कहती हैं, 'आज अगर अर्चना के पापा जिंदा होते तो खुशी से फूले नहीं समाते। अर्चना ने पूरे परिवार का मान बढ़ाया है। ऐसी बेटी भगवान सबको दे।'

धाकड़ व्यक्तित्व के धनी धनखड़

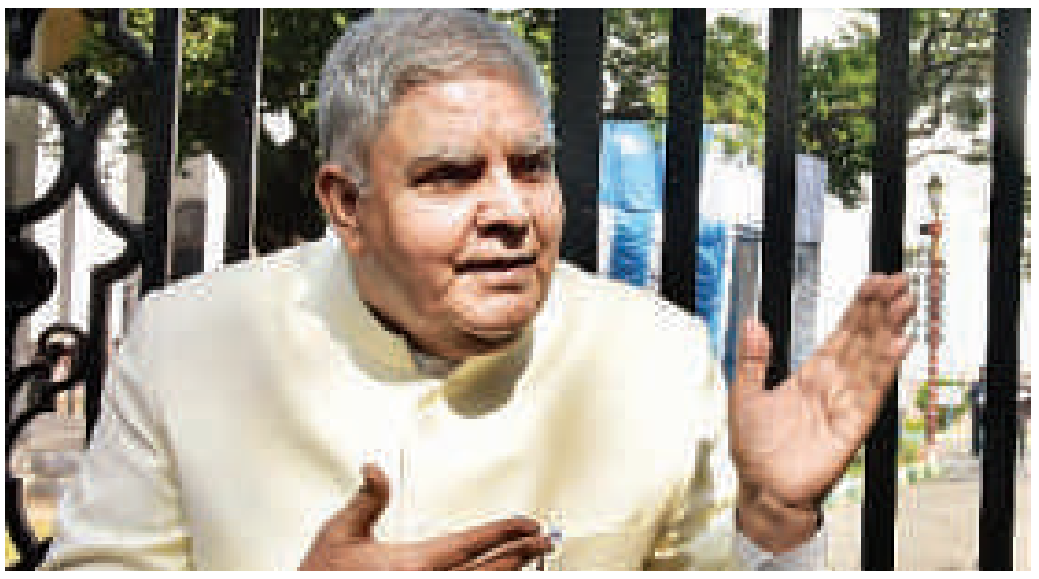

जगदीप धनखड़ जब से बंगाल के राज्यपाल बनाए गए हैं, तब से वह राज्य की सियासत के केंद्र में बने हुए हैं। फाइल

चर्चित चेहरा

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच रिश्तों में तल्खी सुर्खियों में है। ममता को उनके तीखे तेवरों के लिए जाना जाता है, लेकिन धनखड़ ने जैसा रुख दिखाया है उससे नहीं लगता कि वह किसी के दबाव में आने वाले हैं। बीते दिनों बंगाल विधानसभा के बाहर इसी के चलते एक अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला...

बंगाल की राजनीति इन दिनों दो लोगों के इर्दगिर्द घूम रही है। ये दो शख्सियतें हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी। धनखड़ राज्यपाल की सामान्य छवि से एकदम अलग नजर आ रहे हैं-सक्रिय और बेबाक। उनके इस अंदाज ने राज्य में सरकार बनाम राज्यपाल की स्थिति पैदा कर दी है। बंगाल सरकार ने पिछले दिनों यह आरोप लगाते हुए विधानसभा को दो दिन स्थगित कर दिया कि राज्यपाल ने अहम विधेयकों पर दस्तखत नहीं किए हैं। राज्यपाल ने जवाब दिया कि उनके पास कोई बिल लंबित नहीं है। खबर राष्ट्रीय सुर्खी बनी और जब अगले दिन राज्यपाल विधानसभा में प्रवेश करना चाहते थे तो उन्हें वीआइपी गेट बंद मिला। मजबूरी में उन्हें सामान्य गेट से अंदर जाना पड़ा। गेट के बाहर खड़े राज्यपाल की यह तस्वीर भी मीडिया में छाई रही।

दरअसल, मुखर मिजाज, आक्रामक शैली और त्वरित निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता 68 वर्षीय धनखड़ को पिछले राज्यपालों से अलग करती है। वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका को नया आयाम देना चाहते हैं। खुद को राजभवन के आलीशान कमरों व सभा-समारोहों में फीते काटने तक सीमित रखना नहीं चाहते, बल्कि राज्य के कोने-कोने में जाकर जनप्रतिनिधियों व जनता से मिलना चाहते हैं। ममता की पहचान भी अपनी बात आक्रामक तरीके से रखने वाले राजनेता की है। सियासत की उनकी अपनी शैली है और राजनीति को जानने-समझने वाले लोगों को पता है कि ममता की जिद दूर तक जाती है। वह राज्यपाल की सक्रियता को अपने अधिकारों में दखल और केंद्र सरकार की साजिश के रूप में देख रही हैं।

धनखड़ को करीब से जानने वाले बताते हैं कि सैनिक स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने के कारण अनुशासन, दृढ़ निश्चय व नेतृत्व क्षमता जैसे गुण उनमें बचपन से भरे हुए हैं। वह एक बार जो निश्चय कर लेते हैं, उससे पीछे नहीं हटते। त्वरित निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता के साथ ही किसी भी विषय पर त्वरित प्रतिक्रिया देना उनके व्यक्तित्व का विशेष गुण हैं। हाल ही में उन्होंने बेबाकी से कह दिया कि वह न तो रबर स्टांप हैं और न ही पोस्ट ऑफिस। धनखड़ औचक दौरे के लिए भी मशहूर हैं। बंगाल में राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद ऐसे कई मौके देखे गए जब वह अचानक से कहीं पहुंच गए हों। फिर चाहे जादवपुर विश्वविद्यालय पहुंचकर आंदोलनकारी छात्र-छात्राओं के बीच फंसे केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को छुड़ाकर लाना हो, सुबह ट्रैक सूट में विक्टोरिया मेमोरियल जाकर प्रातः भ्रमणकारियों से मुलाकात करना हो या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से टकराव की स्थिति होने के बावजूद उन्हीं की पार्टी के नेता और हावड़ा के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती की मां के निधन की खबर पाकर उनके घर जाकर सांत्वना देना हो-राज्यपाल ने हर बार चौंकाया। धनखड़ से मुलाकात कर चुके लोग उन्हें भारी-भरकम शरीर में बसने वाला नरम मिजाज इंसान करार देते हैं। धनखड़ मिलनसार और सुलझे हुए इंसान हैं भी। वह लोगों से गर्मजोशी से मिलते हैं।

राजस्थान की माटी से गहरा जुड़ाव : 18 मई, 1951 को राजस्थान के झुंझनूं जिले के छोटे से गांव किथाना में जन्मे धनखड़ का अपनी माटी से गहरा जुड़ाव है। उनके व्यक्तित्व में राजस्थानी संस्कृति की गहरी छाप दिखती है। गांव के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा के बाद सैनिक स्कूल, चितौडगढ़ और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। फिजिक्स में बीएससी (ऑनर्स) के बाद एलएलबी की पढ़ाई की। अपने जन्मस्थल झुंझनूं से वह 1989 से 1991 तक जनता दल के सांसद भी रहे हैं। उसी दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री का भी पदभार संभाला। 1993 से 1998 तक राजस्थान की किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक भी रहे। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पद भी बखूबी संभाल चुके हैं। धनखड़ बंगाल की संस्कृति से भी खासे प्रभावित हैं। बंगाल के गौरवशाली इतिहास का वह गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। परिवार में पत्नी सुदेश धनखड़ और विवाहिता पुत्री कामना हैं।

बिना अंतरराष्ट्रीय मैच खेले दुनियाभर में मिली पहचान

सुर्खियों में

वरुण आनंद, नई दिल्ली

आज क्रिकेट की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। भारत की पूर्व क्रिकेटर **जीएस लक्ष्मी** यूएई में विश्व कप लीग दो की तीसरी सीरीज के शुरुआती मैच में पुरुष वनडे में रेफरिंग करेंगी और इसी के साथ यह कीर्तिमान स्थापित करने वाली वह पहली महिला रेफरी बन जाएंगी। इसे एक सहयोग ही कहा जाएगा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक भी मैच नहीं खेला, लेकिन क्रिकेट ने ही उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। आइए जानते हैं उनके क्रिकेटर और क्रिकेटर से रेफरी बनने के सफर के बारे में...

जीएस लक्ष्मी फाइल

क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें भारत की बादशाहत को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। अब इसी कड़ी में एक और कीर्तिमान देश के नाम जुड़ने जा रहा है। भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर गंडीकोटा सर्वा लक्ष्मी रविवार को संयुक्त अरब अमीरात में विश्व कप लीग दो की तीसरी सीरीज के शुरुआती मैच के साथ पुरुष वनडे में मैच रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन जाएंगी। लक्ष्मी यूएई-अमेरिका के बीच शारजाह स्टेडियम में होने वाले मैच में रेफरी होंगी। 51 साल की लक्ष्मी की यह इस साल की दूसरी बड़ी उपलब्धि है। वह मई में मैच रेफरियों के आइसीसी के अंतरराष्ट्रीय पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थीं।

आज क्रिकेट की दुनिया में निर्णायक की भूमिका में दिख रहीं जीएस लक्ष्मी लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। साथ ही उन्होंने बतौर कोच खिलाड़ियों को तराशने का काम भी किया है। 23 मई, 1968 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी लक्ष्मी के पिता जमशेदपुर में टाटा मोटर्स (उस समय टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी) में कार्यरत थे। इसलिए इनका पालन-पोषण जमशेदपुर में हुआ। यहीं उनका क्रिकेट से जुड़ाव शुरू हुआ। क्रिकेट ने न केवल उन्हें पहचान दिलाई, बल्कि इसी खेल ने कॉलेज में उनके प्रवेश का रास्ता बनाया। दरअसल, लक्ष्मी का मन क्रिकेट में इतना रमता था कि पढ़ाई का ध्यान ही नहीं रहता। यही वजह थी कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बेहद खराब अंकों के कारण 1986 में जमशेदपुर वूमेंस कॉलेज ने उन्हें दाखिला देने से इन्कार कर दिया। यहां क्रिकेट ने ही उनका साथ दिया। पिता के आग्रह पर स्पोर्ट्स कोटा से उन्हें दाखिला मिला। अपने जीवन के उस अहम पड़ाव को याद करते हुए वह बताती हैं कि मैं अपने भाइयों और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलती थी। मेरे बॉलिंग एक्शन और स्किल को जब कॉलेज वालों ने देखा तो स्पोर्ट्स कोटे से दाखिला देने को राजी हो गए।'

लंबा रहा है घरेलू क्रिकेट का सफर : लक्ष्मी ने कई घरेलू टीमों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, रेलवे, पूर्वी जोन और दक्षिणी जोन की ओर से 1989 से 2004 तक क्रिकेट खेला। 1991 में जिस दिन उनकी शादी थी, उसी दिन रेस्ट ऑफ इंडिया टीम के लिए बुलावा आया, लेकिन उन्होंने क्रिकेट से कुछ वक्त के लिए विश्राम लेने का फैसला किया। 1995 में दक्षिण मध्य रेलवे के साथ क्रिकेट में वापसी की और अपनी टीम को पहली बार इंटर-रेलवे खिताब दिलवाने में अहम योगदान दिया। 1999 में उन्हें भारत की राष्ट्रीय महिला टीम में शामिल किया गया। वह इंग्लैंड के टूर पर गईं, लेकिन उन्हें मैच खेलने का मौका नहीं मिला। 2004 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया।

संन्यास के बाद भी नहीं छूटा क्रिकेट : रिटायरमेंट के बाद भी लक्ष्मी का क्रिकेट से जुड़ाव बना रहा। वह दक्षिण मध्य रेलवे टीम की कोच नियुक्त की गईं और 2014 तक टीम को तराशा। 2008-09 के घरेलू सीजन में महिला क्रिकेट में लक्ष्मी पहली बार मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की गईं। बीसीसीआइ द्वारा घरेलू क्रिकेट में महिला रेफरियों को जिम्मेदारी देने की शुरुआत की गई, तब पहली बार चुनी गईं पांच महिला रेफरियों में लक्ष्मी भी शामिल थीं। इस दल में वह ही इकलौती ऐसी रेफरी थीं, जिन्होंने एक भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला था। इसके बावजूद क्रिकेट ही आज दुनियाभर में उनकी पहचान की वजह बना।

वर्दी के लिए प्यार ने बना दिया सैन्य अफसर

नई पारी

विजय जोशी, देहरादून

शनिवार को देहरादून में आइएमए की पासिंग आउट परेड में देश को 306 नए सैन्य अधिकारी मिले, जिसमें महाराष्ट्र के **विनय विलास गरड़** को प्रशिक्षण का सर्वोच्च सम्मान स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। जानते हैं, देश सेवा को कॅरियर के रूप में चुनने वाले इस युवा के बारे में...

आइएमए प्रशिक्षण में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विजेता विनय विलास गरड़ (मध्य में) पिता विलास गरड़ और माता वंदना गरड़ के साथ। जागरण

यह देशभक्ति का जज्बा और वर्दी का प्यार ही थी, जो विनय विलास गरड़ ने अपने शिक्षक माता-पिता को स्पष्ट कह दिया कि वह डॉक्टर नहीं, सैन्य अफसर ही बनेंगे। मेहनत और लगन के दम पर आइएमए (भारतीय सैन्य अकादमी) से पास आउट होकर विनय सेना की मुख्य धारा में शामिल हो गए। विनय ने यह भी मिसाल पेश की कि उन्हें आरामदायक एवं उच्च भुगतान वाला कॅरियर नहीं, बल्कि सेना का हिस्सा बनकर देश की सेवा करना पसंद है।

शनिवार को देहरादून में आइएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई, जिसमें देश को 306 नए सैन्य अधिकारी मिले। इसके अलावा 71 विदेशी कैडेट्स भी अकादमी से पास आउट हुए। प्रशिक्षण का सर्वोच्च सम्मान स्वॉर्ड ऑफ ऑनर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद निवासी विनय विलास गरड़ को मिला। प्रशिक्षण के दौरान अपनी मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर विनय ने यह उपलब्धि हासिल की। यह सम्मान उन्हें बतौर निरीक्षण ऑफीसर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदान किया। विनय के माता-पिता बेटे की इस कामयाबी से फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, जब माता-पिता की चाह थी कि विनय डॉक्टर बनें। पढ़ाई में तेज होने के कारण बचपन से ही उनके शिक्षक पिता विलास गरड़ और माता वंदना गरड़ का सपना था कि बेटे को मेडिकल क्षेत्र में ही भेजा जाए, लेकिन विनय को तो सैन्य अधिकारी ही बनना था। इसलिए आठवीं कक्षा के बाद उन्होंने माता-पिता को बता दिया कि उन्हें तो सिर्फ सेना की वर्दी ही पहननी है। डॉक्टर बनने में उनकी कोई रुचि नहीं। माता-पिता ने पहले तो बेटे को अन्य विकल्पों पर विचार करने की सलाह दी। मां ने सुझाया कि वह चाहे तो आइएएस या पीसीएस जैसा कॅरियर चुन सकता है, लेकिन जब विनय ने सेना को ही अपनी पहली और आखिरी पसंद बताया तो माता-पिता को अहसास हो गया कि बेटा सैन्य अधिकारी ही बनेगा। इसके बाद उन्होंने विनय को महाराष्ट्र के ही सतारा स्थित सैनिक स्कूल में दाखिला दिलाया। स्कूली शिक्षा के दौरान भी विनय के दिमाग में सैन्य वर्दी की तस्वीर ही झलकती रहती। फिर क्या था, विनय ने सैन्य अधिकारी बनने के लिए तैयारी शुरू की और प्रथम प्रयास में ही एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर आइएमए की राह प्रशस्त की। यहां कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त कर विनय अब सेना की मुख्य धारा में बतौर सैन्य अधिकारी शामिल हो गए हैं। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण काल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर खुद को साबित भी किया।

अब उनके माता-पिता का कहना है कि विनय जो ठान लेता है, उसे करके दिखाता है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह सैन्य अफसर बनेगा, लेकिन स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल कर विनय ने उन्हें और भी गौरवान्वित कर दिया। विनय के छोटे भाई विरेंद्र गरड़ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और विनय को ही अपना आदर्श मानते हैं।

दुनियाभर के पर्यटकों की पहली पसंद है हांगकांग

हांगकांग भले ही इन दिनों सियासी उठापटक के दौर से गुजर रहा हो, लेकिन दुनियाभर के घुमक्कड़ों के लिए यह पहली पसंद है। यह बात लंदन स्थित मार्केट रिसर्च फर्म यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल लिमिटेड की टॉप 100 सिटी डेस्टिनेशंस 2019 की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में उन गंतव्यों के बारे में बताया गया है, जो दुनियाभर के पर्यटकों को कई कारणों से लुभाता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास स्थानों के बारे में...

यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल लिमिटेड की टॉप 100 सिटी डेस्टिनेशंस 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग के बाद, बैंकॉक और लंदन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वहीं, भारत की राजधानी दिल्ली को इस सूची में 11वां स्थान दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह साल खत्म होने तक एशियाई महानगरों में करीब 2.6 करोड़ अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आने का अनुमान है।

हांगकांग के पश्चिमी हिस्से में स्थित विक्टोरिया पीक से भव्य नजारा। फाइल

एशियाई शहरों का दबदबा

रिपोर्ट के मुताबिक, इस सूची में एशियाई शहरों का दबदबा रहा। उसके बाद यूरोप, फिर अमेरिका और मध्य पूर्व और अफ्रीका के शहर रहे। रिपोर्ट में बताया गया है कि यहां चीनी पर्यटकों की संख्या में खासी वृद्धि देखने को मिली है।

मामूली फेरबदल

पिछले साल की सूची और नवीनतम सूची में कोई ज्यादा फेरबदल नहीं दिखा। हां, इस्तांबुल शहर जरूर इस वर्ष की सूची में शीर्ष 10 में स्थान बनाने में कामयाब रहा है। 2018 की सूची में यह शहर 12वें स्थान पर था।

यूरोपीय शहरों की रैंकिंग में उतार-चढ़ाव

रिपोर्ट के मुताबिक, मिलान (35) और वियना (37) जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय शहरों की रैंकिंग नीचे गिर गई है। वहीं क्रोएशिया, स्लोवेनिया और स्वीडन की रैंकिंग में सुधार हुआ है। ऊंची छलांग मारते हुए मिस्र का शहर मुरादाडा 45 पायदान चढ़कर 82 वें स्थान पर पहुंच गया।

भारत की स्थिति

दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले शीर्ष 20 शहरों की सूची में भारत के दो शहरों दिल्ली और मुंबई ने स्थान बनाया है। यही नहीं वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतिस्पर्धा इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। भारत ने दो सालों में छह स्थान की छलांग लगाई है। 2017 में भारत की 40वीं रैंक थी, वहीं 2019 में भारत 34वें स्थान पर पहुंच गया।

प्रदर्शनों से पर्यटकों की संख्या में आई गिरावट

हांगकांग में चीन और सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों की वजह से पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है। 2018 में आए करीब तीन करोड़ पर्यटकों की तुलना में 2019 में पर्यटकों में 8.7 फीसद की गिरावट आंकी जा रही है। इसके बावजूद पर्यटन की दृष्टिकोण से यह शहर अपना दबदबा बरकरार रखे हुए है।

अमेरिकी शहरों की रैंकिंग गिरी

रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यूयॉर्क (8) को छोड़कर अमेरिका के मियामी (27), लॉस एंजिलिस (29), लॉस वेगास (34) होनोलुलु (81) जैसे शहरों की रैंकिंग गिर गई। वहीं, पिछले साल की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दुबई सूची में सातवें स्थान पर रहा।

शीर्ष 15 शहरों में आने वाले पर्यटक

शहर	2018	2019
हांगकांग	2.92	2.67
बैंकॉक	2.41	2.58
लंदन	1.92	1.95
मकाऊ	1.89	2.06
सिंगापुर	1.85	1.97
पेरिस	1.75	1.90
दुबई	1.59	1.63
न्यूयॉर्क	1.36	1.40
कुआलालंपुर	1.34	1.40
इस्तांबुल	1.34	1.47
दिल्ली	1.26	1.51
एंटाल्या	1.24	1.33
शेनजेन	1.22	1.23
मुंबई	1.05	1.24
फूकेट	1.05	1.09

पर्यटकों की संख्या करोड़ में, 2019 के आंकड़े अनुमानित

16 दिसंबर से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)। नई व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति एमएनपी कराता है तो इसकी प्रक्रिया दो से तीन कामकाजी दिवस में पूरी हो जाएगी। फिलहाल यह प्रक्रिया पूरी होने में सात दिन का समय लगता है।

बिना चीर-फाड़ होगा पोस्टमार्टम

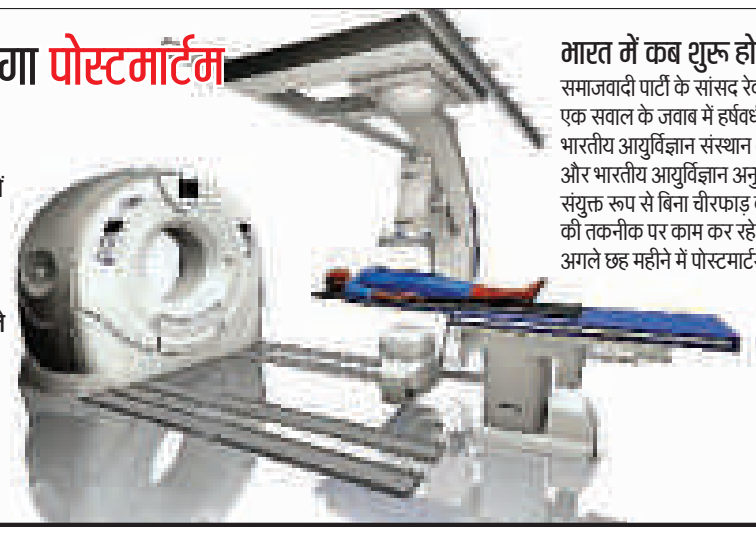

भारत में जल्द ही बिना चीर-फाड़ के पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया में इस तरह से शव परीक्षण करने वाला भारत पहला देश होगा। नई तकनीक के चलते इसमें समय कम लगेगा और बेहतर जांच हो सकेगी। वहीं इस तकनीक के जरिए मृतक के परिजनों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जा सकेगा। आइए इस तकनीक पर डालते हैं एक नजर:

भारत में कब शुरू होगी

समाजवादी पार्टी के सांसद रेवती रमन सिंह के एक सवाल के जवाब में हर्षवर्धन ने कहा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद संयुक्त रूप से बिना चीरफाड़ के पोस्टमार्टम करने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। इसके जरिए अगले छह महीने में पोस्टमार्टम किए जा सकेंगे।

विदेश में है कारगर

दुनिया के कई देश पहले ही ऐसी तकनीक को अपना चुके हैं। यह आभासी शव परीक्षण सबसे पहले स्वीडन में शुरू हुआ। हालांकि अब इसे जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई अन्य देशों ने भी अपनाया है।

आभासी शव परीक्षण

इस तकनीक में डॉक्टर्स रेडिएशन का प्रयोग करेंगे, जिसके जरिए मौत के सही कारण तक पहुंचा जा सकेगा। इसमें सिटी स्कैन या एमआरआइ मशीन का प्रयोग भी संभव है। इसी तरीके से डॉक्टर एक जीवित मनुष्य के शरीर की भी जांच कर सकेंगे। 2013 में 'विरटोप्सी : फॉरेंसिक जांच की नई अवस्था' नाम से सामने आए पेपर में यह अवधारणा सामने आई। विरटोप्सी दो शब्दों के मिश्रण वर्चुअल और ऑटोप्सी से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है आभासी शव परीक्षण। इसके मुताबिक शव परीक्षण एक विशेष शल्य चिकित्सा प्रणाली है। इसके जरिए डॉक्टर मौत का कारण, मृतक के शरीर में बीमारी या फिर चोट का पता लगाता है। यह मृतक के शरीर की जांच के लिए एक विस्तृत और व्यवस्थित जांच की सुविधा प्रदान करता है।

तकनीक एक फायदे अनेक

पोस्टमार्टम का परंपरागत तरीका मृतक के परिजनों को असहज करता है। यह सबसे बड़ा कारण है, जिसके चलते वैश्विक स्तर पर इस तकनीक को अपनाया जा रहा है। साथ ही जहां परंपरागत पोस्टमार्टम में करीब ढाई घंटे का वक्त लगता है, वहीं इस तकनीक के जरिए महज आधे घंटे में पोस्टमार्टम हो जाएगा और इसकी लागत भी कम आएगी।

कितनी सटीक है तकनीक

2012 के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक इस तकनीक में रेडियोलॉजिस्ट मृतक की मौत का कारण बताते हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर इसे स्वीकार करते हैं और ऐसे 90 फीसद मामलों में चीरफाड़ नहीं की जाती है। हालांकि 2018 में जर्नल ऑफ पैथोलॉजी इंफोर्मेटिक्स में रूस और इटली के वैज्ञानिकों ने परंपरागत और आभासी पोस्टमार्टम की तकनीक की तुलना की है। इसमें उन्होंने पाया कि परंपरागत पोस्टमार्टम के 23 में से 15 (करीब 65 फीसद) मामलों की आभासी पोस्टमार्टम के जरिए सही जांच की गई। मौत का एक मामला अनिश्चित रहा और आभासी पोस्टमार्टम में भी यही नतीजा आया। नतीजों के आंकड़ों के मुताबिक आभासी पोस्टमार्टम के नतीजे परंपरागत पोस्टमार्टम से 64 फीसद मिलते हैं।

कह रहे खुलकर कि नहीं करना विवाह, क्योंकि...

बीते दिनों भारत के दौरे पर आए स्वीडन के शाही दंपती से भेंट के लिए पहुंचीं डॉ प्रगति (बाएं)। इस दौरान राजा कार्ल गुस्ताफ (दाएं से दूसरे) और प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करती हुई। सभी फोटो सौजन्य : डॉ. प्रगति

मनु त्यागी, नई दिल्ली

रविवार विशेष

नई बहस छेड़ चुका दिल्ली की डॉ. प्रगति सिंह का फेसबुक पेज 'इंडियन एसेस'

दिल्ली की डॉ. प्रगति सिंह इन दिनों दुनियाभर में चर्चा में हैं। उनका फेसबुक पेज 'इंडियन एसेस' जेंडर (लिंग) और सेक्सुएलिटी (लैंगिकता) के कुछ बेहद जटिल मसलों पर नई बहस छेड़ चुका है। यह बहस, यह पहल इतनी गंभीर है कि दुनिया का ध्यान इसने इस विषय पर खींचा है। यही वजह है कि प्रगति को बीबीसी ने अपनी टॉप-100 वुमन लिस्ट में स्थान दिया है।

चिकित्सक डॉ. प्रगति समझाती हैं कि आज भारत सहित दुनिया भर में अनेक लोग ऐसे हैं, जो यौनेच्छा रहित हैं, भले ही वह किसी भी जेंडर के हों। यह जरूरी नहीं कि इनमें ऐसा किसी बीमारी के कारण है या लाइफस्टाइल में गड़बड़ी के कारण, इसकी अनेक वजह हो सकती हैं। भले ही कोई पूरी तरह स्वस्थ है, कोई शारीरिक अक्षमता भी नहीं है, लेकिन वह जन्म से या भावनात्मक रूप से या किसी और वजह से इस तरह के स्वभाव में घिरा हुआ हो सकता है कि यौनेच्छा या सेक्स उसके लिए गैरजरूरी हो जाते हैं। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि वह हमेशा ही ऐसा रहेगा या रहेगी। यह कुछ समय के लिए भी हो सकता है और यदि समस्या को समय रहते न समझा गया तो लंबे समय तक। तब इसके अन्य दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। लिहाजा, हम ऐसे लोगों को खुलकर सामने आने, जागरूक करने और उन्हें इस स्थिति में मदद पहुंचाने का मंच मुहैया करा रहे हैं। इसे भारत में बड़ा रेस्पांस मिला है। हजारों लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपनी बात साझा कर, समाधान की ओर बढ़ राहत का अनुभव कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि परिवार और समाज का भी इस विषय में जागरूक होना जरूरी है।

प्रगति ने बताया, हर दिन अनेक संदेश आते हैं, लोग अपनी परेशानी साझा करते हैं। कोई कहता या कोई कहती है- बहुत बार कोशिश की मां-पापा से यह कहने की कि शादी नहीं करना..., लेकिन वे इसे नहीं समझते...। बहुत सारे ऐसे शादीशुदा युवक-युवतियों ने संदेश भेजे कि हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन जीवन में कभी भी सेक्स के प्रति रुचि नहीं रही, लेकिन हां, हम साथी के साथ सामान्य जीवन जरूर जीना चाहते हैं। कुछ लड़कियों का कहना है कि महज सेक्स के प्रति डर के कारण वह खुद को तनाव में पाती हैं और अरुचि उत्पन्न हो जाती है।

दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस डॉ. प्रगति ने बताया कि ऐसे अनेक केस हैं, जो लोग पहले अरुचि के शिकार थे, उनमें धीरे-धीरे अब सेक्स के प्रति सामान्य रुचि उत्पन्न हो गई। लिहाजा, इस मसले पर बात करने की और इसे समझने की जरूरत है। बताती हैं, सबसे पहले मैंने इस विषय पर एक ऑनलाइन सर्वे कराया, जिसमें पता चला कि अमूमन लोग इस बारे में किसी से बात नहीं करते हैं और बहुत उलझन में हैं या जबरन शादी के बंधन को निभा रहे हैं। इसके बात मैंने मीट-अप नामक प्लेटफार्म शुरू किया, इसका निमंत्रण ऑनलाइन या वाट्स-एप के जरिए साझा किया गया और अलग-अलग शहरों में हुए आयोजन में ऐसे लोगों को बुलाया गया। अब तक मुंबई, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, भोपाल, हैदराबाद, लखनऊ सहित विदेश में भी मीट-अप का आयोजन किया है।

> मैं पहले नियमित प्रैक्टिस करती थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी कई प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन अब दो साल से पूरी तरह इस प्लेटफार्म पर ही काम कर रही हूं। जल्द ही उम्मीद है इसको लेकर एक मैच मेकिंग एप्लीकेशन भी तैयार कर दूं।
> -फिजिशियन डॉ. प्रगति सिंह

स्वीडन की महारानी ने सराहा

भारत दौरे पर आईं स्वीडन की महारानी सिल्विया ने भी तीन दिसंबर को लैंगिक समानता और स्थिरता के विषय पर आयोजित बैठक में डॉ. प्रगति के इंडिया एसेस प्लेटफार्म की सराहना की। महारानी सिल्विया ने इस अवसर पर यह भी कहा कि मैं समझ सकती हूं लोगों को इस बारे में जागरूक करना और खुलकर बोलने के लिए सामने लाना आसान नहीं है, ऐसे वर्कशॉप की बहुत जरूरत है। डॉ. प्रगति को इसके लिए उत्साह बनाए रखना चाहिए।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

सच पर पर्दा ▶ कई महीने से चल रहा अफसरों और टेनरियों की मिलीभगत का खेल, टेनरियों से रोज निकल रहा फिनिश लेदर

टेनरियों पर ताला, फिर भी गंगा में गिर रही गंदगी

कागज पर 'बंद' टेनरियां से निकल रहा सात-आठ एमएलडी डिस्चार्ज, खुले पर निकलता था नौ एमएलडी

श्रीनारायण मिश्र, कानपुर

पोल खोल पार्ट-चार

नमामि गंगे समीक्षा की... जागरण पड़ताल

नई चुंगी से लेकर वाजिदपुर तक टेनरी कर्मचारियों की चहल-पहल जारी है। कर्मचारी नियमित ड्यूटी पर आ रहे हैं। वाहन में लदकर फिनिश लेदर टेनरियों से बाहर जा रहा है। चमड़ों की कतरन के ढेर बाहर लग रहे हैं..., सारा काम रोज की तरह हो रहा है। इन टेनरियों से रोज 70 से 80 लाख लीटर प्रदूषित तरल अपशिष्ट जलनिगम के ट्रीटमेंट प्लांट तक भी पहुंच रहा है। ये हालात तब हैं, जब दिसंबर 2018 से अभी तक केवल एक माह छोड़कर शेष दिन टेनरियां बंद रहीं।

यह बात दीगर है कि एक भी टेनरी नहीं चल रही है, लेकिन जल निगम के रजिस्टर में रोज 7-8 एमएलडी (मिलियन ऑफ लीटर्स पर डे) टेनरी वेस्ट दर्ज हो रहा है। प्रधानमंत्री नमामि गंगे के कामों की समीक्षा करने 14 को कानपुर आ रहे हैं। उनके साथ इस परियोजना में संलग्न दस केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री और संबंधित पांच राज्यों के मुख्यमंत्री भी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। फिर भी उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का तुर्रा यह है कि कानपुर में टेनरियां बंद हैं।

अर्द्धकुंभ 2019 के लिए दिसंबर 2018 में कानपुर की सभी 323 टेनरियां बंद कर दी गई थीं। बीच में एक महीने के लिए मानक पूरा करने वाली 122 टेनरियों को एक माह के लिए खोला गया, लेकिन फिर बंद कर दिया गया। अब एक नवंबर 2019 से सभी टेनरियां बंद हैं। टेनरियां बंद रहें, इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है। जागरण की पड़ताल में सामने आया कि अफसरों की मिलीभगत से टेनरियां चल रही हैं, जबकि उप्र प्रदूषण नियंत्र बोर्ड (यूपीपीसीबी) के आंकड़ों में निरीक्षण और टेनरी बंदी दर्ज हो रही है।

प्लांट की शोधन क्षमता नौ एमएलडी होने के बाद भी 12 से 14 एमएलडी टेनरी वेस्ट के डिस्चार्ज का पर्दाफाश किया गया तो मंडलायुक्त ने पेच कसे। तब पीसीबी ने कुछ टेनरियां बंद कराईं। बंदी के दौरान डिस्चार्ज घटकर औसतन आठ एमएलडी प्रतिदिन हो गया है। इस के बाद भी टेनरी बंदी का राग अलापा जाता रहा। शनिवार को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर में थे, इन टेनरियों ने सात लाख एमएलडी से अधिक प्रदूषित पानी उगला।

यह है हाल...

शनिवार को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर में थे, इन टेनरियों ने सात लाख एमएलडी से अधिक प्रदूषित पानी उगला।

वजीदपुर में बने 36 एमएलडी के कामन इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट में पड़ा टेनरी वेस्ट। इस प्लांट में ड्रेनेज और टेनरी वेस्ट दोनों शोधित होते हैं। धीरज गुप्ता

दिसंबर के पहले सप्ताह टेनरी वेस्ट

तिथि	मात्रा
01	9.42
02	7.59
03	7.02
04	7.02
05	7.59
06	7.52
07	7.05

(मात्रा मिलियन लीटर प्रति दिन के हिसाब से। स्रोत कॉमन इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वाजिदपुर)

जागरण की पड़ताल पर योगी ने अफसरों को फटकारा

जागरण संवाददाता, कानपुर : गंगा में सीवर और नालों का प्रदूषित जल जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को फटकार लगाई है। उन्होंने नाले बंद करने के लिए कहा। शनिवार को कानपुर पहुंचे योगी ने गंगा बैराज के अटल घाट से सीसामऊ तक स्टीमर (स्वचालित नौका) से निरीक्षण के बाद चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) सभागार में अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ योगी ने बैठक की। उन्होंने पूछा, दैनिक जागरण में गंगा में नाले गिरने की खबरें प्रकाशित हो रही हैं। क्या हो रहा है? अफसरों ने कहा कि छावनी परिषद की एनओसी न मिलने से दो नाले बंद नहीं हुए हैं, वह ही गिर रहे हैं। ये नाले नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किए गए थे। अफसर यहां आधा सच छिपा गए। डबका नाला, भगवतदास घाट नाला, परमिया नाला समेत गंगा में गिरने वाले एक दर्जन अन्य नालों के बारे में नहीं बताया। यह जरूर कहा, एक नाले की खबर प्रकाशित की है, उसे आज दिखवा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों से दो टूक कहा है कि गंगा में गिरने वाले सारे नाले बंद कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 दिसंबर को समीक्षा बैठक भी गंगा की गोद में ही करेंगे।

धुप्पा से दूर नहीं रह सकता यह सारस

जीना इसी का नाम है

जीतेन्द्र पांडेय, गोरखपुर

हर किसी को अपनी चिंता है, पर नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का एक किसान ऐसा भी है, जो बेहाल जीव-जंतुओं को घायल नहीं देख सकता। नाम है धुप्पा। घायल पशु-पक्षियों को घर लाना और उपचार करने के बाद उन्हें किसी सुरक्षित स्थल पर छोड़ देना उनका जुनून है। जुनून कुछ वर्षों से नहीं बल्कि पूरे 30 वर्षों से बना हुआ है। उनकी जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, इस पुनीत कार्य के प्रति लगाव भी बढ़ता गया।

45 वर्षीय धुप्पा जोगिया विकास खंड के ग्राम गोनहा ताल के रहने वाले हैं। वह सेही (पूरे शरीर पर कांटे वाला जानवर), मोर, सारस समेत 50 से अधिक घायल पशु-पक्षियों का जीवन बचा चुके हैं। इनमें से कई तो अब उनके साथ घर पर रहते हैं। परिवार के सदस्य बन गए हैं। सहसा विश्वास नहीं होता, लेकिन सच यही है कि छह वर्ष से एक सारस उनका घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं। कई बार उन्होंने उसे खुले में छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह उन्हें छोड़कर एक कदम आगे गया ही नहीं। जबकि माना जाता है कि सारस साथी के बिना रह नहीं सकता।

जीवों के प्रति अगाध प्रेम ने उन्हें इर्द-गिर्द के गांव में इस कदर लोकप्रिय बना दिया है कि कोई जीव घायल होता है तो लोग इसकी सूचना पशु चिकित्सा विभाग को देने की बजाय धुप्पा को देते हैं। सभी को भरोसा रहता है कि धुप्पा के प्रयास से घायल को जिंदगी मिल जाएगी। धुप्पा बताते हैं कि जीव-जंतुओं के प्रति लगाव उनका बचपन से ही है। कहते हैं, छोटा था तो कई बार घर पर घायल गौरैया के बच्चों को ले आया। देखभाल की और ठीक होते ही उड़ने के लिए छोड़ दिया। ऐसे ही यह सिलसिला चलता रहा। गांव वाले भी उनके इस नेक कार्य की तारीफ करते हैं। बताते हैं कि तीन वर्ष पूर्व ट्रैक्टर की चपेट में एक सांप आ गया। धुप्पा ने उसका भी उपचार किया और फिर उसे गांव के बाहर ले जाकर छोड़ दिया। एक वर्ष पूर्व उसे मोर के दो छोटे बच्चे मिले, दोनों ही चोटिल थे। उनका उपचार किया और उन्हें वहीं खेत में छोड़ा। थोड़ी देर बाद लौटा तो दोनों उसी स्थान पर मिले। उन्हें कोई जानवर अपना शिकार न बना ले। इसलिए उन्हें घर ले आया। अब दोनों मोर घर पर रहते हैं।

खेती करने वाले धुप्पा के स्वजन भी पूरा सहयोग करते हैं। पशु-पक्षियों के लिए मिट्टी का घर बनाया है। इसमें मुर्गी से लेकर सेही व मोर के बच्चे साथ रहते हैं। सभी को वहीं पर खाना मिल जाता है और वही वह उसे चुगते हैं।

अपने घर पर सारस के साथ धुप्पा। जागरण

50 से अधिक जीवों का जीवन बचा चुके हैं किसान धुप्पा

30 वर्षों से घायल पशु-पक्षियों को घर लाना और उपचार करना है इनका जुनून

- इलाज के बाद सारस, मोर और सेही बन गए परिवार के सदस्य
- उम्र के साथ बढ़ती गई जीवों के प्रति दया भावना, गांव में इस कदर लोकप्रिय कि घायल जीवों को यहीं लाते हैं लोग

बढ़ता जा रहा परिवार...

धुप्पा की सेवा-समर्पण और लगाव का नतीजा है कि सारस के अलाव सेही और कई मोर उनके घर के सदस्य के मानिंद रहते हैं। इन सभी पक्षियों को वह कभी घायलावस्था में घर लाए थे। अब राज्य पक्षी सारस व राष्ट्रीय पक्षी मोर की जुगलबंदी देखते ही बनती है। धुप्पा की एक आवाज पर ये परिंदे उसके पास खिंचे चले आते हैं।

जिनके अपनों को टाइगर ने निवाला बना लिया...

आदिवासी ग्रामीण बच्चों को कंप्यूटर सिखाते शिक्षक। जागरण

प्रकाश पांडेय, कोलकाता

अपना देस खुशबू माटी की

जय गोपालपुर में गरीबी को मात देने को ग्रामीण कर रहे हैं दिन-रात मेहनत

बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बासंती स्थित सुदूर जय गोपालपुर गांव में गरीबी को मात देने को हर शख्स दिन-रात काम करता है। इसमें वे महिलाएं भी शामिल हैं, जिनके सुहाग को बंगाल टाइगर ने अपना नेवाला बना लिया। लेकिन इस गांव के गम को कम करने और ग्रामीणों को मुख्यधारा में लाने को जेजीवीके यानी जय गोपालपुर ग्राम विकास केंद्र नामक एक गैर सरकारी संस्था नित्य प्रयासरत है।

गांव के बच्चों की पढ़ाई को संस्था की ओर से विवेकानंद शिक्षा निकेतन नाम से विद्यालय की स्थापना की गई, जहां उच्च माध्यमिक तक पढ़ाई की व्यवस्था है। फिलहाल यहां डेनमार्क से आए युवा शोधकर्ता भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

सामुदायिक अनुसंधान विषय पर शोध को भारत आई डेनमार्क निवासी नान्ना इमेली वेस्टरगाड बताती हैं कि विवेकानंद शिक्षा निकेतन में अधिकतर वे ही बच्चे पढ़ने आते हैं, जिनके अभिभावकों की मौत बाघों के हमले में हो गई। नान्ना ने बताया कि वे यहां पिछले कई महीनों से नियमित कक्षाएं ले रही हैं और उन्हें इन बच्चों के बीच सुखद अनुभव होता है। यहां वे अंग्रेजी और साइंस की कक्षाएं लेती हैं। इसके अलावे बच्चों को कंप्यूटर, प्रकृति महत्व और योग प्रशिक्षण से जोड़ उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है।

एक अन्य शोधार्थी जेपे मोइलर ने बताया कि इस गांव के दर्जनों परिवार अब मुख्यधारा से जुड़ने को प्रयत्नशील हैं। स्कूल के सभी विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी सजग हैं। बीते कई सालों से इस स्कूल के बच्चे शैक्षणिक दौरे पर डेनमार्क भी जाते रहे हैं और वहां के बच्चों संग मिलकर कई प्रोजेक्ट पर संयुक्त रूप से काम कर चुके हैं। ऐसे में हमारी कोशिश है कि यहां के बच्चों को आत्म निर्भर बना उन्हें मुख्यधारा में लाया जाए। संस्था के सचिव विश्वजीत महाकुर के प्रयासों की हम सभी सराहना करते हैं। इनके प्रयास से आज जय गोपालपुर गांव के दयनीय ग्रामीणों को काफी हद तक आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है।

ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार वस्त्रों को दिखाती संस्था की प्रतिनिधि। जागरण

मिला उत्कृष्ट सम्मान...

जेजीवीके के सचिव विश्वजीत महाकुर ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता की दिशा में हमारे उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए जय गोपालपुर ग्राम विकास केंद्र को भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय की ओर से इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं सुंदरबन में जैव विविधता संरक्षण के लिए बंगाल जैव विविधता बोर्ड की ओर से सेवर ऑफ बॉयोडाइवसिटी सम्मान भी प्रदान किया गया।

दरअसल, बेरोजगारी के कारण इन परिवारों के सदस्य जंगलों पर निर्भर रहे हैं, जहां इन्हें बाघ का सामना भी करना पड़ता। अब महिलाओं के उत्थान को स्वरोजगार के अवसर दिए गए हैं। उन्हें सिलाई, बुनाई, चित्रकारी, मत्स्य पालन समेत अन्य स्वउद्यमों की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग उपरांत उनके द्वारा तैयार माल को देश-दुनिया में आयोजित होने वाले मेलों व महोत्सवों में बेचने को ले जाया जाता है। नतीजतन, आज इस गांव की तस्वीर बदली है और ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान उनके गम पर मरहम की तरह काम कर रही है।

जगी उम्मीद

इसी माह पूर्ण हो रही है औली के अंतरराष्ट्रीय स्लोप को वर्ष 2010 में मिली मान्यता की अवधि, वर्ष 2012 व 2018 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन न होने से बरकरार नहीं रह पाई स्लोप की मान्यता

जल्द मिल सकती है औली को 'फिस' से मान्यता

रणजीत सिंह रावत, जोशीमठ (चमोली)

विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली के अंतरराष्ट्रीय नंदा देवी स्लोप को जल्द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कीइंग (फिस) से मान्यता मिलने की उम्मीद है। संयुक्त निदेशक उत्तराखंड पर्यटन परिषद विवेक चौहान ने बताया कि फिस की टीम औली में इस स्कीइंग स्लोप का निरीक्षण कर चुकी है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट फेडरेशन को सौंप देगी।

दरअसल, स्लोप को वर्ष 2010 में मिली मान्यता की अवधि इसी माह पूर्ण हो रही है और दो बार यहां राष्ट्रीय खेल भी नहीं हो पाए। ऐसे में अगले दस साल के लिए औली के अंतरराष्ट्रीय स्लोप को फिर नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। इसी के बाद स्लोप को मान्यता प्रदान की जाएगी।

फिस की मान्यता के बाद स्लोप पर प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना जरूरी है, लेकिन वर्ष 2012 और 2018 में बर्फबारी न होने के कारण औली को इन खेलों से महरूम रहना पड़ा। आयोजन की तिथि आगे खिसकाने के बाद भी यहां राष्ट्रीय खेल नहीं हो पाए। अगर यह आयोजन हो जाते तो स्लोप को स्वाभाविक रूप से अगले दस सालों के लिए मान्यता मिल जाती। हालांकि, इस अवधि में एक बार शीतकालीन दक्षिण एशियाई खेल (सैफ गेम्स) और पांच बार शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो चुका है, लेकिन मान्यता बरकरार रखने के लिए इसमें निरंतरता होना जरूरी है।

विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ चमोली के सचिव अजय भट्ट कहते हैं कि इस बार नवंबर से ही यहां अच्छी बर्फबारी हो रही है, सो उम्मीद की जानी चाहिए कि फिस रेस के साथ राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में भी कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी।

उत्तराखंड के चमोली स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली के स्कीइंग स्लोप। फाइल फोटो

स्की रेस के लिए हर दृष्टि से संपन्न है औली

चमोली जिले में समुद्रतल से 10500 फीट की ऊंचाई पर औली का 1300 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा दक्षिणमुखी स्लोप देश ही नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्लोपों शामिल है। बर्फ न पड़ने की स्थित में यहां आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन भी लगाई गई है। इसके लिए यहां 25 हजार किलो लीटर क्षमता की एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है। खिलाड़ियों को स्लोप के फिनिशिंग प्वाइंट से स्टार्ट प्वाइंट तक ले जाने के लिए 800 मीटर लंबी चेयर लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है।

नेपाल एसबीआइ का लाभ बढ़ा

काठमांडू : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की नेपाल में सहायक शाखा नेपाल एसबीआइ बैंक को वित्त वर्ष 2018-19 में 229 .25 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 13 .29 प्रतिशत ज्यादा है। बैंक की सालाना आमसभा से पहले जारी बयान में कहा गया कि समीक्षाधीन अवधि में बैंक ने जमा मद में 9,792 .45 करोड़ रुपये हासिल किए और 8,864 .47 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे। (प्रेट्र)

भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर के आकार तक पहुंचाने में स्टार्ट-अप, सेवा और कृषि क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है।

— सुरेश प्रभु, पूर्व वाणिज्य मंत्री

संकट ▶ जीएसटी संग्रह की वर्तमान स्थिति देख राज्यों से सहमति मिलने की उम्मीद नहीं

महंगे पेट्रोल-डीजल से आम आदमी को राहत मिलने की राह मुश्किल

पिछली दो बैठकों में राज्यों ने प्रस्ताव ठुकराया, लंबे वक्त तक रहेगा ग्राहकों पर बोझ

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

पिछले सवा दो वर्षों से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने और इनके दाम घटने की उम्मीद कर रहे आम आदमी को अभी कोई राहत मिलने के संकेत नहीं हैं। जीएसटी काउंसिल में राज्यों के प्रतिनिधि इन उत्पादों को नई टैक्स व्यवस्था में लाने ही नहीं देना चाह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पेट्रोल और डीजल से राज्यों को बड़ा राजस्व मिलता है, क्योंकि दोनों उत्पादों पर राज्यों द्वारा लगाया जा रहा टैक्स बहुत ज्यादा है। और जीएसटी संग्रह की मौजूदा लचर स्थिति को देखते हुए ज्यादातर राज्य पेट्रोल-डीजल से हासिल राजस्व में कोई कमी नहीं चाहते हैं। वित्त मंत्रालय मोटे तौर पर तो इन दोनों समेत अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है। लेकिन वह अपनी तरफ से राज्यों पर दबाव बनाने की स्थिति में खुद को नहीं पा रहा है।

जीएसटी काउंसिल की पिछली दोनों बैठकों में जब भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई तो राज्यों ने उसे एक सिरे से खारिज किया है। यह भी ध्यान रहे कि पिछले एक वर्ष में भाजपा ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब महाराष्ट्र में सत्ता गंवा दी है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती सात महीनों के दौरान जीएसटी संग्रह अनुमान से कम रहा है। ऐसे में पेट्रो उत्पादों को जीएसटी में शामिल होने से उनकी आमदनी का यह स्रोत भी प्रभावित हो जाएगा। वर्ष 2018-19 में राज्यों को पेट्रो उत्पादों से कुल 2,30,130 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया था जो उससे पिछले वर्ष के मुकाबले 13 फीसद ज्यादा था। इस रेवेन्यू में सबसे बड़ा योगदान पेट्रोल व डीजल से बिक्री कर वसूली का है। अभी पेट्रोल पर राज्यों की तरफ से 17-36 प्रतिशत बिक्री कर या वैट वसूला जाता है, जबकि डीजल पर यह दर 8-18 प्रतिशत तक है।

इसलिए जीएसटी से पेट्रोल-डीजल बाहर

राज्यों के राजस्व में पेट्रो उत्पादों से हासिल कमाई का हिस्सा बहुत ज्यादा है। कुछ राज्यों के कुल राजस्व में पेट्रोलियम उत्पादों से हासिल टैक्स की हिस्सेदारी 60 फीसद तक है। यही वजह है कि राज्य इसकी वसूली केंद्र को देने को तैयार नहीं हुए।

क्या बनी थी सहमति

जीएसटी लागू होने के समय यह सहमति बनी थी कि पांच वर्ष बाद इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अभी राजस्व की जो स्थिति है, उसे देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य पांच वर्ष बाद भी पेट्रो उत्पादों को शायद ही जीएसटी में शामिल करने को तैयार हों।

राज्यों का तर्क क्या है

अभी जबकि राज्यों के गैर-पेट्रोलियम उत्पादों से होने वाले राजस्व में भारी कमी हो रही है, तब उन्हें पेट्रोलियम उत्पादों से हो रहे रेवेन्यू से ही मदद मिल रही है। अप्रैल-जून में राज्यों को पेट्रो उत्पादों से मिले 51,600 करोड़ राजस्व में पेट्रोल, डीजल, एटीएफ व गैस की राशि 46,176 करोड़ रुपये की थी।

पेट्रोलियम मंत्री भी कर रहे मांग

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी लंबे अरसे से पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने की मांग कर चुके हैं। प्रधान पिछले एक वर्ष के दौरान करीब दर्जनभर मौकों पर उम्मीद जता चुके हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं। लेकिन मौजूदा हालात में उनकी मांग पूरी होने की दूर-दूर तक गुंजाइश नहीं दिख रही है।

स्टार्ट-अप्स में पेंशन फंड के निवेश पर विचार के लिए सरकार तैयार

पणजी, आइएएनएस : सरकार स्टार्ट-अप कंपनियों में पेंशन फंड के एक हिस्से के निवेश को इजाजत देने पर विचार कर रही है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के सचिव गुरु प्रसाद महापात्र ने कहा कि इसके लिए सरकार एक अंतर-मंत्रालयी विमर्श की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके तहत इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या स्टार्ट-अप कंपनियों में पेंशन फंड के एक छोटे हिस्से के निवेश की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं।

महापात्र के मुताबिक उद्योग जगत ने सरकार के समक्ष यह तर्क रखा है कि विदेशी पेंशन फंड्स को भारतीय स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश की इजाजत है। फिर ऐसी ही इजाजत घरेलू पेंशन फंड्स को देने में क्या दिक्कत है। सचिव ने इसकी वजह यह बताई कि विदेशी पेंशन फंड्स को अपनी घरेलू स्टार्ट-अप कंपनियों से जितना रिटर्न मिलता है, उसके मुकाबले भारतीय कंपनियां बहुत ज्यादा रिटर्न देती हैं। इसलिए विदेशी पेंशन फंड्स भारतीय कंपनियों में निवेश करते हैं। लेकिन भारतीय बाजार में पेंशन फंड्स संवेदनशील हैं, क्योंकि इनसे कामकाजी लोगों की जिंदगीभर की गाढ़ी कमाई जुड़ी हुई है। ऐसे में कई बार पेंशन फंड को लेकर बेहद संरक्षणवादी रवैया अपनाना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय पेंशन फंड्स मुख्य रूप से सरकारी बांड्स में निवेश करते हैं, जहां रिटर्न निश्चित होता है। हालांकि मंत्री ने उद्योग को आश्वस्त किया है कि पेंशन फंड के छोटे से हिस्से का निवेश स्टार्ट-अप कंपनियों में किए जाने पर विचार की गुंजाइश है।

प्रतीकात्मक

उद्योग का तर्क

- जब विदेशी पेंशन फंड्स को निवेश की इजाजत, तो घरेलू फंड्स को क्यों नहीं
- सरकार का तर्क - भारत में पेंशन फंड संवेदनशील, कामकाजी वर्ग की जिंदगीभर की कमाई इसमें सुरक्षित

गोवा में संपन्न वेंचर कैपिटल मीट के दौरान उद्योग जगत ने मंत्री के समक्ष यह मामला रखा है। सैद्धांतिक रूप से यह विचार बेहद आकर्षक अवसर की तरह है। अगर ऐसा होता है तो स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए फंड की किल्लत का एक हद तक समाधान हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि भारत में पेंशन और इंश्योरेंस उद्योग और फंड्स का आकार बहुत बड़ा है।

इकोनॉमी के विकास में स्टार्ट-अप्स अहम

मुंबई, प्रेट्र : पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर का महत्वाकांक्षी आकार देने में स्टार्ट-अप कंपनियों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि जब हम पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा हिस्सा स्टार्ट-अप कंपनियों की तरफ से ही आने वाला है। इसके साथ ही इस लक्ष्य को हासिल करने में सेवा क्षेत्र और कृषि की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है।

न्यूज गैलरी

इंश्योरेंस कंपनियों में बैंक हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी

मुंबई : बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) बैंकों को एक से अधिक बीमा कंपनी में 10 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी रखने की इजाजत देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि वे एक से अधिक बीमा कंपनी में प्रबंधन पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। इसके साथ बैंकों को इस तरह की एक से अधिक इंश्योरेंस कंपनियों में हिस्सेदारी सिर्फ जीवन बीमा और साधारण बीमा क्षेत्र के लिए मिल सकेगी। जिन 10 बैंकों के विलय की तैयारी शुरू हो चुकी है, उनमें से कई की इंश्योरेंस इकाइयां भी हैं। पीएनबी, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, केनरा बैंक और ओबीसी की इंश्योरेंस इकाइयां हैं। (प्रेट्र)

एनईएफटी सुविधा 16 दिसंबर से चौबीसों घंटे मिलेगी

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के तहत लेनदेन की सुविधा अब चौबीसों घंटे मुहैया कराने का फैसला किया है। यह सुविधा 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। वर्तमान में यह सुविधा सोमवार से शनिवार के दौरान सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक के लिए उपलब्ध है, जबकि हर महीने पहले और तीसरे शनिवार को यह दिन के एक बजे तक मुहैया कराई जाती है। इसका निस्तारण हर घंटे के बैच में होता है। एनईएफटी के तहत दो लाख रुपये तक का लेनदेन किया जा सकता है। (प्रेट्र)

एनबीसीसी और सुरक्षा की बोलियों पर एक साथ वोटिंग

नई दिल्ली : जेपी इन्फ्राटेक के घर खरीदार व कर्जदाता सरकारी कंपनी एनबीसीसी और निजी कंपनी सुरक्षा रियल्टी की बोलियों पर एक साथ वोटिंग करेंगे। सूत्रों ने बताया कि शनिवार को कर्जदाताओं की बैठक में फैसला लिया गया कि वोटिंग प्रक्रिया 10 दिसंबर को शुरू होगी और 16 दिसंबर तक चलेगी। दोनों कंपनियों को बोली जमा कराने के लिए शनिवार रात 11 बजे का समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तीसरी बार बोली की प्रक्रिया की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि कमेटी ऑफ केडिटर्स (सीओसी) की बैठक में आइसीआइसीआइ बैंक और एक्सिस बैंक एक साथ दोनों बोलियों पर वोटिंग के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि पहले बड़ी बोली वाले पक्ष पर वोटिंग होनी चाहिए। हालांकि कर्जदाता यह तय नहीं कर पाए कि दोनों कंपनियों में किसकी बोली ज्यादा और किसकी बोली कम है। (प्रेट्र)

कोल कंपनियों ने बिजली उत्पादकों को दिया 700 करोड़ का झटका

नईदुनिया पड़ताल

रायपुर, नईदुनिया

केंद्र और राज्य के बीच रार से सरकारी बिजली कंपनियों को 700 करोड़ रुपये का झटका लगा है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के थर्मल संयंत्रों को पर्याप्त कोयला नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कंपनी को पिछले चार महीने में लगभग यह नुकसान उठाना पड़ा है। बिजली कंपनी का उत्पादन ठप होने से कंपनी की आय में लगातार गिरावट आई है, जिसका सीधा असर इसे राज्य के राजस्व में नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। इधर पावर कंपनी के अधिकारियों का मानना है कि पिछले 18 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब साल के नवंबर-दिसंबर माह में कोयले की कमी की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ हो।

बिजली की इकाइयों में ऐसे कम की गई आपूर्ति : प्रबंधन ने बताया कि केटीपीएस कोरबा ईस्ट इकाई में 120 मेगावाट की दो यूनिट है संचालित है, इसमें हर दिन 4,000 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत पड़ती है, लेकिन पिछले दिनों से एक से 1,500 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की जा रही थी। वहीं हसदेव विद्युत संयंत्र में प्रतिदिन 22 हजार मीट्रिक टन पर 10 से 12 हजार मीट्रिक टन कोयला दिया जा रहा था। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी संयंत्र (डीएसपीएम) में 8,000 मीट्रिक टन कोयले की जगह भी जरूरत से कम आपूर्ति थी। वहीं, मड़वा में भी 15 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन कोयले की खपत पर पिछले दिनों तक मात्र तीन से चार हजार मीट्रिक टन कोयला एसईसीएल द्वारा दिया जा रहा था।

- बिजली कंपनी को जरूरत का कोयला नहीं मिलने से उत्पादन में 200 करोड़ यूनिट बिजली का घाटा

पांच दिन का बैकअप फ्यूल रखना जरूरी : कंपनी के अनुसार थर्मल संयंत्रों को चलाने के लिए पांच दिनों तक के फ्यूल का बैकअप रखना जरूरी है। नहीं होने की स्थिति में संयंत्र को बंद करना पड़ता है। कोयले की कमी की वजह से जांजगीर-चांपा स्थित मड़वा प्लांट के 500 मेगावॉट प्लांट को पिछले दिनों बंद रखना पड़ा था। यही स्थिति दो दिन पूर्व भी बनी हुई थी। अफसरों के अनुसार स्थिति नहीं सुधरी तो आगे भी बिजली उत्पादन को लेकर संकट पैदा होगी।

एसईसीएल और रेलवे के रवैये से परेशान कंपनी : अधिकारियों ने बताया कि एसईसीएल बिजली कंपनी को कोयला उपलब्ध कराती है। वहीं इसके परिवहन के लिए रेलवे मालवाहक रेल की व्यवस्था करता है, लेकिन पिछले कुछ समय से जहां एसईसीएल ने कोयले के लिए हाथ खींच रखे थे।

रेलवे भी पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थता जाहिर कर रहा था। बिजली कंपनी के अधिकारी दबी जुबान में यहां तक कह रहे हैं कि एसईसीएल और रेलवे लगातार उनकी बातों को अनसुना कर रहे थे। वहीं परेशानी पूछने पर केंद्र से आंतरिक दबाव की बात भी कह रहे हैं। हालांकि मुख्य सचिव की बिजली, रेलवे और एसईसीएल के अधिकारियों की बैठक के बाद कोयला आपूर्ति में थोड़ा सुधार आ रहा है। हालांकि स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है।

86 ट्रकों में आया 3,182 टन अफगानी प्याज

जासं, अमृतसर : अफगानी प्याज महंगाई से लाल हो रही जनता को राहत दिला सकता है। शनिवार को वाघा के रास्ते 86 ट्रकों में 3,182 टन अफगानी प्याज आइसीपी (इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट) अटारी पहुंचा। इससे पहले शुक्रवार को कुलियों की हड़ताल के चलते अफगानी प्याज के 40 ट्रकों को वापस वाघा लौटा दिया गया था। आइसीपी अटारी पर बकाया भुगतान को लेकर कुली दो दिनों से हड़ताल पर थे। शनिवार को हड़ताल खत्म होने के बाद कस्टम विभाग ने अफगानी प्याज के ट्रकों को भारत भेजने की क्लीयरेंस दी। शाम तक अफगानी प्याज के 86 ट्रक भारत पहुंच चुके थे। ड्राई फ्रूट एसोसिएशन के प्रधान अनिल मेहरा ने बताया कि कुलियों की हड़ताल खुलने से कारोबारियों को राहत मिली है। आने वाले दिनों में अफगानी प्याज बड़ी मात्रा में पहुंचने की उम्मीद है। यहां से यह प्याज देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाएगा।

हिंद मजदूर सभा अटारी बॉर्डर के सदस्य सुरिंदर सिंह छिंदा और कुलवंत सिंह बावा ने बताया कि शुक्रवार देर शाम खाते में रकम ट्रांसफर कर देने के बाद कुलियों ने हड़ताल वापस ले ली। शनिवार को वाघा के रास्ते भारत पहुंचे अफगानिस्तानी प्याज के ट्रकों की अनलोडिंग भी कर दी गई है।

वोडा-आइडिया टूटी तो एयरटेल होगी फायदे में

नई दिल्ली, प्रेट्र : शेयर ब्रोकिंग सेवा प्रदाता कंपनियों का मानना है कि अगर वोडाफोन आइडिया का कारोबार बंद होता है, तो एयरटेल को बड़ा फायदा होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के मामले में दोनों कंपनियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, तो ये कंपनियां पिछले 14 वर्षों के लिए सरकार को भुगतान करने को मजबूर हो जाएंगी। शेयर ब्रोकर्स का मानना है कि ऐसी स्थिति के लिए एयरटेल की बैलेंस शीट ज्यादा मजबूत है और वह अपनी देनदारियों का व्यवस्थित तरीके से भुगतान कर सकती है।

वोडाफोन ने पिछले एक महीने में कम से कम दो मौकों पर कहा है कि एजीआर के बोझ से भारत में उसके अस्तित्व पर संकट है। पिछले महीने वोडाफोन के सीईओ निक रीड और शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला के बयानों से स्पष्ट है कि सरकार से मदद नहीं मिलने की सूरत में कंपनी अपना परिचालन बंद करने के बारे में गंभीरता से विचार कर सकती है। दोनों कंपनियां अपने-अपने स्तर पर सरकार से इस समस्या के निदान के लिए गुहार लगा रही हैं।

वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट में उसके फैसले पर अलग-अलग पुनर्विचार याचिकाएं 24 अक्टूबर को दाखिल की थीं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन अपने फैसले में कहा था कि एजीआर की गणना का सरकार का तरीका सही है। आदेश के बाद इन कंपनियों पर एजीआर मद में कुल देनदारी 1.47 लाख करोड़ रुपये बनती है।

अग्रणी ब्रोकिंग संस्था मॉर्गन स्टेनले ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन कंपनियों की याचिकाएं खारिज कर देता है तो यह एयरटेल के लिए बुरा होगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। इसकी वजह यह है कि याचिकाएं खारिज होने की स्थिति में कंपनियों को 24 जनवरी, 2020 से पहले इन देनदारियों का भुगतान करना होगा। इससे टेलीकॉम उद्योग में कंपनियों की मार्केट पोजिशनिंग पर भी गहरा असर पड़ेगा, जिसका आखिरकार फायदा मौजूदा बाजार में एयरटेल को मिल सकता है।

- ब्रोकरेज कंपनियों का मानना है कि बदली परिस्थितियों के लिए एयरटेल बेहतर तरीके से तैयार
- सरकारी मदद नहीं मिलने की सूरत में वोडाफोन आइडिया दे चुकी है कारोबार समेटने का संकेत

प्रतीकात्मक

एयरटेल से आउटगोइंग हुआ मुफ्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारती एयरटेल ने अन्य नेटवर्क पर मुफ्त आउटगोइंग कॉल्स की सीमा शनिवार से समाप्त कर दी है। इससे पहले कंपनी ने 28 दिनों की वैधता वाले प्लान के लिए अन्य नेटवर्क पर 1,000 मिनट, 84 दिनों की वैधता वाले प्लान के लिए 3,000 मिनट और 365 दिनों की वैधता वाले प्लान के लिए 12,000 मिनट मुफ्त आउटगोइंग कॉल्स की सीमा रखी थी। कंपनी ने तीन नए प्लान भी लांच किए हैं, जो 28 दिनों और 56 दिनों के लिए हैं।

भारती एयरटेल के लिए सकारात्मक यह है कि कंपनी के निदेशक बोर्ड ने 300 करोड़ डॉलर (करीब 21,000 करोड़ रुपये) जुटाने को मंजूरी दे दी है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि पांच दिसंबर को भारती एयरटेल के प्रमुख सुनील भारती मित्तल से उसके अधिकारियों की मुलाकात हुई थी। इसमें मित्तल ने टेलीकॉम कारोबार के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय रखी। इसमें उद्योग जगत के आउटलुक, एजीआर देनदारी के संभावित परिणाम और एयरटेल की बैलेंस शीट से जुड़े पहलू शामिल थे। इस बातचीत के बाद वह मानती है कि बदली परिस्थितियों में भारती एयरटेल के लिए उसे ज्यादा मौके दिख रहे हैं। मॉर्गन स्टेनले का मानना है कि इन दोनों कंपनियों समेत मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस जियो ने टैरिफ बढ़ाने का जो फैसला किया है, वह उचित दिशा में उठाया गया कदम है।

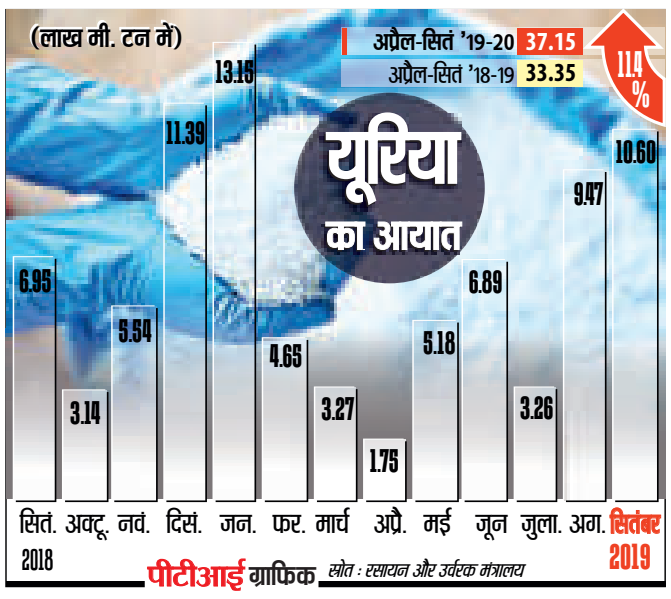

मारुति सुजुकी का उत्पादन बढ़ा

नई दिल्ली, आइएएनएस : देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा है कि नवंबर में उसके उत्पादन में 4.3 प्रतिशत का उछाल देखा गया है। शेयर बाजारों को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि नवंबर में उसने 1,41,834 यूनिट कारों का उत्पादन किया। पिछले वर्ष इसी महीने में कंपनी ने 1,35,946 यूनिट का कारों का उत्पादन किया था।

आयकर विभाग ने 39 ठिकानों पर मारे छापे

नई दिल्ली, प्रेट्र : आयकर विभाग ने कर चोरी के मामले में बीएसई से जुड़े कुछ ब्रोकर और कारोबारियों के 39 ठिकानों पर छापा मारा है। इन कारोबारियों पर 3,500 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेनदेन में कर चोरी का आरोप है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सीबीडीटी ने बताया कि मुंबई, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद और गाजियाबाद स्थित 39 ठिकानों पर तीन दिसंबर को छापे मारे गए थे। बोर्ड ने बताया कि ये शेयर ब्रोकर और कारोबारी इक्विटी डेरिवेटिव सेग्मेंट के लिक्विड स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते थे। इसके बाद बहुत छोटे समय अंतराल में रिवर्स ट्रेड करते हुए नकली नफा-नुकसान दर्शाते थे। ऐसा करते हुए इन्होंने इस तरह के नफा-नुकसान के मद में 3,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बचा ली। यदि यह ट्रेडिंग नियमों के अनुरूप होती तो उन्हें इस राशि पर कर का भुगतान करना पड़ता। आयकर विभाग की छापेमारी में बीएसई में लिस्टेड कम से कम तीन छोटे स्टॉक्स में गलत तरीके से कैपिटल गेन का मामला भी सामने आया। इसमें सभी संबंधित पक्षों ने करीब 2,000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।

- बीएसई से जुड़े कई ब्रोकर और कारोबारियों पर कर चोरी का आरोप

इस तरह की गतिविधियों से फायदा उठाने वालों की संख्या हजार से ज्यादा हो सकती है। फायदा उठाने वाले पूरे देश में फैले हो सकते हैं। इनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। साथ ही यह जानने का प्रयास भी हो रहा है कि किसने कितना लाभ कमाया। छापे में 1.20 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद हुई है। सीबीडीटी ने बताया कि छापे में कई दस्तावेज और प्रमाण मिले हैं। प्रत्यक्ष कर के विभिन्न नियमों के आधार पर इनकी जांच की जा रही है।

म्यूचुअल फंड्स में निवेश के अवसर तलाश रहे निवेशकों के लिए यह सुनहरा दौर

पिछले वर्ष लगभग इसी समय जब मैं यह कॉलम लिख रहा था तो मेरे दिमाग में भारत में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआइपी) निवेश की शानदार विकास दर बसी हुई थी। उस समय मैंने लिखा था कि अगर यह रूझान जारी रहा तो अगले 15 वर्षों में न सिर्फ इक्विटी असेट बढ़कर 320 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी, बल्कि यह भारत में कुल म्यूचुअल फंड निवेश का लगभग 75 प्रतिशत होगा।

अब मुझे लगता है कि मेरा यह आकलन गलत था। पिछले कुछ माह की घटनाओं से पता चलता है कि एसआइपी का चलन इससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि एसआइपी भारतीय निवेशकों के मनोविज्ञान को बदल रही है। मैं पहले से ही इस बात की उम्मीद कर रहा था। निवेशकों पर एसआइपी का यह सबसे अहम प्रभाव है। इससे पहले इक्विटी मार्केट एक ही स्तर के आसपास घूम रहा था फिर इसमें तेजी का दौर आया। ऐसे में एसआइपी निवेशक और गैर-एसआइपी निवेशक के व्यवहार में साफ अंतर देखा जा सकता है। यह बात सिर्फ कुछ लोगों के आकलन के आधार पर नहीं कही जा रही है बल्कि यह बात म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के आंकड़ों में साफ दिखती है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एमएफआइ) हर माह म्यूचुअल फंड से जुड़े आंकड़े जारी करता है।

सितंबर, 2009 में इक्विटी और इक्विटी फंडों में निवेश का कुल प्रवाह 28 प्रतिशत कम हो गया। यानी यह 9,152 करोड़ रुपये से गिरकर 6,609 करोड़ रुपये रह गया। इसे एक बुरी खबर की तरह देखा गया। लेकिन एसआइपी निवेश 8,231 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,263 करोड़ रुपये हो गया। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि गैर-एसआइपी निवेशकों ने उसी तरह से व्यवहार किया, जिस तरह से वे पहले करते थे। उन्होंने बाजार में सही मौका देखकर रकम निकाल लिया और मुनाफा कमाने का प्रयास किया। हालांकि एसआइपी निवेशक इसका अपवाद रहे और उन्होंने अच्छे या बुरे समय में निवेश जारी रखा।

धीरेंद्र कुमार, सीईओ
वैल्यू रिसर्च

बोनस

एसआइपी निवेश की विकास दर को लेकर एक वर्ष पहले जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, असल में विकास उससे कहीं ज्यादा हुआ है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि कुछ वर्ष पहले तक इक्विटी बाजार एक दायरे में था और उसमें कोई तेज विकास नहीं दिख रहा था, जो पिछले कुछ वर्षों में दिखा है। ऐसे में यह सहज था कि लोग एसआइपी में निवेश के प्रति ज्यादा आकर्षित होते, और यही हो रहा है। इस लिहाज से कहें, तो इकोनॉमी की वर्तमान हालत को देखते हुए कुछ लोग जिस कदर निराशावादी हो रहे हैं, वैसा होने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी कभी दिनों और महीनों के चश्मे से नहीं देखी जाती, बल्कि इसका व्यवहार दशकों का है।

यह म्यूचुअल फंड निवेश की नई दुनिया है, जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। मेरा हमेशा से मानना था कि समय के साथ भारतीय निवेशकों का रवैया बदलेगा और वे इसी दिशा में जाएंगे। मैंने पहले कभी ऐसा उत्साह महसूस नहीं किया था, क्योंकि इस बार यह वास्तव में होता हुआ दिख रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि निवेशकों के रवैये में यह बदलाव अपने आप हो रहा है और वे खुद इस बदलाव को मजबूत कर रहे हैं। जैसे-जैसे अधिक से अधिक निवेशकों को एसआइपी का अनुभव हो रहा है वे बेहतर रिटर्न और सुकून हासिल कर रहे हैं।

भारतीय निवेशकों के रवैये में बड़े पैमाने पर बदलाव आने का कारण यह भी है कि साथ ही साथ म्युचुअल फंडों की दुनिया भी लगातार बेहतरी की ओर बढ़ती रही है। ये बदलाव अचानक नहीं हुए हैं, बल्कि इसमें एक दशक से भी अधिक का समय लगा है। हालांकि, एक के बाद एक सभी बड़ी दिक्कतों को दूर किया गया है। ये सभी बदलाव कदम-दर-कदम हुए हैं। ऐसे में इस बात का अनुभव करना थोड़ा कठिन है कि इससे क्या फर्क पड़ा है। हालांकि अगर आप इन सभी बदलावों को एक साथ देखें तो आपको पता चलेगा कि इससे भारतीय बचतकर्ताओं को एक नया विकल्प मिला है। सही मायने में अगर आप 17 साल पहले से तुलना करें तो आज के म्यूचुअल फंड अब पूरी तरह से नए प्रोडक्ट हैं। अहम बात यह है कि ये सभी बदलाव बेहतरी के लिए हुए हैं, और इसने म्यूचुअल फंड को एक बेहतरीन जरिया बना दिया है जिससे भारतीय बचतकर्ता रकम बना सकें।

हम म्यूचुअल फंड में निवेश इसलिए करते हैं जिससे हम आर्थिक विकास में अपना हिस्सा हासिल कर सकें। एफडी वह फायदा नहीं देता, जो म्यूचुअल फंड देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी विकास दर को लेकर कही और गढ़ी जाने वाली बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि हम हमेशा इस बात को बढ़ा-चढ़ाकर आंकते हैं कि एक वर्ष में क्या कर सकते हैं और इस बात को कम करके आंकते हैं कि 10 वर्षों में क्या कर सकते हैं। यह बात बचत और निवेश के लिए ज्यादा सही है। महीनों और वर्ष को खुद पर हावी मत होने दीजिए, यह दशक है जो आपके लिए मायने रखता है।

21 में से 28 सीटों पर जीत मिली है डोमिनिका में प्रधानमंत्री रूजवेल्ट की पार्टी को। इसके साथ ही उनका पांचवीं बार सत्ता में आने का रास्ता साफ होता दिख रहा है।

पाकिस्तान के ढोंग से फिर बचा हाफिज

दोहरा चेहरा ▶ मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर नहीं तय हो पाए आरोप

अब 11 को तय होंगे आरोप, सह आरोपित के कोर्ट में नहीं आने पर बढ़ी तारीख

हाफिज सईद। फाइल

लाहौर, प्रेट्र: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद के मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान का ढोंग और दोहरा चरित्र सामने आया है। शनिवार को लाहौर स्थित आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) उसके खिलाफ आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित आरोप तय नहीं कर सकी, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल सुनवाई में एक सह आरोपी को पेश नहीं किया जा सका। यह घटनाक्रम भारत की उस प्रतिक्रिया के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें भारत ने कहा था कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में न केवल बेरोकटोक घूम रहा है, बल्कि उसके आतिथ्य का आनंद भी ले रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कहा था कि भारत ने सईद से संबंधित सभी साक्ष्य पाकिस्तान को सौंप दिए हैं और अब हमले के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है।

एटीसी ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और एक अन्य आरोपी मलिक जफर इकबाल के खिलाफ आरोपों को तय करने के लिए अब 11 दिसंबर की तारीख तय की है। अदालत में हुई सुनवाई के बाद एक न्यायिक अधिकारी ने बताया कि पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग की प्राथमिकी के तहत हाफिज सईद और अन्य के खिलाफ आरोप तय होने थे, लेकिन सह आरोपी मलिक जफर इकबाल को जेल से लाया नहीं जा सका। इसके कारण अब 11 दिसंबर को आरोप तय किए जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल से अदालत लाया गया। सुरक्षा के चलते पत्रकारों को अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। बता दें कि एक दिसंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने सईद और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने की तारीख सात दिसंबर तय की थी।

पाक ने आतंकियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट एफएटीएफ को सौंपी

इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तान ने शनिवार को 22 बिंदुओं पर कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट एफएटीएफ को सौंप दी। आतंकवादी संगठनों और संगठित अपराधी गिरोहों के अर्थतंत्र पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को आतंकी संगठनों के खिलाफ 27 बिंदुओं पर सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। लेकिन पाकिस्तान 22 पर ही काम कर सका।

अक्टूबर में हुई एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ कुछ खास न कर पाने पर सदस्य देशों ने असंतोष जताया था और उसे ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रस्ताव तैयार किया था। लेकिन पाकिस्तान के मित्र चीन, मलेशिया और तुर्की ने उसे ब्लैक लिस्ट में जाने के बचा लिया। इसके बाद सदस्य देशों ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया था। एफएटीएफ ने फरवरी 2020 में होने वाली अपने वृहत बैठक से

27 में से 22 बिंदुओं पर ही काम कर सका पाकिस्तान

पहले पाकिस्तान को आतंकी संगठनों के खिलाफ 27 बिंदुओं पर कार्य करने का मौका दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान एक बार फिर विफल रहा तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। एफएटीएफ की प्लेनरी बैठक फरवरी 2020 में होगी। उसमें पाकिस्तान पर भी चर्चा होगी। इस रिपोर्ट को दाखिल करने के बाद पाकिस्तान ने खुद को ग्रे लिस्ट से निकालने की मांग की है, जिससे उसकी छवि में सुधार आए और उसके यहां विदेशी पूंजीनिवेश गति पकड़ सके।

एफएटीएफ ने अपने प्रतिक्रिया में कहा है कि पाकिस्तान सभी 27 बिंदुओं पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। वह चिह्नित आतंकियों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर और उनके अर्थतंत्र को बर्बाद करे।

बगदाद में प्रदर्शनकारियों पर बंदूकधारियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, 25 लोगों की मौत

बगदाद, एएनआइ : इराक की राजधानी बगदाद में एक रैली में जुटे प्रदर्शनकारियों पर कुछ बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। इसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 130 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। बगदाद समेत पूरा इराक पिछले दो माह से सरकार विरोधी प्रदर्शनों की चपेट में है।

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, यह वारदात शुक्रवार शाम उस समय हुई, जब मध्य बगदाद के अल-खलानी स्क्वायर इलाके में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। इसी दौरान असैन्य वाहनों से आए कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने राइफलों से उन पर गोलियां बरसा दीं। इसके चलते प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मच गई और वे जान बचाने के लिए समीप की इमारतों और मस्जिद की ओर भागने लगे। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद प्रदर्शनकारियों में रोष बढ़ गया है। उन्होंने शनिवार को शहर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।

सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 440 की जा चुकी है जान : सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ बगदाद में गत एक अक्टूबर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल चुका है। दो माह से जारी विरोध प्रदर्शनों ने कई बार हिंसक रूप भी लिया। सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़पों में 440 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 20 हजार घायल हुए।

प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी के इस्तीफे के बावजूद विरोध प्रदर्शन थमा नहीं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सभी भ्रष्ट नेताओं के हटने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

इराक की राजधानी बगदाद में बंदूकधारियों की फायरिंग में घायल प्रदर्शनकारी का उपचार करते चिकित्सक। एएफपी

ईरान में सात हजार प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

जेनेवा, आइएएनएस : संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि ईरान में मध्य नवंबर से सात हजार से ज्यादा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वालों की तेजी से गिरफ्तारी की जा रही है।

मौलवी सद्र के घर ड्रोन से किया गया हमला

समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, इराक में शिया समुदाय के पवित्र शहर नजफ में मौलवी मोक्तदा सद्र के घर पर ड्रोन से बम गिराया गया। हालांकि हमले के समय सद्र घर पर नहीं थे। वह इस समय इराक से बाहर बताए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन किया है।

न्यूज गैलरी

कंधार में मारे गए 15 तालिबानी आतंकी

काबुल : अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत कंधार में अफगान सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में जहां 15 तालिबानी आतंकी मारे गए, वहीं दो को गिरफ्तार कर लिया गया। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अफगान नेशनल आर्मी के ऑपरेशनल कार्प्स के हवाले से बताया कि इस ऑपरेशन को शुक्रवार को निस जिले के किझक इलाके में अंजाम दिया गया। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन पर तालिबान ने कोई टिप्पणी नहीं की है। (एएनआइ)

फेस स्कैन की योजना अमेरिका ने टाली

सैन फ्रांसिस्को : डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने फिलहाल उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसमें अमेरिका में प्रवेश करने और वहां से जाने से पहले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का फेस स्कैन किया जाना था। सीमा सुरक्षा और आव्रजन जांच की जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वह सुरक्षा संबंधी नियमों में संशोधन करना चाहता है। नए नियमों के तहत अमेरिकी नागरिकों सहित सभी यात्रियों का अमेरिका में प्रवेश और यहां से जाने से पहले फेस स्कैन किए जाने का प्रस्ताव था। (आइएएनएस)

आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप बंद करे अमेरिका : चीन

बीजिंग : चीन के शीर्ष राजनयिक यांग जिइचेी ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो से शनिवार को फोन पर वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका को उसके आतंरिक मामलों में दखल देने से बाज आना चाहिए। उइगर मानवाधिकार नीति बिल और हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र कानून का हवाला देते हुए यांग ने कहा कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय संबंधों का उल्लंघन कर रहा है। वाशिंगटन से अपनी गलतियों को सुधारने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि वह तुरंत चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने से बाज आए। (रायटर)

अमेरिकन चैंबर ऑफ कामर्स की अध्यक्ष को मकाऊ में हिरासत में रखा

हांगकांग : अमेरिकन चैंबर ऑफ कामर्स की अध्यक्ष ने शनिवार को कहा कि उन्हें चीन शासित मकाऊ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान उन्हें आव्रजन अधिकारियों ने लगभग दो घंटे तक हिरासत में रखा। अमेरिकी नागरिक तारा जोसेफ ने कहा कि वह पूर्व में पुर्तगाली उपनिवेश रहे मकाऊ की यात्रा पर गई थीं, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी। इसके पीछे उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया। (रायटर)

मौत की सजा पर रोक हटाने से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

वाशिंगटन, एएफपी: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पर लगाई रोक हटाने से इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत के इस फैसले से मौत की सजा जल्द से जल्द बहाल करने की डोनाल्ड ट्रंप सरकार के न्याय विभाग की योजना पर पानी फिर गया है। बता दें कि अमेरिकी सरकार ने वर्ष 1988 में मौत की सजा बहाल की थी और तब से लेकर अब तक संघीय सरकार द्वारा केवल तीन लोगों को ही मृत्युदंड की सजा दी गई है। आखिरी बार 16 साल पहले मौत की सजा दी गई थी।

दरअसल, न्याय विभाग संघीय अपराधों के लिए मौत की सजा बहाल करना चाहता है और अगला मृत्युदंड सोमवार को दिया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर लगी रोक हटाने से इन्कार कर दिया। श्वेत वर्चस्व को मानने वाले डेनियल लुईस को आठ साल की बच्ची समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या करने के 1996 के मामले में मौत की सजा दी जानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार के अपने आदेश में कहा है सजा के निष्पादन पर रोक की अपील को निचली अदालतों द्वारा सुना जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि फिलहाल याचिका खारिज कर दी गई है, लेकिन अगर निचली अदालतों में 60 दिनों के अंदर इस पर कोई फैसला नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में

सजा जल्द बहाल करने की ट्रंप सरकार की योजना पर पानी फिरा

प्रतीकात्मक

याचिका दोबारा दाखिल की जा सकती है। अटार्नी जनरल बिल बार ने जुलाई में घोषणा की थी कि इंडियाना की जेल में बंद हत्या के पांच दोषियों को मौत की सजा देने के लिए एक नया घातक इंजेक्शन प्रोटोकॉल को अपनाया जाएगा। इस तरह के इंजेक्शन में पेंटोबार्बिटल नामक घातक दवा का प्रयोग किया जाता है। इन सजाओं का निष्पादन नौ दिसंबर से 15 जनवरी 2020 के बीच किया जाना था। दोषियों के वकीलों ने प्रोटोकॉल की वैधानिकता को चुनौती दी तो निचली अदालतों ने इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इसी के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।

दोहा में फिर शुरू हुई अमेरिका-तालिबान के बीच शांति वार्ता

दोहा, एजेंसियां: अमेरिका ने कतर की राजधानी दोहा में शनिवार से तालिबान के साथ बातचीत एक बार फिर से शुरू कर दी। इसमें अफगानिस्तान सुलह के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जालमे खलीलजाद भी शामिल हुए। एक अमेरिकी सूत्र ने यह जानकारी दी है। बता दें कि तीन महीने पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए आत्मघाती हमले में एक अमेरिकी सैनिक की मौत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी समूह के साथ वार्ता स्थगित कर दी थी।

सूत्र ने बताया, 'अमेरिका ने तालिबान से दोहा में शनिवार से फिर बातचीत शुरू कर दी। शांति वार्ता का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति कायम करने के साथ ही संघर्ष विराम को स्थायी बनाना है। इसी साल सितंबर में अमेरिका और तालिबान एक समझौते पर दस्तखत करने के करीब पहुंच गए थे। अगर यह समझौता हो जाता तो सुरक्षा की गारंटी के बदले अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद अपने हजारों सैनिकों की वापसी की शुरुआत कर देता। इतना ही नहीं इस समझौते के बाद तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच सीधी वार्ता का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता, लेकिन अमेरिकी सैनिक के मारे जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कैंप डेविड में होने वाली वार्ता को रद कर दिया था।

चीन को कर्ज देने पर डोनाल्ड ट्रंप विश्व बैंक से खफा

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को कर्ज दिए जाने को लेकर विश्व बैंक से खफा हो गए हैं। उन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की आलोचना करते हुए बीजिंग को कर्ज दिए जाने पर सवाल उठाए हैं।

ट्रंप ने शुक्रवार को ट्वीट के जरिये पूछा, 'विश्व बैंक चीन को लोन क्यों दे रहा है? क्या यह संभव हो सकता है? चीन के पास बहुत धन है, अगर नहीं है तो वह इसका प्रबंध करे। कर्ज रोका जाए।' अमेरिकी वित्त मंत्री स्टीवन मेनुचिन ने भी इसी तरह की बात एक दिन पहले कही थी। स्टीवन ने गुरुवार को संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की एक समिति से कहा था, 'अमेरिका ने चीन में विश्व बैंक के बहुवर्षीय लोन प्रोग्राम और प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई है।' अमेरिका की यह दलील है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला चीन इतना संपन्न है कि वह खुद ही पूंजी की व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए वह विश्व बैंक पर निर्भर नहीं है। इस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान को गरीब देशों के लिए वित्तीय स्रोत बनने पर ध्यान देना चाहिए। जबकि विश्व बैंक में चीन मामलों के निदेशक मार्टिन रेजर ने कहा, 'यह प्रोग्राम चीन के साथ हमारे संबंधों की प्रगति को दर्शाता है।'

हर साल मिलेगा दस हजार करोड़ : समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, विश्व बैंक ने चीन को वित्तीय मदद मुहैया कराने के प्रोग्राम को गुरुवार को स्वीकृति दी। इस प्रोग्राम के तहत चीन को जून 2025 तक निम्न ब्याज पर हर साल एक अरब से लेकर डेढ़ अरब डॉलर (करीब सात हजार से दस हजार करोड़ रुपये) का कर्ज दिया जाएगा।

पूछा, बीजिंग को क्यों दिया जा रहा लोन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रायटर

चीन-अमेरिका में 18 माह से कारोबारी जंग

ट्रंप का यह रुख ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और चीन में गत 18 माह से छिड़ी कारोबारी जंग को खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है। हालांकि दोनों देशों में इस मसले पर किसी करार को लेकर अनिश्चितता बरकरार है।

एच-1बी वीजा के लिए अमेरिका ने तैयार की ई-पंजीकरण प्रक्रिया

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका की संघीय आव्रजन एजेंसी ने एलान किया है कि उसने 2021 के वीजा के लिए एच-1बी इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रक्रिया लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अब वित्त वर्ष 2021 के लिए विदेशी कर्मचारियों के वास्ते एच-1बी वीजा का आवेदन करने वाली कंपनियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराने के साथ ही 10 डॉलर का शुल्क भी देना होगा। बता दें कि एच-1बी वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को उनकी विशेषज्ञता के चलते अपने यहां काम पर रखने की अनुमति प्रदान करता है। भारत और चीन जैसे देशों के हजारों कर्मचारी अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनियों में इसी वीजा के तहत काम कर रहे हैं।

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआइएस) वित्त वर्ष 2021 के लिए एक अप्रैल 2020 से एच-1बी वीजा आवेदन लेना शुरू करेगी। एच-1बी वीजा आवेदनों को मंजूरी प्रदान करने वाली इस एजेंसी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रक्रिया से कागजी काम कम होगा और आवेदनकर्ताओं का पैसा भी बचेगा। नई प्रक्रिया के तहत एच-1बी वीजा के जरिये कर्मचारी नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

उत्तर कोरिया से वार्ता जारी रखने पर ट्रंप और जे-इन मून राजी

सियोल, रायटर : उत्तर कोरिया के साथ परमाणु वार्ता में आए गतिरोध को दूर करने के प्रयास में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष जे-इन मून से फोन पर करीब आधे घंटे तक बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने उत्तर कोरिया के साथ कूटनीतिक संबंध और वार्ता जारी रखने के तौर-तरीके पर चर्चा की।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भवन ब्लू हाउस ने शनिवार को बयान में बताया, 'ट्रंप और मून में इस बात को लेकर सहमति बनी कि कोरियाई प्रायद्वीप में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तर कोरिया के साथ वार्ता को जारी रखा जाना चाहिए।' परमाणु मसले पर ट्रंप और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के बीच दो बार शिखर वार्ता हो चुकी है। पहली बार दोनों नेताओं ने गत वर्ष जून में सिंगापुर में बातचीत की थी। इसके बाद उनकी दूसरी वार्ता इस साल फरवरी में वियतनाम में हुई थी, लेकिन उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग पर यह वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गई थी।

21वीं सदी में महाशक्ति बन सकता है भारत : श्रृंगला

वाशिंगटन, प्रेट्र: भारतीय अर्थव्यवस्था का रथ आगे बढ़ रहा है और 21वीं सदी में देश के महाशक्ति बनने की सभी परिस्थितियां वर्तमान में मौजूद हैं। यह बात अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को कही। वह हार्वर्ड केनेडी स्कूल में विद्यार्थियों और अध्यापकों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने 'भारत की आर्थिक वृद्धि एवं विकास' विषय को लेकर अपने संबोधन में कहा, 'भारत को एक लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में आजादी के बाद 60 साल लगे। इसके बाद दो लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में 12 साल लगे। अब महज पांच साल में 2014-19 के दौरान यह दो लाख करोड़ डॉलर से तीन लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया है।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को 2025 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और हम सभी इसे पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।'

श्रृंगला ने कहा, 'भारत की वृद्धि उसकी बुनियाद पर आधारित है। हमने वृद्धि की गति को तेज करने के साथ ही वृहद स्थिरता,

हर्षवर्धन श्रृंगला। फाइल

टिकाऊ तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल की है। हमने सामाजिक सामंजस्य, लोकतंत्र और कानून का राज बनाए रखते हुए उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल की।' उन्होंने कहा कि कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष आय में असमानता की दिक्कतें रही हैं, लेकिन 1990 के बाद उदारीकरण को अपनाने से लेकर अब तक भारत लाखों लोगों को गरीबी रेखा से उबारने में कामयाब हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में 2030 तक हर दो में से एक परिवार के मध्यमवर्गीय हो जाने का अनुमान है। तब तक देश विश्वबैंक के वर्गीकरण के हिसाब से उच्च-मध्यम आय वाला देश बन जाएगा।

हांगकांग में खास जनसभा आज पुलिस की रणनीति बनाकर तैनाती

हांगकांग, रायटर : हांगकांग के आंदोलन को मिल रहे वैश्विक समर्थन के चलते पुलिस रणनीति बदलकर उससे निपटने की राह पर चल निकली है। लोकतंत्र समर्थकों की रविवार को आयोजित जनसभा के प्रति पुलिस ने लचीला रवैया अपनाने का फैसला किया है। नए पुलिस प्रमुख क्रिस टैंग ने कहा है कि हम आंदोलनकारियों के प्रति आक्रामक रवैया नहीं अपनाएंगे। किसी भी उपद्रव को भड़कने से रोका जाएगा और उसके नियंत्रण के लिए न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया जाएगा। जनसभा में लाखों की संख्या में लोगों के आने के आसार हैं।

क्रिस टैंक ने कहा, हम सख्त और नरम रुख अपनाते हुए कार्य करेंगे और पूर्व की अपेक्षा ज्यादा लचीला रवैया अपनाएंगे। शांतिपूर्ण जनसभा और जुलूस में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन आंदोलनकारी हिंसक हुए तो पुलिस उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। जनसभा का आयोजन एक मानवाधिकार संगठन ने किया है। यह संगठन पहले भी लोकतंत्र समर्थकों के

हांगकांग में शनिवार को लोगों ने चीन के समर्थन में भी रैली की। रायटर

कई कार्यक्रम आयोजित कर चुका है। हांगकांग में हाल ही में हुए निकाय चुनावों में मिली भारी सफलता और अमेरिका द्वारा समर्थन में बनाए गए कानून से लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारी उत्साहित हैं। पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय में पुलिस की कार्रवाई से आंदोलन में जो बाधा आई थी, बाद के इन दो कारणों से वह काफी हद तक दूर हो गई है और आंदोलनकारी बढ़े उत्साह के साथ फिर से एकजुट हो रहे हैं। हांगकांग में छह महीने से लोकतंत्र की मांग वाला आंदोलन जारी है। इस बीच हांगकांग में अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष तारा जोसेफ को शनिवार को मकाऊ में प्रवेश करने से रोक दिया गया। हवाई अड्डे पर दो घंटे तक उन्हें हिरासत की स्थिति में रखा गया और वहां से वापस कर दिया गया। मकाऊ भी चीन के अधिकार वाला इलाका है। अमेरिकी नागरिक तारा को रोके जाने का कारण नहीं बताया गया।

सुलह के आसार

बेहद तल्ख माहौल में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की जगी उम्मीद, ट्रंप के कार्यकाल में कैदियों की अदला-बदली की घटना मानी जा रही अप्रत्याशित

अमेरिका और ईरान ने मुक्त किए एक-दूसरे के नागरिक

दुबई, रायटर : अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तल्खी और तनाव पैदा करने वाले बयानों और प्रतिबंधों से इतर भी 'कुछ' चल रहा है। इसी का नतीजा है कि शनिवार को दोनों देशों ने अपने यहां कैद एक-दूसरे के नागरिकों को आजाद किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कैदियों की ऐसी अदला-बदली की घटना अप्रत्याशित मानी जा रही है। ट्रंप 2015 में अपने चुनाव प्रचार के समय से ही ईरान के खिलाफ लगातार आग उगलते रहे हैं। कुछ महीने पहले हालात युद्ध वाले भी बन गए थे।

ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी नागरिक शीयू वांग को ईरान से मुक्त किया गया है। जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया बीजिंग में जन्मा वांग तीन साल से ईरानी जेल में कैद था। जबकि अमेरिका ने ईरानी नागरिक मसूद सुलेमानी को जेल से मुक्त किया है। स्विट्जरलैंड ने कैदियों की अदला-बदली में बिचौलिये की भूमिका निभाई। ईरान के विदेश मंत्री मुहम्मद जवाद जरीफ ने ज्यूरिच में अमेरिका से मुक्त होकर आए सुलेमानी का स्वागत किया। सुलेमानी के रविवार तक ईरान पहुंचने की संभावना है। व्हाइट

यह तस्वीर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने सात दिसंबर, 2019 को जारी की थी। इसमें प्रिंसटन के छात्र शीयू वांग (मध्य में) अपनी पत्नी और बेटे के साथ नजर आ रहे हैं। वांग को ईरान में हिरासत में लिया गया था। फाइल/एएफपी

हाउस के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने सुलेमानी के बारे में कुछ नहीं बोला है। लेकिन वांग की रिहाई में स्विट्जरलैंड सरकार की मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया है।

ट्रंप ने कहा है कि कैद अमेरिकी की आजादी उनके प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशी जेलों में झूठे आरोपों में बंद अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के लिए हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। जबकि जवाद जरीफ ने सुलेमानी के साथ अपनी फोटो ट्विटर पर डाली हैं। जरीफ ने ट्वीट किया है- खुशी की बात है कि प्रोफेसर मसूद सुलेमानी और शीयू वांग जल्द ही अपने परिवारों से मिलेंगे। स्विट्जरलैंड की सरकार समेत उन सभी को बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया। ईरानी समाचार एजेंसी इरना ने कहा है कि वांग को इस्लाम धर्म में व्याप्त दया की भावना के तहत रिहा किया गया है। अमेरिका के प्रिंस्टन विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट वांग को 2017 में ईरानी अदालत ने जासूसी का दोषी मानते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई थी। वांग और उसके परिजनों का कहना है कि वह शोध कार्य के सिलसिले में ईरान गया था। जबकि ईरान के प्रोफेसर सुलेमानी स्टेम सेल एक्सपर्ट हैं। उन्हें 2018 में शिकागो एयरपोर्ट से तब गिरफ्तार किया गया था जब वह जीव विज्ञान में काम आने वाला कुछ सामान ईरान भेज रहे थे। यह ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन था।

उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड का राजदूत ईरान में अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। यह व्यवस्था ईरान में 1979 में हुई इस्लामी क्रांति के समय से ही चल रही है। तब अमेरिका और ईरान ने आपसी कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर लिए थे।

लीबिया में रूसी वायुसेना ने मार गिराया था अमेरिकी ड्रोन

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिकी सेना का दावा है कि पिछले महीने लीबिया की राजधानी त्रिपोली के निकट लापता हुए उसके हथियार रहित ड्रोन को वास्तव में रूसी वायुसेना ने मार गिराया था। अमेरिकी सेना ने ड्रोन के मलबे को वापस करने की मांग की है। अमेरिकी अफ्रीका कमान ने यह जानकारी दी।

कमान का कहना है कि यह घटना तेल संपन्न देश लीबिया के गृहयुद्ध में रूसी भूमिका को उजागर करती है। वह इस गृहयुद्ध में पूर्वी लीबिया के कमांडर खलीफा हफ्तार की तरफ से दखल दे रहा है। हफ्तार ने त्रिपोली पर कब्जे का एलान किया है, जो अभी लीबिया की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सरकार गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड (जीएनए) के नियंत्रण में है। अमेरिकी अफ्रीका कमान के प्रमुख जनरल स्टीफेन टाउनसेंड ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि हमले के समय वायु सैनिकों को यह पता नहीं होगा कि रिमोट संचालित ड्रोन अमेरिका का है,

रुस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन (बाएं) और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

गत महीने त्रिपोली के पास लापता हुए ड्रोन के संबंध में अमेरिकी सेना ने किया दावा

लेकिन अब उसे निश्चित तौर पर पता होगा कि ड्रोन किसका है? मुझे नहीं पता कि अब वह कहां है, लेकिन मैं उसे लेकर कोई सौदा नहीं करने जा रहा हूं।' अमेरिका का मानना है कि 21 नवंबर को उसके ड्रोन पर हमला रूसी निजी सैन्य ठेकेदारों या हफ्तार की कथित लीबियन नेशनल आर्मी ने किया होगा।

ये भी जानिए

युजवेंद्रा सिंह चहल एक विकेट लेते ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। फिलहाल अश्विन और चहल दोनों के 52-52 विकेट हैं।

विराट के 'ऑटोग्राफ जश्न' ने जीता अमिताभ का दिल

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय कप्तान विराट कोहली के आक्रामक अंदाज से पूरी दुनिया वाकिफ है। इस बार वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज केसरिक विलियम्स की थी, जिन्होंने 2017 के वेस्टइंडीज दौरे पर विराट को आउट करके अपने 'नोटबुक ऑटोग्राफ अंदाज' में जश्न मनाया था। कोहली को वह अच्छे से याद था और उन्होंने शुक्रवार को हैदराबाद में विलियम्स का धागा खोल दिया। फिर उन्हीं के अंदाज में 'नोटबुक ऑटोग्राफ जश्न' मनाकर उन्हें करारा जवाब दिया। दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के साथ ही बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी कोहली का यह अंदाज खूब भाया। उन्होंने ट्विटर पर कोहली की तारीफ के पुल बांध दिए।

तारीफ

- 'अमर अकबर एंथनी' के डायलॉग से दी भारतीय कप्तान को बधाई
- कोहली ने भी बॉलीवुड महानायक का जताया आभार

अमिताभ बच्चन। फाइल फोटो, प्रेट्र

जब अमिताभ फिर बने एंथनी : अमिताभ ने कोहली की तारीफ के लिए फिल्मी डायलॉग का इस्तेमाल किया। कोहली की तारीफ के लिए अमिताभ ने मनमोहन देसाई निर्देशित अपनी फिल्म अमर अकबर एंथनी का डॉयलॉग बोला। अमिताभ ने ट्विटर पर लिखा, 'यार कितनी बार बोला मई तेरे को ...कि विराट को मत छेड़, मत छेड़, मत छेड़ पन सुनताइच किधर है तुम। अभी पर्ची लिख के दे दिया ना हाथ में। देख देख ...वेस्टइंडीज का चेहरा देख ... कितना मारा उसको, कितना मारा।' दरअसल अमिताभ की फिल्म 'अमर अकबर एंथनी' में एक गुंडे जिबिस्को से पिटने के बाद आइने के सामने खड़े होकर वह ऐसा ही डायलॉग बोलते हैं।

कोहली ने जताया आभार: कोहली ने अमिताभ के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी, मुझे यह डायलॉग बहुत पसंद है सर। आप हमेशा एक प्रेरणास्त्रोत हैं।

2017 में विराट को आउट करने के बाद जश्न मनाते केसरिक विलियम्स (बायें)। 2019 में उस पर प्रतिक्रिया देते विराट ● ट्विटर

केसरिक विलियम्स का अनोखा जश्न

नई दिल्ली : वेस्टइंडीज का यह तेज गेंदबाज हमेशा बल्लेबाजों को आउट करने के बाद इसी तरह से जश्न मनाता है। वह जब भी विकेट लेते हैं तो जेब से डायरी निकालने का एक्शन दिखाते हैं और फिर अंगुलियों से पन्ने पलटते हुए दिखाई देते हैं और बाद में अनोखे अंदाज में उसमें दस्तखत करने का इशारा करते हैं। इस बार विराट ने भी उनके खिलाफ 16वें ओवर में लगातार चौका-छक्का मारने के बाद जेब से नोटबुक निकालने और ऑटोग्राफ देने का वैसा ही इशारा किया। विराट को दो साल पहले अपने साथ हुई घटना याद थी। पिछले वर्ष कैरेबियाई प्रीमियर लीग में विलियम्स ने चेडरिक वॉल्टन को आउट करने के बाद ऐसा ही इशारा किया था, लेकिन अगले मैच में वॉल्टन ने उनसे बदला लिया। वॉल्टन जब भी केसरिक की गेंद पर चौका या छक्का लगाते, उन्हें इसी अंदाज में इशारा करते।

> कैरेबियन लीग की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। जब हम 2017 में वेस्टइंडीज गए थे तो जमैका में हुए मैच में विलियम्स ने मुझे आउट करने के बाद इस तरह का जश्न मनाया था। मैंने भी उसके खिलाफ ऐसा ही किया। -विराट कोहली (अपने ऑटोग्राफ जश्न पर)

कोहली के अंदाज से दिक्कत नहीं : पोलार्ड

हैदराबाद : भारतीय कप्तान विराट कोहली का नोटबुक ऑटोग्राफ सेलिब्रेशन चर्चा में है। सोशल मीडिया पर उनका उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस मामले पर विपक्षी कप्तान कीरोन पोलार्ड से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बल्लेबाज खुद को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करते हैं। इसके साथ ठीक हूं मैं। उन्होंने कहा कि यह खेल का हिस्सा होता है। कभी-कभी आपको खुद को रन बनाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में ऐसा करना पड़ता है।

एक नजर में

मुठभेड़ पर लोगों के जश्न से निराश थी : ज्वाला

नई दिल्ली : पूर्व भारतीय शटलर ज्वाला गुट्टा ने शनिवार को कहा कि वह हैदराबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए रेप के आरोपियों की मौत के बाद लोगों के जश्न से निराश थीं। हैदराबाद रेप केस में शामिल चारों आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को मुठभेड़ में मार गिराया था। उन्होंने साथ ही कहा वह संतुष्ट हैं कि कुछ लोग मेरी बात से सहमत हैं। शुक्रवार को वाकई में मैं बहुत ही परेशान और निराश थी कि लोग किस तरह से जश्न मना रहे हैं। मैं सो तक नहीं पाई। (एएनआइ)

टाइगर वुड्स की निगाहें विश्व चैलेंज पर

नस्साऊ (बहामास) : हीरो विश्व चैलेंज के फाइनल दौर में गैरी वुडलैंड ने एक शॉट की बढ़त बनाई हुई है, जबकि टाइगर वुड्स 2011 के बाद अपने पहले खिताब की तलाश के साथ तीसरे स्थान पर हैं। यूएस ओपन चैंपियन वुडलैंड ने तीसरे दौर में चार अंडर-68 लगाकर अमेरिकन साथी पैट्रिक रीड को शीर्ष स्थान से हटा दिया। रीड ने दो शॉट पेनाल्टी के लगाए क्योंकि गेंद रेत में चली गई थी। हालांकि रीड के लिए मुश्किल की बात नहीं है क्योंकि तीसरे दौर में 74 अंक के साथ वह शीर्ष पर पहुंचने से तीन शॉट दूर हैं। (प्रेट्र)

रेलवे की आठ मुक्केबाज फाइनल में

कुन्नूर (केरल) : मौजूदा चैंपियन रेलवे की आठ मुक्केबाजों ने शनिवार को मुंडायाड इंडोर स्टेडियम में जारी चौथी एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना वर्चस्व कायम करते हुए फाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। इनमें सोनिया चहल (57 किग्रा) और भाग्यवती काचारी (75 किग्रा) प्रमुख हैं। इसके अलावा ज्योति (51 किग्रा), कविता चहल (81 किग्रा), मीना कुमारी देवी (54 किग्रा) ने फाइनल में जगह बनाई। (प्रेट्र)

जीत की पटरी पर लौटना चाहेगा एफसी गोवा

हैदराबाद : एफसी गोवा रविवार को यहां जीएमसी बालायोगी एथलेटिक स्टेडियम में मेजबान हैदराबाद एफसी को हराकर इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) में जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। पिछले दो मैचों में केवल एक अंक हासिल करने वाली कोच सर्जियो लोबेरा की एफसी गोवा के पास शीर्ष चार में पहुंचने का मौका है। दूसरी तरफ हैदराबाद एफसी के छह मैचों में केवल चार अंक है और अगर मेजबान टीम यहां गोवा के खिलाफ कोई उलटफेर करती है तो वह अन्य टीमों को प्रभावित कर सकती है। (आइएएनएस)

भारत ने न्यूजीलैंड को हराया

कैनबरा : शर्मिला देवी के दो गोलों की मदद से भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने तीन देशों के टूर्नामेंट के अपने तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया। न्यूजीलैंड के लिए ओलिविया शेनोन ने चौथे मिनट में ही गोल दाग दिया। शर्मिला ने 12वें और 43वें मिनट में गोल किया जबकि ब्यूटी डुंगडुंग ने 27वें और लालरिंडिकी ने 48वें मिनट में गोल दागे। (प्रेट्र)

आज एक और ब्लॉकबस्टर की उम्मीद

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी-20 आज, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में सुधार करना चाहेगी टीम इंडिया

तिरुवनंतपुरम, प्रेट्र: भारतीय टीम जब रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी-20 मुकाबले में उतरेगी तो वह अपने गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में सुधार करना चाहेगी। इसी के साथ एक बार फिर बल्लेबाजों के सुपर शो के जरिए सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी। शुक्रवार को मेहमान टीम को छह विकेट से हराकर भारतीय टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। भारतीय टीम ने पिछले महीने बांग्लादेश को भी टी-20 सीरीज में 2-1 से हराया था। रविवार की जीत भारतीय टीम को ना सिर्फ सीरीज में अजेय बढ़त दिलाएगी, बल्कि इससे उन्हें आगामी टी-20 विश्व कप को देखते हुए अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाने का मौका मिलेगा। भारतीय टीम ने शुक्रवार को टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य हासिल किया था। भारत ने हैदराबाद में सिर्फ 18.4 ओवर में ही 209 रन बनाकर जीत हासिल कर ली थी। जहां केएल राहुल ने 40 गेंद पर 62 रन बनाकर जीत का प्लेटफॉर्म तैयार किया, तो वहीं विराट कोहली ने नाबाद 94 रन बनाकर टी-20 करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली।

शिखर की कमी नहीं खलने देंगे राहुल : चोटिल शिखर धवन की जगह ओपनिंग करने उतरे राहुल बेहद अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस बीच कर्नाटक के बल्लेबाज राहुल टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने 29 पारियों में यह कारनामा किया और वह रविवार को भी कुछ ऐसी ही पारी खेलने की कोशिश करेंगे। पिछले मैच में दो गगनचुंबी छक्के लगाने वाले पंत के पास भी खुद पर से दबाव कम करने का मौका है। इस सीरीज से पहले उनका दस्तानों और बल्ले से प्रदर्शन खराब रहा है।

कुलदीप यादव को जगह दो : भारतीय गेंदबाज इविन लुइस, शिमरोन हेटमायर और कप्तान कीरोन पोलार्ड के आगे बेबस नजर आए थे। दीपक चाहर ने दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज में प्रभावित किया था, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को संभालना चाहर के लिए पहले मुकाबले में मुश्किल साबित हुआ। उन्होंने 54 रन देकर मात्र एक विकेट लिया। ऐसे में वह भी रविवार को अपना प्रदर्शन सुधारना चाहेंगे। टी-20 टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार एक भी विकेट नहीं ले पाए। भारतीय गेंदबाजी में सबसे कमजोर कड़ी वाशिंगटन सुंदर दिखाई दिए। वह पिछले छह टी-20 मुकाबलों में मात्र दो ही विकेट ले पाए हैं। ऐसे में विराट को अपने सर्वश्रेष्ठ टी-20 गेंदबाज कुलदीप यादव को अंतिम एकादश में जगह देनी चाहिए। उनकी और युजवेंद्रा सिंह चहल की जोड़ी कैरेबियन बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। अब देखना होगा कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के आक्रमण को देखते हुए कप्तान कोहली 20 वर्षीय सुंदर को ही टीम में रखते हैं या फिर उनकी जगह कुलदीप यादव की अंतिम-11 में वापसी कराते हैं। भारतीय टीम को क्षेत्ररक्षण में भी सुधार करने की जरूरत है। भारत के सुंदर और रोहित शर्मा कैच टपकाते दिखे। अगर इस बार भी इन्होंने कैच टपकाए तो मैच भी इनके हाथ से टपक सकता है। बाउंड्री के पास भी इन्हें मेहनत करने की जरूरत है।

वेस्टइंडीज के गेंदबाज पस्त : मेहमान टीम वापसी की जुगत में होगी और सीरीज को जिंदा रखना चाहेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें भारतीय बल्लेबाजों को रोकना जरूरी होगा। वेस्टइंडीज के गेंदबाज कोहली के आगे रविवार को पूरी तरह से बेबस नजर आए थे। तेज गेंदबाज केसरिक विलियम्स ने 3.4 ओवर में 60 दे दिए। कप्तान कीरोन पोलार्ड चाहेंगे कि उनके अनुभवी गेंदबाज जेसन होल्डर और शेल्डन कॉटरेल विकेट निकालें। मेहमान टीम ने साथ ही 23 रन अतिरिक्त दिए थे।

शनिवार को त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा। पत्नी रीवा सोलंकी और बेटी भी उनके साथ दिखीं ● प्रेट्र

भारतीय टी-20 टीम: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, संजू सैमसन, रिषभ पंत (विकेटकीपर), मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्रा सिंह चहल, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार और मुहम्मद शमी।

वेस्टइंडीज: कीरोन पोलार्ड (कप्तान), फेबियान एलेन, ब्रैंडन किंग, दिनेश रामदीन, शेल्डन कॉटरेल, इविन लुइस, शेरफेन रदरफॉर्ड, शिमरोन हेटमायर, खारे पियरे, लेंडल सिमंस, जेसन होल्डर, हेडन वाल्श जूनियर, कीमो पॉल, केसरिक विलियम्स।

वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले दूसरे टी-20 मैच के लिए शनिवार को त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा। प्रेट्र

13 महीनों में भारत ने विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज के खिलाफ सात टी-20 मुकाबले खेले हैं और सभी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है

2547 रन रोहित शर्मा और 2544 रन विराट कोहली अब तक टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बना चुके हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दोनों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है

01 मुकाबला अब तक वेस्टइंडीज की टीम ने तिरुवनंतपुरम में खेला है। नवंबर 2018 में मेहमान टीम इस मैदान पर मात्र 104 रन पर ढेर हो गई थी और नौ विकेट से हार गई थी

04 मैचों का प्रतिबंध झेलने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन रविवार को वापसी करेंगे और रामदीन की जगह विकेटकीपिंग का जिम्मा संभालेंगे

चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता कोहली की बड़ी ताकत

के श्रीकांत
कलम से

मैं दुनियाभर के क्रिकेट लेखकों की दुविधा समझ सकता हूं। विराट कोहली के बारे में कुछ भी नया लिखना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ईमानदारी से कहूं तो मैंने किसी भी बल्लेबाज को इस स्तर पर इतना निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन करते नहीं देखा। मेरे हिसाब से चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता और लक्ष्य पर ध्यान उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब उन्होंने 2009 में वापसी की थी तो हम सभी जानते थे कि वो खास खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने सभी की अपेक्षाओं से आगे बढ़ गए हैं, मेरी भी।

अगर मुझे किसी से कोहली की तुलना करनी हो तो मेरे जेहन में दो नाम आते हैं। एक ब्रायन लारा और दूसरे स्टीव वॉ। लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली का खेल अलग स्तर पर पहुंच गया। जिस समय मैंने क्रिकेट खेला, अगर वो जावेद मियांदाद और विव रिचर्डस का युग था तो ये पीढ़ी कोहली के असाधारण प्रदर्शन से जानी जाएगी। तीसरे क्रम के किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़े लक्ष्य का पीछा करने तक नाबाद रहना आसान नहीं होता। मगर भारतीय कप्तान ने असाधारण निरंतरता के साथ ऐसा करने में कामयाबी हासिल की है।

हैदराबाद में मिली जीत ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय गेंदबाजों को क्या करने की जरूरत है। पिच सपाट थी, फील्डिंग साधारण थी और भारतीय गेंदबाज आक्रामक बल्लेबाजों की फौज का सामना कर रहे थे। लेकिन भारत को अंतिम ओवरों में और विकल्प आजमाने चाहिए थे। आखिरकार सभी को मौका देना इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर ऐसा न किया गया तो गेंदबाज सुस्त हो सकते हैं। खासकर ये देखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले भारत को करीब 10 टी-20 मैच ही और खेलने हैं। निश्चित रूप से जब जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी व मुहम्मद शमी और कुलदीप यादव टी-20 अंतिम एकादश में लौटेंगे तो टीम की योजना भी बदलेगी। बावजूद इसके मौजूदा संसाधनों के साथ भी गेंदबाज और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। अगले दो मुकाबले सीखने के लिहाज से बेहतरीन होंगे और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इस प्रारूप में वेस्टइंडीज की टीम एक कड़ी चुनौती है। भारत ने अगर ये टेस्ट पास करते हुए सीरीज जीत ली तो ये विश्व कप की तैयारियों से अच्छा होगा।

खराब क्षेत्ररक्षण पर युवी ने टीम इंडिया पर निशाना साधा

क्रिकेट डायरी

हैदराबाद, आइएएनएस : पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी-20 मैच में खराब फील्डिंग को लेकर मेजबान टीम की आलोचना की है। युवराज ने ट्विटर पर लिखा कि शुक्रवार को मैदान पर भारतीय टीम का बेहद खराब प्रदर्शन। युवा खिलाड़ियों ने काफी देर बाद रिएक्ट किया। क्या यह ज्यादा क्रिकेट का असर है?

पीटरसन ने की कोहली की तारीफ: भारतीय कप्तान विराट कोहली ने विंडीज के खिलाफ खेले गए पहले टी-20 मैच में 94 रनों की नाबाद पारी खेली। मैच के बाद कोहली ने इंस्टाग्राम पर मैच की कुछ फोटो साझा की हैं और लिखा कि सीरीज की शुरुआत शानदार रही। आज की जीत से काफी सकारात्मक चीजें सीखने को मिलीं। कोहली की इस पोस्ट पर पीटरसन ने लिखा कि इस मैच में आपका फ्लिक बेहतरीन था भाई। अपनी पारी के पहले हिस्से में कोहली संघर्ष करते दिखे और सिर्फ 20 गेंदों पर 20 रन ही बना पाए लेकिन इसके बाद मौजूदा समय के महान बल्लेबाजों में शुमार कोहली ने अगली 30 गेंदों पर 74 रन बटोरे और विंडीज गेंदबाजों को सीमारेखा के पार भेजते रहे।

राहुल ने चहल की टांग खींची: पहले टी-20 के बाद युजवेंद्रा सिंह चहल ने राहुल से पूछा कि अब आप 1000 रन बना चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि आप टी-20 में मुझसे कितने रन आगे हैं।

राहुल ने मजाकिया जवाब देते हुए कहा कि मैं आपसे 999 रन आगे हूं। मैच के बारे में राहुल ने कहा कि हमने पहली पारी में देखा कि जब बल्लेबाज विकेट पर सेट हो रहे थे तो रन आसानी से बन रहे थे। विकेट थोड़ी अजीब थी, यह फ्लैट नहीं थी लेकिन दोनों टीमें 200 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहीं इसलिए विकेट के बारे में शिकायत नहीं कर सकते। दूसरे ओवर में मुझे दो-तीन बाउंड्री मिलीं, लेकिन दुर्भाग्यवश रोहित जल्दी आउट हो गए।

कतर ने 2022 फीफा विश्व कप स्टेडियम के उद्घाटन को टाला

दोहा, रायटर : कतर ने 2022 में होने वाले फीफा विश्व कप के आयोजन में इस्तेमाल वाले स्टेडियम के उद्घाटन को अगले साल के लिए टाल दिया है। फीफा ने शनिवार को बताया कि एजुकेशन सिटी स्टेडियम का अनावरण इस साल 18 दिसंबर को क्लब विश्व कप के सेमीफाइनल मैच के दौरान होना था।

स्टेडियम को स्थानीय अधिकारियों से प्रमाणपत्र मिलने में हो रही देरी के कारण क्लब विश्व कप के इस मुकाबले को खलीफा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। एजुकेशन सिटी का अनावरण अब 2020 में होगा, लेकिन फीफा ने इसके लिए कोई तारीख की घोषणा नहीं की है।

फीफा ने कहा, 'एजुकेशन सिटी स्टेडियम का निर्माण पूरा हो चुका है और यह स्थल अब परिचालन में है। ऐसे में स्टेडियम फीफा क्लब विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल से पहले आवश्यक परीक्षण मुकाबलों की मेजबानी करने में असमर्थ था।'

9 बल्लेबाज शून्य पर आउट, टीम आठ रन पर ढेर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : किसी भी अंतरराष्ट्रीय मैच में ऐसा आश्चर्य ही होगा कि टीम के 09 बल्लेबाज कोई रन ही नहीं बना पाएं, लेकिन ऐसा शनिवार को हुआ। हैरान होने की बात ही है कि मालदीव महिला क्रिकेट टीम के 09 बल्लेबाज कोई रन बनाए ही पवेलियन लौट गए। टीम की सलामी बल्लेबाज ऐमा ने एक रन बनाया जबकि अतिरिक्त से सात रन मिले। एक बल्लेबाज नाबाद रहा।

दक्षिण एशियाई खेलों (सैग) की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मुकाबले में नेपाल के खिलाफ मालदीव की टीम 11.3 ओवर में आठ रन पर ऑलआउट हो गई। इसके पीछे एक बार फिर नेपाल की अंजलि चंद का ही हाथ रहा जिन्होंने चार ओवर में तीन मेडन और केवल एक रन देकर चार विकेट झटक लिए। नेपाल की महिला टीम ने सात गेंदों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज काजल श्रेष्ठ ने नाबाद दो और रोमा थापा ने नाबाद पांच रन बनाए। अंजलि के करियर का यह दूसरा ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच रहा और उनके नाम अब दो मैचों में कुल 10 विकेट हो गए हैं और उन्होंने सिर्फ एक रन दिया है। इससे पहले 24 साल की अंजलि ने सोमवार को इतिहास रचा था जब इसी टूर्नामेंट में मालदीव के खिलाफ बिना कोई रन दिए छह विकेट झटके थे।

अंजलि के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (पुरुष और महिला) का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी दर्ज है। उनसे पहले मालदीव की मास एलिसा ने चीन के खिलाफ इसी साल तीन रन देकर छह विकेट झटके थे। पुरुष क्रिकेट में भारत के दीपक चाहर के नाम सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रिकॉर्ड है जिन्होंने इसी साल बांग्लादेश के खिलाफ सात रन देकर छह विकेट लिए थे।

दक्षिण एशियाई खेल

- नेपाल की महिला टीम के खिलाफ मालदीव का फिर से खराब प्रदर्शन
- सलामी बल्लेबाज ने बनाया एक रन, सात रन अतिरिक्त से मिले

08 रन टी-20 अंतरराष्ट्रीय में किसी भी टीम का दूसरा सबसे कम स्कोर है। इससे पहले माली की महिला टीम सिर्फ छह रन के कुल योग पर इस साल रवांदा के खिलाफ ढेर हो गई थी

04 बल्लेबाजों को नेपाल की अंजलि चंद ने पवेलियन भेजा। उन्होंने सिर्फ एक रन खर्च किया। अंजलि ने अपने पहले मैच में इसी टीम के खिलाफ बिना रन दिए छह विकेट लिए थे

06 विकेट सात रन पर टी-20 में भारत के दीपक चाहर ने बांग्लादेश के खिलाफ लिए थे जो पुरुष टी-20 में किसी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है

भारत के पदकों की संख्या 200 के पार

काठमांडू : तैराकों और पहलवानों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने शनिवार को दक्षिण एशियाई खेलों (सैग) में अपने कुल पदकों की संख्या 200 के पार पहुंचा दी जिसमें स्वर्ण पदकों का भी सैकड़ा पूरा किया। टूर्नामेंट के छठे दिन भारत ने 49 पदक जीते जिसमें 29 स्वर्ण शामिल हैं। भारत पदक तालिका में कुल 214 (110 स्वर्ण, 69 रजत, 35 कांस्य) पदकों के साथ शीर्ष पर है जबकि मेजबान नेपाल 142 (43 स्वर्ण, 34 रजत, 65 कांस्य) पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं, श्रीलंका (30 स्वर्ण, 57 रजत, 83 कांस्य) 170 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। भारतीय तैराकों ने शनिवार को सात स्वर्ण, एक रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं, भारतीय पहलवानों ने शनिवार को चार स्वर्ण पदक जीते जबकि भारोत्तोलकों ने भी दो स्वर्ण भारत की झोली में डाले। हालांकि भारत को ट्रैक एवं फील्ड के अंतिम दिन कोई स्वर्ण पदक हासिल नहीं हुआ, लेकिन आठ पदक फिर भी जीत लिए।

एनबीए ड्राफ्ट में शामिल हो चुके सतनाम डोप टेस्ट में फेल

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : अमेरिका की मशहूर बास्केटबॉल लीग एनबीए के ड्राफ्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय सतनाम सिंह भामरा पिछले महीने डोपिंग परीक्षण में विफल रहे जिसके बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने उन्हें अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया।

लुधियाना के 23 साल के इस खिलाड़ी को 2015 में एनबीए ड्राफ्ट में चुना गया था। वह दक्षिण एशियाई खेलों (सैग) की तैयारियों के लिए लगाए गए शिविर के दौरान नाडा द्वारा बेंगलुरु में टूर्नामेंट के बाहर आयोजित हुए परीक्षण में विफल रहे। उन्हें 19 नवंबर को अस्थाई रूप से निलंबित किया गया था।

सतनाम सिंह, फाइल फोटो ● ट्विटर

सतनाम ने व्यक्तिगत कारणों से एक दिसंबर से शुरू हुए 13वें सैग से हटने का फैसला किया था। सात फुट दो इंच का यह खिलाड़ी सैग के लिए बेंगलुरु के साई सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा था। सतनाम के मूत्र के ए नमूने में पाए गए प्रतिबंधित पदार्थ का पता नहीं चला है। नियमों के अनुसार, एक एथलीट के पास ए नमूने का नोटिस मिलने के सात दिन के अंदर बी नमूने की जांच कराने का अधिकार है। अगर बी नमूना भी पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके मामले की सुनवाई नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल द्वारा होती है जो फैसला करता है कि सजा दी जाए या नहीं। अगर सतनाम को डोपिंग का दोषी पाया जाता है तो उन पर पहली बार डोपिंग में सकारात्मक पाए जाने के लिए अधिकतम चार साल का प्रतिबंध लग सकता है। हालांकि अभी पता नहीं चला है कि सतनाम ने बी नमूने की जांच का अनुरोध किया है या नहीं। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ (बीएफआइ) के महासचिव चंदर मुखी शर्मा ने कहा कि उन्हें सतनाम के डोपिंग मुद्दे की जानकारी नहीं है क्योंकि वह शहर से बाहर हैं। सतनाम ने हमें पत्र में लिखकर कहा था कि वह व्यक्तिगत कारणों के चलते सैग टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएगा। वह सितंबर 2018 में कनाडा की एनबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय बने थे। उनका इस लीग के लिए सेंट जोंस की टीम से करार हुआ था।

शर्मनाक

- पिछले महीने हुए डोपिंग परीक्षण में लिया गया नमूना फेल
- दोषी पाए जाने पर सतनाम पर लग सकता है चार साल का प्रतिबंध

सतनाम सिंह का करियर

10 दिसंबर 1995 को बरनाला में जन्मे सतनाम सिंह भामरा की 10 साल ही उम्र में लंबाई पांच फुट से ज्यादा हो गई तो उनके पिता ने बास्केटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद 12 साल की उम्र में उन्होंने पहला मैच खेला। पहले लुधियाना और उसके बाद पंजाब टीम के लिए खेल चुके हैं। सतनाम चार साल पहले स्कॉलरशिप मिलने के बाद अमेरिका चले गए थे। लीग मैचों में डलास मेवरिक्स और एनबीएल (नेशनल बास्केटबॉल लीग) ऑफ कनाडा में सेंट जोंस की तरफ से भी खेल चुके हैं। 2015 में उनका चयन एनबीए के ड्राफ्ट में हुआ।

सतनाम सिंह ने अनुशासनात्मक पैनल के सामने सुनवाई का किया अनुरोध

जेएनएन, बरनाला: भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा ने कहा कि वह इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहते। उनके मैनेजर ने सतनाम सिंह के हवाले से बताया कि नाडा से 11 नवंबर को डोप टेस्ट में फेल होने का नोटिस मिला था। उन्होंने इन आरोपों को विवादित बताते हुए नाडा से अपील की है कि मामले की सुनवाई डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल (एडीडीपी) में की जाए।

सतनाम ने मीडिया में चल रही उन खबरों को भ्रमित करने वाला बताया जिसमें कहा जा रहा है कि नाडा ने उनको अस्थाई तौर पर निलंबित कर दिया है और इसे सतनाम ने स्वीकार भी कर लिया। नाडा के सामने विवादास्पद प्रक्रिया को संभालने का जिम्मा क्रीड़ा लीगल (कानूनी प्रतिनिधि) को सौंपा है। उम्मीद जताई की एडीडीपी 90 दिन में इस मामले की सुनवाई कर फैसला सुनाएगा। सतनाम ने कहा कि पूरा विश्वास है कि पाक साफ होकर निकलूंगा। जैसा अब तक करियर रहा है, वैसा ही आगे रहेगा।

पिता ने कहा, डोप टेस्ट की बात मान ही नहीं सकता : पिता बलबीर सिंह ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। पहले भी उसने देश का नाम रोशन किया है और अब भी करेगा। वह इस बात को मान ही नहीं सकते कि सतनाम किसी तरह का ड्रग या दवा लेता है।

डोप टेस्ट में फेल पंजाब के खिलाड़ी: फरवरी 2018 में जालंधर के गांव चक शुकरा के रहने वाले भाला फेंक खिलाड़ी देविंदर सिंह कंग डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। इस पर उन्हें विश्व एथलेटिक्स की संचालन संस्था ने अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया था। 2017 में गोला फेंक खिलाड़ी मनप्रीत कौर डोप टेस्ट में फेल हुई थी।